हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 07 मार्च, 2022 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बज़े अपराह्न आरम्भ हुई।

तारांकित प्रश्न

07/03/2022/1400/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

प्रश्न काल आरम्भ

प्रश्न संख्याः 4849

श्रीमती रीता देवीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जवाब में लिखा है कि इस भवन का निर्माण कार्य इसी वर्ष आरम्भ कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इस भवन का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इन्दौरा में मिनी सचिवालय के भवन निर्माण कार्य में हुई देरी के कई कारण हैं। किसी भी भवन को बनाने के लिए जब तक उसके लिए जमीन का हस्तांतरण नहीं होता है तब तक उसकी आगे की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकती हैं। जमींन का हस्तांतरण होने के पश्चात् उसका केस चीफ आर्किटेक्चर को भेजा जाता है। उसके बाद यह देखा जाता है कि इस भवन के लिए किन-किन विभागों की निविदाएं आईं हैं क्योंकि वह भवन कई विभागों के कार्यालयों के लिए बन रहा होता है। इन सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद उसका डिजाइन तैयार किया जाता है और डिजाइन तैयार होने के पश्चात यह केस विभाग के पास आता है। फिर विभाग उसकी डी0पी0आर0 बनाता है। आपके इस भवन की औपचारिकताएं लगभग पूर्ण हैं। **मुख्य मंत्री जी ने इस भवन के लिए धन का प्रावधान किया है और हम शीघ्र ही इस भवन के लिए टेंडरिंग का प्रोसैस शुरू करने जा रहे हैं।**

प्रश्न समाप्त

07/03/2022/1400/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

प्रश्न संख्या : 4850

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उससे एक गंभीर विषय सामने आता है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की 16954-08-00 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह 1954 के सैटलमेंट में अंकित है और यह सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में भी अंकित है लेकिन यह इलाका ऐसा था जहां सड़क इत्यादि की सुविधा नहीं थी और ये हिमाचल प्रदेश की जमीन पर कब्जा करते गए। वर्ष 2016-17 में यह विषय सरकार और विभाग के ध्यान में आया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जमीन पर लगभग 9.5 किलोमीटर सड़क भी बना ली है। It is the most beautiful tourism place और इसके बारे में कुछ दिनों पहले हमारे अधिकारियों की मीटिंग भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री और

एन0एस0 द्वारा जारी ...

07-03-2022/1405/NS/YK/1

प्रश्न संख्या : 4850 ..... क्रमागत

श्रीमती आशा कुमारी .....जारी

मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि अधिकारियों के स्तर पर बातचीत हो रही है लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि डिप्टी कमीश्नर इस मामले को नहीं सुलझा सकते। अपनी टेरीटरी को एज़ पर सेटलमैंट, एज पर सर्वे ऑफ इंडिया मैप और वहां सैंसस कोड है और यह कोड भी हिमाचल प्रदेश का है क्या आप इस मामले को इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग में उठाएंगे? मंत्री जी से हिमाचल प्रदेश के लोगों का संरक्षण भी चाहूंगी। वहां पर प्राईवेट लैंड में अगर कोई व्यक्ति कुछ बनाता है तो जम्मू-कश्मीर के सरकारी और दूसरे लोग आ करके उसको तोड़ रहे हैं। वे हमारे लोगों को अपनी जमीन में कोई फसल लगाने नहीं देते और न ही दुकानें बनाने देते हैं। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों और

लोगों को हिमाचल सरकार के जिला प्रशासन ने रोका तो उन्होंने वहां पर सड़क खोद दी और उसके ऊपर पेड़ गिरा दिया। इस तरह की हरकतें जम्मू-कश्मीर न करे और हमारी टेरीटरी हमें वापिस करे तथा हम उसको रिक्लेम करें क्या आप इस मामले को इंटर स्टेट काउंसिल में उठाएंगे?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका जी ने ठीक कहा है कि वर्ष 2016-17 में यह पता चला कि जो हमारी सीमा चम्बा जिले की जम्मू-कश्मीर के साथ लगती है वहां पर जम्मू-कश्मीर ने 9.50 किलोमीटर सड़क जिला चम्बा की धरती पर बना ली है। यह मामला वर्ष 2016-17 में ध्यान में आया और उसके बाद लगातार हमारा कोरेसपोडेंस जम्मू-कश्मीर की सरकार के साथ चलता रहा। हमने दिनांक 16.01.2017, 31.07.2018, 28.01.2021 और 07.10.2021 को ज्वाईंट डिमार्केशन करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को कहा। आप अंदाजा लगाएं कि वर्ष 2016-17 से ले करके वर्ष 2021 तक कितना पत्राचार हुआ। इतना पत्राचार करने के उपरांत इंटर स्टेट मोनिटरिंग डिसप्यूट को सैटल करने के लिए ज्वाईंट डिमार्केशन 10 दिसम्बर, 2021 को हुई। उस डिमार्केशन में जिला डोडा के डिप्टी कमिश्नर और जिला चम्बा के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे और राजस्व विभाग के अधिकारी भी वहां पर गए थे। डिमार्केशन होने के उपरांत वे वहां पर अपना कब्जा बता रहे थे और उनके पास इसका कोई रिकोर्ड नहीं था। उनके पास इसका कोई ततीमा या अन्य आवश्यक रिकोर्ड नहीं

07-03-2022/1405/NS/YK/2

था लेकिन हमारे पास यह सब रिकोर्ड में दर्ज़ है। अध्यक्ष महोदय, जिला चम्बा में रेग्युलर बंदोबस्त वर्ष 1951 से ले करके 1958 तक हुआ। हमारे पास सज़रा, किस्तवार, फील्ड बुक, मिस्सल हकीकत, हदवस्त नम्बर-138 कुल किता 22 और कुल एरिया 16954-08-00 बीघा में उन्होंने आगे बढ़ करके कब्जा किया हुआ था और मुहाल ठेकाधार पादरी पटवार सर्कल भांडल तहसील सलूणी जिला चम्बा में यह हिमाचल प्रदेश के कब्जे में पाया गया है। उन्होंने जहां पर ये 9.50 किलोमीटर सड़क बनाई वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया है और वहां पर पुलिस की पोस्ट स्थापित कर दी। वहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती है तो कुछ समय के लिए पुलिस वहां से चली जाती है। यह एक गंभीर विषय है। ऐसे विषयों पर पहले ही ध्यान देना चाहिए लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

07.03.2022/1410/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 4850 जारी

जल शक्ति मंत्री... जारी

हम इस मामले को गृह मंत्रालय के इंटर स्टेट नार्थ जोन कौंसिल में ले जाने की सोच रहे हैं । पूरे देश के जितने भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए अलग-से कानून बने हैं। हम इस मामले को नार्थ जोन कौंसिल में ले जाएंगे। इस तरह के विवाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी चल रहे हैं। जिला लाहौल और स्पिति के सरचु क्षेत्र में भी लद्दाख रीजन की ओर से ऐसे कब्ज़े हुए हैं। हम इस मसले को भी नार्थ जोन कौंसिल में ले गए हैं। हमारा परवाणू के पास भी हरियाणा राज्य से सीमा विवाद चला हुआ है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है और हम इस मसले को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की नॉर्थ जोन कौंसिल में उठाएंगे। हम इस मसले पर शीघ्र फैसला करवाएंगे ताकि हमारी धरती पर दूसरे प्रदेश के लोग कब्जा न कर सके।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी की नीयत पर कोई शक नहीं है। मैं वर्तमान उपायुक्त, चम्बा को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इस मामले को टेक-अप किया। लेकिन जब ज्वाइंट डिमार्केशन होती है और कोई प्रोपर्टी किसी के हक में पाई जाती है तो वहां हमें अपनी बुर्जियां लगानी चाहिए। जहां-जहां डिस्प्यूट नहीं है वहां तो कम-से-कम हमें अपनी बुर्जियां लगा देनी चाहिए। मैं मानती हूं कि जंगल के क्षेत्र में डिस्प्यूट है और इसके पेपर न हमारे पास है और न उनके पास। जहां हमारी पुलिस पोस्ट है उससे आगे 16,954 बीघा, यानी साढ़े नौ किलोमीटर, हमारा एरिया लगता है। यह क्षेत्र बहुत सुन्दर है और यहां हम अपनी बुर्जियां लगा सकते हैं। जहां-जहां हम बुर्जियां लगा सकते हैं वहां हमें बुर्जियां लगा देनी चाहिए। ज्वाइंट डिमार्केशन का मतलब क्या हुआ?

इसका मतलब हुआ कि दोनों राज्य सहमत हैं। वे भी ज्वाइंट डिमार्केशन के लिए सहमत थे। जब दोनों राज्य सहमत होते हैं तभी ज्वाइंट डिमार्केशन

07.03.2022/1410/RKS/AG-2

होती है। चम्बा जिला के उपायुक्त और उनके संबंधित जिला के उपायुक्त डिमार्केशन के समय वहां उपस्थित थे। जहां पुरानी जगह में बुर्जियां लगी थी लेकिन उन्हें जे.एंड के. वालों ने निकाल दिया था वहां तो कम-से-कम हमें बुर्जियों लगा देनी चाहिए। वहां पर उन्होंने टूरिज्म कॉम्पलैक्स खड़ा कर दिया है और आपको इस मामले को गृह मंत्रालय से टेक-अप करना पड़ेगा। लेकिन जो खाली भूमि है हम उस भूमि को तो कम-से-कम रिक्लेम कर सकते हैं।

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े विस्तार से प्रश्न का उत्तर दिया है। चम्बा जिला और उनके संबंधित जिला के उपायुक्तों के सामने यह डिमार्केशन हुई है। हिमाचल प्रदेश के पास इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है। उनके पास रिकॉर्ड है या नहीं यह अलग बात है। वे कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। हमने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार डिमार्केशन की है। हम सर्वे ऑफ इंडिया वालों से भी टेक-अप करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई झगड़े वाली बात हो। हमने उन्हें कहा है कि आपने जो स्ट्रक्चर स्थापित किया है उसे आप उखाड़ कर ले जाएं। जैसा आपने अपनी सीमा पर बुर्जियां लगाने का सुझाव दिया है, यह अच्छा सुझाव है और हम इस पर काम करेंगे।

प्रश्न संख्याः 4851

श्री रविन्द्र कुमार (जयसिंहपुर): उपस्थित नहीं

प्रश्न संख्या 4852,श्री बी.एस.द्वारा...जारी

07.03.2022/1415/बी.एस./ए0जी0/-1

प्रश्न संख्याः 4852

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वेटरिनरी फार्मासिट के प्रदेश में कितने संस्थान हैं और इनमें कुल कितनी सिट्स हैं? इस वक्त कितने वेटरिनरी फार्मासिस्ट अभी नौकरी के लिए कतार में लगे हैं? आपने 23 संस्थान दिए हैं, क्या आपके गृह जिला में किसी भी संस्थान की जरूरत नहीं थी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कुछ 26 वेटरिनरी संस्थान हैं और 23 संस्थानों के लिए लोगों ने अभी एप्लाई किया था और उन सभी को मापदंडों के अनुसार स्वीकृत भी किया है। इसके अलावा भी माननीय उच्च न्यायाल की रिकमेंडेशन पर कुछ संस्थान देने पड़े हैं। इनमें हमारे पास अब तक 464 पद खाली हैं और जो हमारे पास रजिट्र्ड हैं परंतु पेंडिंग हैं, वे कुल 663 हैं। हम जल्दी ही ये पोस्टें भर रहे हैं और अब तक जैसा आपने प्रश्न में पूछा है कि 23 संस्थानों में कितनी सीटें हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि 1645 सीटें प्रदान की गई है। जहां तक आपने जिला ऊना का प्रश्न किया है कि वहां पर संस्थान क्यों नहीं खुले, तो वहां पर अभी आवेदन आए हैं और हम यह भी देख रहे हैं कि जहां पर ज्यादा संस्थान खुल चुके हैं, वहां हम बंद भी करना चाहते हैं। हमने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो पूरा आकलंन करेगी कि हमें कितनी आवश्यकता है और कितनी सीटें हमें देनी है। अगर आवश्यकता हुई तो हम उसे रेशनलाइज भी करेंगे और सीटें कम भी करेंगे। लेकिन जहां पर नहीं हैं वहां हम संस्थान अवश्य देंगे। इसके साथ ही जहां जितनी आवश्यकता है वहां हमने उनरी सीटें दी हैं और आवश्यता पड़ी तो उसे रेशनेलाइज भी करेंगे।

प्रश्न समाप्त/

07.03.2022/1415/बी.एस./ए0जी0/-2

प्रश्न संख्याः 4853

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारा 66 के0वी0 सब-स्टेशन चौंपाल का कार्य बहुत जोरों पर चला है। मैं मुख्य मंत्री महोदय का चौपाल की जनता और अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं कि हमारा एफ0सी0ए0 केस भी इन्होंने क्लीयर करवाया है औरसाथ-ही-साथ 35 करोड़ रुपए के करीब इसकी कम्पलीशन के लिए इसी सरकार से प्राप्त हुआ है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस 66 के0वी0 बस-स्टेशन के कार्य को आप कब तक पूर्ण कर लेंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि इस सब-स्टेशन का कार्य पिछले लगभग 10 वर्षों से चला था क्योंकि कुछ निजी भूमि थी, जिसमें टावर लगने थे और कुछ फोरेस्ट एरिया था, जिसकी अनुमति नहीं मिली थी। वर्तमान समय के सरकार में इसकी अनुमति मिली है और हमने इसकी डी0पी0आर0 भी रिवाइज कर दी है। अब इस पर 35 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब खर्च होगें। हम इस सब-स्टेशन को 31 मार्च, 2022 तक पूरा करके जनता को समर्पित कर देंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसमें अभी दो-तीन टावर अभी खड़े होने हैं, जिनमें पहले भूमि विवाद था परंतु उसे अब समाप्त कर दिया गया है। वहां ठेकेदार कार्य को शुरू नहीं कर रहा है। वहां पहले 80-82 टावर खड़े कर दिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि आप अधिकारियों को आदेश दें कि वहां पर ठेकेदार कार्य आरंभ कर दें।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

07-03-2022/1420/ए.एस.-एन.जी. /1

प्रश्न संख्या - 4853.....जारी

श्री बलबीर सिंह वर्मा के पश्चात...

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो टावर थे और उनमें कुछ विवाद था। उस विवाद को अब निपटाया जा चुका है। अब उन टावरों के फाउंडेशन का काम चल रहा है। **मैंने पहले भी कहा है कि बहुत जल्दी उन्हें पूर्ण करके जनता को समर्पित कर देंगे।** मैं माननीय सदस्य जी को यह भी सूचना देना चाहता हूं कि आपके **चौपाल मण्डल में जितने भी लकड़ी के पोल हैं वे सभी मानसून से पहले बदल दिए जाएंगे।**

प्रश्न समाप्त/-

प्रश्न संख्या - 4569

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) : उपस्थित नहीं।

07-03-2022/1420/ए.एस.-एन.जी. /2

प्रश्न संख्या - 4854

श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल-कोटखाई): अध्यक्ष महोदय, कृषि व बागवानी क्षेत्र में आमतौर पर यह देखा गया है कि प्राकृतिक आपदा घटने के महिनों बाद नुकसान का आंकलन होता है। उसके बाद राहत मिलेगी, यह भी सुनिश्चित नहीं होता। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष अप्रैल माह में बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि व बरसात के कारण लगभग 284 करोड़ रुपये की क्षति हुई और उसके आंकलन के लिए केन्द्र की टीम नवम्बर माह में आती है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में बागवानी व कृषि के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा का आंकलन एक निश्चित समयावधि में होगा? इसके अतिरिक्त किसानों-बागवानों को समय पर राहत मिल सके? दूसरा, इसके लिए जो रिलीफ नियमावली बनी हैं उसमें जहां बाकी घटकों में समय-समय पर संशोधन व बढ़ोतरी हुई है लेकिन मैं पिछले दो

दशकों से देख रहा हूं कि किसान-बागवानों को अधिकतम राहत केवल 7,000 रुपये ही मिलती है। क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल व मई माह में शिमला जिला में भारी बर्फबारी, बरसात व ओलावृष्टि हुई। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष अप्रैल-मई माह में बर्फबारी, बरसात व ओलावृष्टि केवल शिमला जिला में ही नहीं बल्की सिरमौर के ऊपरी भाग में, शिमला जिला के अनेक क्षेत्रों में, किन्नौर जिला, मण्डी जिला के ऊपरी भाग और चम्बा जिला में भी हुई है। इस बेमौसमी बर्फबारी की वजह से किसानों-बागवानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि इससे केवल बागवानों का नुकसान हुआ बल्की इससे किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहता हूं कि अप्रैल-2021 में बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से लगभग 211.59 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है।

07-03-2022/1420/ए.एस.-एन.जी. /3

जिसमें से कृषि क्षेत्र का 72.80 करोड़ रुपये और बागवानी क्षेत्र का 138.79 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है। सरकार ने इसके लिए एक विभागीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने हर क्षेत्र में जा कर नुकसान का जायज़ा लिया था जिसके बाद यह आंकड़ा हमारे सामने आया। इस सारे मामले की रिपोर्ट को सरकार द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्रालय को अगस्त-2021 में भेजा गया था। उसके उपरांत श्री प्रमोद कुमार महेन्द्रा, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय केन्द्रीय दल ने दिनांक 14-11-2021 से 17-11-2021 तक प्रदेश का दौरा किया था। उनका दौरा जिला शिमला, सोलन, सिरमौर आदि में हुआ। अप्रैल-मई में जो बर्फबारी, बरसात व ओलावृष्टि हुई उसके नुकसान का आंकलन लगभग 211 करोड़ रुपये किया गया है और यह सारा मामला हमारी सरकार की ओर से केन्द्र को चला गया है। अब उसके लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है। आपको पता है कि हमारी

श्री जे.एस. द्वारा जारी.........

07.02.2022/1425/JS/AS/1

प्रश्न संख्या 4854ः----जारी----

जल शक्ति मंत्रीः----जारी----

उस रिलीफ मैनुअल में क्या-क्या दिखाया गया है, आप उसके बारे में जानना चाहे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके उपरान्त फिर जब मॉनसून सीज़न आया, उसमें भी प्रदेश का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसमें लगभग 1151.70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हमने यह सारी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी। जैसे ही भारत सरकार से कोई राहत आएगी, उस राहत को हम उस आदमी तक पहुंचाएंगे जिसका इसमें नुकसान हुआ है। वर्ष 2021 के दौरान मॉनसून के नुकसान का निरीक्षण करने के लिए 24.11.2021 से 27.11.2021 तक एक सात सदस्यीय दल केन्द्र से आया था। उन्होंने भी देखा कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में ही इस बार ऐसी अनहोनी बारिश हुई कि समुद्री तूफान आए और बहुत सारी लहरें वहां पर उठी जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। **जैसे ही हमें भारत सरकार से राशि मिलेगी उसमें जो भी लाभार्थी होंगे, उन तक उस राशि को तुरन्त पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।**

अध्यक्षः राहित ठाकुर जी, बड़े विस्तार से उत्तर आ गया है।

श्री रोहित ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, हम आशा रखते हैं कि दूसरा इंजन जल्दी चलेगा। इसमें जो अधिकतम सीमा 7000 रुपये की रखी गई है, क्या इसको बढ़ाने का सरकार विचार रखती है क्योंकि बाकी जो भी आपके घटक थे उनमें बढ़ौत्तरी हुई है सिवाय इस घटक के तो मैं यह जानना चाहता हूं?

जल शक्ति मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को नॉर्म्ज़ बढ़ाने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी भेज रखा है। हमने तो चाहा है कि वर्तमान

के नॉर्म्ज़ को डबल कर दिया जाए ताकि किसानों या बागवानों का कोई भी नुकसान होता है तो उनको उचित राहत मिल सके।

प्रश्न समाप्त

07.02.2022/1425/JS/AS/2

प्रश्न संख्याः 4855

श्री प्रकाश राणाः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 4856

श्री परमजीत सिंहः कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

07.02.2022/1425/JS/AS/3

प्रश्न संख्याः 4857

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि असल में जो वर्ल्ड बैंक का यह प्रोजैक्ट था, असल में क्लस्टर बनाने का उसका उद्देश्य यह था कि अकेला किसान पानी नहीं पहुंचा सकता है इसलिए क्लस्टर के माध्यम से वह काम करें। लेकिन जिस समय यह रिपोर्ट बनी वह हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को मध्यनज़र नहीं रखते हुए नहीं बनी। जो क्लस्टर का न्यूनतम एरिया था, जिसमें कल्टिवेशन होनी थी, वह लगभग 550 से 700 बीघा तक रखा गया। यानि जब हम उस जमीन को हैक्टेयर में तबदील करेंगे तो वह इतना एरिया हो जाएगा। यह तो उसमें आया है लेकिन क्लीयर नहीं है। अगर कम एरिया है तो उसमें संशोधित हो करके अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी?

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

07.03.2022/1430/SS-DC/1

प्रश्न संख्या : 4857 क्रमागत

श्री राकेश सिंघा क्रमागत :

यह एक बात है। यह ठीक है कि सोर्स ऑफ वाटर एक ही होगा। जो आप कह रहे हैं कि औरों के अधिकार नहीं होने चाहिएं, नेचुरल सोर्स वहीं से होगा जहां पर औरों के अधिकार नहीं हैं।

दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यह मानसिकता थी कि जो हम रूट स्टॉक पर कल्टीवेशन करेंगे तो यह बड़ा भारी पानी मांगता है। अभी भी यही मानसिकता है। मैं गारंटी देता हूं और सिद्ध करूंगा कि जो छत का पानी है उससे जितने लोगों के पास रकबे हैं, कितने रकबे हैं? ढाई बीघे, तीन बीघे, चार-पांच बीघे या ज्यादा-से-ज्यादा 20 बीघे चला जाएगा ...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न करें।

श्री राकेश सिंघा : सर, मैं प्रश्न को समझाने के लिए यह सब कह रहा हूं। तो छत के पानी से क्लस्टर को अवॉयड करते हुए क्या आप अनुमति देंगे? क्योंकि छत के पानी से क्लस्टर नहीं होगा।

मैं तीसरी बात कह दूं कि बहुत-सा रूट स्टॉक एम-9 को छोड़कर ज्यादा पानी नहीं मांगता। यह सिम्पल लॉजिक है कि अगर पेड़ 30 फुट होगा तो उसको ज्यादा पानी चाहिए। पेड़ छोटा होगा तो उसको पानी कम चाहिए। रूट स्टॉक का एडवांटेज है कि अगर एक कोली पानी डालोगे तो उसे 100 परसैंट लेगा। सीडलिंग में आप ड्रम डालोगे तो एक बाल्टी लेगा। That is the advantage. इसलिए यह जो मानसिकता है कि नहीं लगेगा या नहीं होगा, सही नहीं है। इसलिए क्या आप अनुमति देंगे कि छत के पानी को टैप करके कोई

उसमें अपने आपको शामिल करना चाहता है तो वह 20 या 30 हजार लीटर का टैंक बनाए? ये तीन बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा।

07.03.2022/1430/SS-DC/2

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक बहुआयामी विश्व बैंक की योजना है जो हिमाचल प्रदेश के लगभग साढ़े 5-6 हजार फुट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए भारत सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 2016-17 में प्राप्त हुई है। इसकी सारी प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई गई और उसके मुताबिक फिर विश्व बैंक की गाइडलाइन्ज़ के अनुसार प्रोजैक्ट आगे बढ़ा। उसमें माननीय सदस्य सिंचाई की व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनी है उसमें विलेज वाटर यूजर एसोसियेशन बनाई गई है और उनको ही सारा अधिकृत कर दिया गया है। उनको कुछ टेक्निकल लोग दिए गए हैं ताकि वे मेक्सिमम ऐसी योजनाएं बनाएं जिन पर प्रति हैक्टेयर दो लाख रुपया खर्च हो। जो उठाऊ सिंचाई योजनाएं हैं उसको उन्होंने अधिकतर कोशिश की थी कि वे न बनें। जैसे सिंघा जी कह रहे हैं, इनका कहना ठीक है। हमारी एक ऐसी कंवैंशन बन चुकी है कि रूट स्टॉक बहुत ज्यादा पानी चाहता है। अब जितना बड़ा शरीर होगा उतनी ज्यादा उसको हर चीज़ की आवश्यकता होगी। उसमें खाद्य सामग्री की उतनी आवश्यकता होगी, पीने के पानी की भी उतनी आवश्यकता होगी। ठीक है, आप भी बागवान हैं और मैं तो छोटा-मोटा बागवान हूं। मैं भी ऐसा महसूस करता हूं कि जितना पेड़ छोटा होगा उसको उतने कम पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी मैं सिंघा जी को कहना चाहूंगा कि रूट स्टॉक्स को अपने आधार के मुताबिक ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें जो फ्रूटिंग होती है वह ज्यादा होती है। लकड़ी पानी कम लेती है। जब पौधा फैलेगा, टहनियां होंगी, पत्ते होंगे तो ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी जितनी ज्यादा आवश्यकता फ्रूट के लिए होती है।

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2020/1435/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या 4857 जारी....

जल शक्ति मंत्री जारी--

फ्रूट का साइज़ तभी बढ़ेगा जब उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी मिलेगा। 281 क्लस्टर्ज़ हमारे चिन्हित हुए हैं। उनमें से अधिकतर में सिंचाई का काम कुछ जगह पूर्ण हो चुका है, कुछ जगह चला हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह एक बहुत अच्छा प्रोजैक्ट है। ठीक है, शुरूआत में इसमें कुछ दिक्कतें आई थीं लेकिन अब विश्व बैंक ने भी उद्यान विभाग और इसमें जो अधिकारी/कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी पीठ थपथपाई है कि आपने हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम किया है। पीछे कोविड काल में जो चीज़ें यहां आनी चाहिए थीं, उनमें आने में देरी हो रही थी। मैं हाउस के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के अंदर हमारा जिला सिरमौर, किन्नौर, शिमला, मण्डी जिला का हिस्सा, कुल्लू, लाहौल-स्पिति, चम्बा, सोलन और कांगड़ा का हिस्सा है। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसके अच्छे परिणाम आए और आ रहे हैं। ...(व्यवधान)... पानी की सप्लीमेंट्री क्योंकि नेगी जी करने वाले हैं तो उसमें आगे बढ़कर मैं और बात करुंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह वर्ल्ड बैंक पोषित परियोजना है। इसकी गाइडलाइन वर्ल्ड बैंक के माध्यम से अप्रूव हो कर आई है। हम उससे हटकर काम नहीं कर सकते। मैंने जो गाइडलाइन को स्टडी किया है, उसमें रूफ हार्वेस्टिंग शामिल नहीं है।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो आपका क्लस्टर सिस्टम है, इन्होंने बहुत विस्तार से वह बात बताई जिसकी जानकारी हमें नहीं चाहिए थी। असली बात तो बताई ही नहीं। किस कंसल्टैंट ने क्लस्टर सिस्टम को उत्पन्न किया है? 50 या 60 हैक्टेयर जगह अगर खाली हो, तब तो क्लस्टर सिस्टम ठीक है। मेरे किन्नौर में हर गांव में आपके विभाग द्वारा फ्लो इरिगेशन की सुविधा है।

07.03.2020/1435/केएस/डीसी/2

वहां भी आप इसी स्कीम को ओवरलैप कर रहे हैं। जो इन्होंने 281 स्कीमें बताई उसमें क्या हो रहा है, उसमें कोई 2000 लीटर का, कोई 7000 लीटर का टैंक बन रहा है । उस टैंक से क्या आप बागवानी में एक क्रांति लाएंगे? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो क्लस्टर सिस्टम है, it is a total failure. क्या आप दोबारा से रिव्यू करेंगे कि जिस इलाके में जो ज़रूरत है और जो कंसल्टैंट ने दिल्ली या वाशिंगटन में बैठकर यह सिस्टम बनाया है, उसको छोड़कर क्या आप इसको रीविज़िट करेंगे otherwise it is going to be a total failure. दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक चौरा नामक गांव हैं जहां आई.पी.एच. में विधायक प्राथमिकता में पौने दो करोड़ रुपये की पानी की स्कीम है। वहां होर्टिकल्चर वाले फिर घुस गए। 67 लाख रुपये उसमें डालना चाह रहे हैं। इनके पास कोई काम ही नहीं है, they just want to build tanks and purchase HTP pipes. The entire money is going down the drains. मंत्री जी, आप चिंता करेंगे? क्या दोबारा से इस बारे में आप कोई सोच रखेंगे?

जल शक्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं नेगी जी को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 में यह प्राजैक्ट रिपोर्ट आपके कालखंड में ही बनी थी। जब वह प्रोजैक्ट रिपोर्ट बन कर विश्व बैंक को गई फिर उन्होंने इसके लिए जो गाइडलाइन बनाई, मैं भी आपसे सहमत हूं कि जब भी कोई काम किया जाता है उसमें कई जगह कुछ कमियां रह जाती हैं। अब मान लो जो यह बिल्डिंग बनी है, जब इसकी फाउंडेशन बनी थी, अगर इसमें कोई कमी रह गई हो,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

07.03.2022/1440/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 4857----क्रमागत

जल शक्ति मंत्री----जारी

अगर नींव डालते ही किसी प्रकार के सरिया या सीमेंट आदि की कमी रह जाए तो उसके उतने लाभप्रद परिणाम सामने नहीं आते। माननीय सदस्य, मैं भी आपकी चिंता के साथ हूं। अब तो यह प्रोजैक्ट एक-दो वर्षों के लिए बाकी बचा है। अब इस स्टेज पर आकर मैं इस सदन के अंदर यह कह दूं कि नहीं, हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। अब तो रिव्यू करने का समय निकल गया है। अब तो इसमें केवल किसी प्रकार की कमी को ठीक करने का कार्य ही किया जा सकता है और वह भी सबके सहयोग से हो सकता है। यह केवलमात्र ऑफिसर्ज की जिम्मेवारी नहीं है, उसमें बागवान और विलेज वॉटर यूजर्स एसोसिएशन भी शामिल हैं। विलेज वॉटर यूजर्स एसोसिएशन के माध्यम से जो टैंक बन रहे हैं उसमें लोगों को भी देखना चाहिए कि उनमें ऐसी कोई कमी न रह जाए कि कल को उनसे पानी बाहर निकलता रहे। यह योजना ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हैं तथा विशेषकर के हमारे लाहौल-स्पिति, किन्नौर, शिमला के ऊपरी एरिया में जहां बर्फ बहुत पड़ती है; वहां सीमेंट को पकड़ के लिए काफी समय लगता है। इसलिए अब जैसे है **अगर उसी में सुधार किया जाए तो हम उस प्रकार से सुधार करने का आश्वासन देते हैं।**

समाप्त

07.03.2022/1440/av/hk/2

प्रश्न संख्या : 4858

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर अगला प्रश्न करेंगे।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 4859

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, सॉइल कंज़र्वेशन डिपार्टमैंट के अंतर्गत चैक डैम इत्यादि कई प्रकार के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में ब्रैस्ट वॉल्ज की बहुत

जरूरत है और जितनी भी सड़कें बन रही हैं चाहे वह प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नाबार्ड या लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही हैं; ये विभाग ब्रैस्ट वॉल लगाते भी हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सॉइल कंज़र्वेशन डिपार्टमैंट के तहत भी ब्रैस्ट वॉल लगाने हेतु कोई प्रोविजन करेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिछले तीन वर्षों की सूचना मांगी थी और इनके रामपुर में बहुत अच्छे काम हुए हैं तथा उनकी प्रोग्रैस रिपोर्ट भी काफी अच्छी है। लेकिन आपने जो ब्रैस्ट वॉल के बारे में पूछा है तो यह जहां पर हमारी उपजाऊ जमीन है और वह बह रही है; तो केवल उसके लिए ही ब्रैस्ट वॉल का प्रावधान है। परंतु आबादियों के लिए इसमें प्रावधान नहीं है क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य कृषि उपजाऊ भूमि के रख-रखाव से है।

समाप्त

07.03.2022/1440/av/hk/3

प्रश्न संख्या : 4860

अध्यक्ष : अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर करेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखी गई सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में विभिन्न शिक्षा संस्थानों में लगभग 122 लाइब्रेरियन की पोस्ट्स सैंक्शन्ड हैं जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत खाली हैं। प्रश्न के 'बी' पार्ट में मंत्री जी का जवाब है कि इनकी भर्ती का मामला अण्डर कंसिड्रेशन है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने लाइब्रेरियन के कोर्सिज किए हैं उनमें से बहुत से लोग तो ओवर एज हो गए हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पहले इनकी भर्ती किस वर्ष में हुई थी और क्या अभी आप इनकी भर्ती करने जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि मुझे यह लगता है कि इनकी भर्ती शायद 15-20 वर्ष पूर्व हुई थी।

टी सी द्वारा जारी

07/03/2022/1445/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

प्रश्न संख्याः 4860.... क्रमागत्

श्री नरेन्द्र ठाकुर ... जारी

उनके बारे में भी सरकार विचार करें क्योंकि उनकी आयु 45-50 साल के होने वाली हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इन पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को इनका लाभ मिल सकें।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि रिक्तियां बहुत अधिक हैं। कुल 122 पद सैंक्शन्ड हैं जिनमें से अभी 59 पद रिक्त हैं। यह मामला अभी शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के पास विचाराधीन है और हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही इन पदों को भरा जाए। इससे पहले असिस्टेंट लाइब्रेरियन के कैडर को डाईंग कैडर घोषित किया गया था लेकिन उसके बाद यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के आदेशानुसार इनको यू0जी0सी0 का स्केल दिया गया। कार्य बाधित न हो, इसलिए इन लोगों को भी कॉलेजों में नियुक्त किया गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि जे0ओ0ए0 के लगभग 700 पदों को भी शीघ्र ही भरा जाएगा। **इनके आर0एण्ड पी रुल्ज बन रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को आश्वास्त करना चाहूंगा कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।**

07/03/2022/1445/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

प्रश्न संख्याः 4861

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय सदस्य को भेजा गया है, यह पहले चला गया था। विभाग को दिनांक 28 फरवरी, 2022 को सूचना प्राप्त हुई है कि इससके लिए भूमि स्थानांतरण की प्रकिया पूरी हो गई है। विभाग ने लोक निर्माण विभाग के चीफ आर्किटेक्चर को इसका नक्शा व एस्टिमेट इत्यादि तैयार करके शिक्षा विभाग को प्रेषित करने लिए कहा है। जैसे ही यह प्रकिया पूरी हो जाएगी, हम इसकी आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे।

प्रश्न समाप्त

07/03/2022/1445/टी0सी0वी0/ए0जी0/3

प्रश्न संख्याः 4862

श्री जिया लाल : अध्यक्ष महोदय, जितनी भी भेड़-बकरियां गाड़ी के नीचे आती हैं उनको मु0 3000 रुपये मुआवजे के रूप में प्रति भेड़ या बकरी दिये जाते हैं लेकिन यह मुआवजा 30 या 31 भेड़-बकरियों के लिए ही दिया जाता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जितनी भी भेड़ और बकरियां गाड़ी के नीचे आती हैं, उन सब के लिए मुआवजा दिया जाए और यह मुआवजे की राशि भी बढ़ाई जाए। क्योंकि जिसकी गाड़ी के नीचे भेड़ बकरियां गाड़ियों के नीचे आती हैं, उनके खिलाफ न तो कोई केस दर्ज़ किया जाता है और न ही कोई कार्रवाई होती है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने एस0पी0 (ऊना) से बात की तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मालिक कहता है कि मैं मुआवजा नहीं दूंगा। इस तरह से तो सारी भेड़-बकरियां गाड़ी के नीचे आकर खत्म हो जाएंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, निश्चिततौर पर यह एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा ही खुले आसमान के नीचे रहता है। ये घरों से निकल जाते हैं और इनका जीवन भेड़-बकरियों के साथ ही गुजर जाता है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

07-03-2022/1450/NS/YK/1

प्रश्न संख्या : 4862 ..... क्रमागत

जल शक्ति मंत्री .....जारी

माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वह बिल्कुल जायज है। ट्रक या अन्य वाहन अगर किसी जानवर को कुचल दे और उसके ऊपर कार्रवाई न हो तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। निश्चित तौर पर यह एक अपराध है। अगर ऐसा होता है तो चालक के

खिलाफ़ नियमों के अंतर्गत कार्रवाई होती है। दूसरा, माननीय सदस्य ने कहा है कि मैक्सिमम यूनिट 30 लिए गए हैं। मैन्युअल में ही सारा कुछ दर्शाया गया है। आपने सुझाव दिया है कि इसमें 30 की कैप लगी है और इसको बढ़ा दिया जाए। मैंने यहां पर पहले भी कहा है जब माननीय रोहित ठाकुर जी का प्रश्न आया था कि हमने रिलीफ़ मैन्युअल में बढ़ौतरी करने के लिए भारत सरकार को लिखा है। भेड़-बकरियों को रिलीफ़ मैन्युअल के हिसाब से 3000 रुपये दिए जाते हैं और हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2015 के बाद इसके लिए नॉर्म्ज़ नहीं बनाए गए हैं। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा और भारत सरकार के गृह मंत्रालय में व्यक्तिगत तौर पर जाकर मिलूंगा ताकि नॉर्म्ज़ में संशोधन हो सके। पूरे देश के लिए इन नॉर्म्ज़ का संशोधन होगा न कि हिमाचल प्रदेश के लिए होगा। माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न पूछा था तो उसके मुताबिक मालिकों का इन भेड़-बकरियों के लिए जितना मुआवजा बनता था वह सारा मुआवजा दे दिया गया है। हम भेड़-बकरियों के मालिकों की संभव मदद करने का प्रयास करेंगे।

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, जिया लाल जी ने बताया कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भेड़-बकरियों को चराने ले जाते हैं तो वे चोरी हो जाती हैं। चोरी हुई भेड़-बकरियां मिल ही नहीं पाती हैं और न ही उनका कोई मुआवजा मिलता है। मैं, मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसा कोई विचार रखती है कि इनको भी किसी तरह का मुआवजा मिले?

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब भेड़-बकरियां चोरी होती हैं तो उसकी एफ0आई0आर0 होती है और उसकी जांच होती है तथा कार्रवाई की जाती है। जहां तक मुआवजे की बात है तो जो फिजिकली है केवल उसी का मुआवजा दिया जाता है।

07-03-2022/1450/NS/YK/2

प्रश्न संख्या : 4863

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि रोहड़ू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एस0सी0डी0पी0 के तहत वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं, सड़कें व भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है; स्थिति का ब्योरा दें। मेरा, मंत्री महोदया से

अनुरोध है कि जो सूचना आपको दी गई है वह प्रोपर नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि समोली में पब्बर नदी पर डबल लेन ब्रिज बन रहा है और इसका 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने दो साल पहले इस पुल का उद्घाटन कर दिया है। यह हमारी सरकार के समय में बनना शुरू हुआ था और 85 प्रतिशत कार्य

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

07.03.2022/1455/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः 4863... जारी

श्री मोहन लाल ब्राक्टा...जारी

अगर इसके अलावा कोई और दूसरा पुल होगा तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आपने 57 सड़कों की बात की है और कहा है कि इन सड़कों में से किसी सड़क का 40 प्रतिशत, किसी का 35 प्रतिशत, किसी का 15 प्रतिशत, किसी का 10 प्रतिशत और किसी का 5 प्रतिशत कार्य हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि इन सड़कों का निर्माण कार्य धीमी गति से चला हुआ है? क्या आपके पास इन सड़कों का कार्य पूर्ण करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है? इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के अंतर्गत डोडरा-क्वार में रेंज कार्यालय का निर्माण, रोहडू में वन मंडल अधिकारी के कार्यालय का निर्माण कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शीलघाट के भवन का निर्माण कार्य व अन्य स्कूल भवनों का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है लेकिन मुझे इनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में गत चार वर्षों में 57 सड़क योजनाओं, तीन नये भवन निर्माण कार्य और अन्य 27 योजनाओं में काम चला हुआ है। वर्ष 2018-19 में 30 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 16 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 37 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 में 28 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एस.सी. कम्पोनेंट से दी

गई है। मैं सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों को बराबर धनराशि आंबटित करने की कोशिश करती हूं। आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिए गत चार वर्षों में 112 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। जो आपने एक पुल के 85 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण करने की बात की है उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि कई बार उद्घाटन हो जाता है और देनदारियां रह जाती हैं। मैं इसकी पूर्ण सूचना ले लूंगी। अधिकतर यह होता है कि उद्घाटन हो जाता है और ठेकेदार की देनदारियां स्टैंड रहती है। मैं इसको चैक कर लूंगी। जो आप भवनों के निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं, आपको इसके लिए संतुष्ट होना चाहिए कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में इतने ज्यादा कार्य हो रहे हैं। अगर आपको कोई अन्य सूचना चाहिए होगी तो वह आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।

07.03.2022/1455/RKS/YK-2

प्रश्न संख्याः 4864

कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार इस सब-स्टेशन का काम जून, 2022 तक शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि इस सब-स्टेशन को स्थापित करने के लिए अभी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या माह जून तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस 33 के.वी. सब-स्टेशन के लिए निजी भूमि चिन्हित की गई है। इसकी भूमि अधिग्रहण के लिए नेगोशिएशन चली हुई है। इस भूमि को शीघ्र अधिग्रहण करके सब-स्टेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

07.03.2022/1500/बी.एस./ए0जी0/-1

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस साप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं, जोकि इस प्रकार हैः-

सोमवार, 7 मार्च, 2022 शासकीय/विधायी कार्य/
बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 पर सामान्य चर्चा।

मंगलवार, 8 मार्च, 2022 शासकीय/विधायी कार्य/
बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 पर सामान्य चर्चा।
बुधवार, 9 मार्च, 2022 शासकीय/विधायी कार्य/
बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 पर सामान्य चर्चा एवं समापन।

वीरवार, 10 मार्च, 2022 1. शासकीय/विधायी कार्य ।
2. गैर-सरकारी सदस्य कार्य।
शुक्रवार, 11 मार्च, 2022 शासकीय/विधायी कार्य/ वित्तीय बजट अनुमान वर्ष 2022-23 मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

07.03.2022/1500/बी.एस./ए0जी0/-2

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब सचिव, विधान सभा द्वारा पारित विधेयक की प्रति, जिनमें महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, सभा पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से **हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6)** की प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्तहो चुकी है,की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।
07.03.2022/1500/बी.एस./ए0जी0/-3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से , बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 की प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

07.03.2022/1500/बी.एस./ए0जी0/-4

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटलट पर रखता हूंः-

(i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्यांक 68) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20; और

(ii) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्यांक 68) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21।

I07.03.2022/1500/बी.एस./ए0जी0/-5

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का **49वां मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा 5.3 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश समान्य उद्योग निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-

18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा 5.4 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम** से सम्बन्धित है

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी यूक्रेन में फंसे हिमाचल के छात्रों के बारे में इस माननीय सदन में वक्तव्य देना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यूक्रेन में जो हिमाचल के बच्चे फंसे हैं, उनकी वजह से हम सब चिंतित हैं और उनके परिवार जन, वे तो बहुत ही चिंचित हैं। आदरणीय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयत्न किए हैं और जितने भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं, चाहे वे छात्र हैं, चाहे अन्य नागरिक हैं। उन्हें बचाने के लिए, भारत पहुंचाने के लिए

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

07-03-2022/1505/ए.जी.-एन.जी. /1

मुख्य मंत्री..... जारी

एक बहुत बड़े अभियान के रूप में उस कार्य को गति देने की कोशिश की है और उसमें सफलता भी हासिल की है। वहां पर जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके माता-पिता के साथ हम लगातार सम्पर्क में हैं। इसी बीच में बच्चों के साथ भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया था। उस समय बच्चों ने जो हमारे साथ जानकारी सांझा की कि किस प्रकार उन्हें वहां से निकाला जा सकता है और क्या करना उचित रहेगा, क्योंकि वहां की परिस्थिति को वे बहुत करीबी से देख व समझ रहे हैं। ऐसे में जो भी जानकारियां हमारी तरफ से केन्द्र सरकार को दी जानी चाहिए थीं वह हमने दे दी है और उसका परिणाम भी अच्छा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस माननीय सदन को लेटस्ट स्थिति से अवगत करवाना चाहता हूं। यूक्रेन में युद्ध की स्थिति से उत्पन्न संकट में वहां से प्रदेश के छात्रों की सकुशल वापसी की नवीनतम स्थिति से मैं आज पुनः सदन को अवगत कराना

चाहता हूं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापिस लाने के लिए पड़ोसी देशों से 'ऑप्रेशन गंगा' के तहत कमर्शियल व भारतीय वायु सेना के विमानों की उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इस संदर्भ में प्रदेश सरकार पूर्ण संवेदनशीलता से विदेश मंत्रालय एवं यूक्रेन व पड़ोसी देशों में फंसे प्रदेश के छात्रों व उनके परिवारों से लगातार संपर्क में है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 410 छात्र सकुशल वापिस पहुंच चुके हैं। अभी प्रदेश के 58 छात्र यूक्रेन अथवा पड़ोसी देशों में हैं। उनकी वापसी के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यूक्रेन के पूर्वी भाग में रूस की सीमा के पास स्थित खारकीव से सभी भारतीय अब निकल चुके हैं। सूम्मी शहर में अभी भी भारतीय छात्र फंसे हैं जिन्हें निकालने के लिए विदेश मंत्रालय यूक्रेन व रूस दोनों देशों से संपर्क में है तथा हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

07-03-2022/1505/ए.जी.-एन.जी. /2

हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के शेष छात्र भी शीघ्र ही सकुशल लोटेंगे। इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार सभी परिवारों के साथ खड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानकारी के रूप में इस माननीय सदन को अवगत करवाया है क्योंकि सभी बच्चों के परिवारजन बहुत चिंतित हैं। मुझे लगा कि जो भी जानकारी हम तक प्राप्त हो रही है उस जानकारी को मैं लगभग हर रोज इस माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश के लोगों तक पहुंचाता रहुं।

07-03-2022/1505/ए.जी.-एन.जी. /3

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-323 के अंतर्गत व्यवस्था के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 05-03-2022 को

बजट अनुमान की चर्चा पर भाग ले रहा था और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन में उपस्थित नहीं थे। परंतु माननीय मुख्य मंत्री जी बीच में इस माननीय सदन में आए और उसमें इन्होंने दख़ल दिया। इन्होंने जिस प्रकार से मुझे सम्बोधित किया, जिस प्रकार से डांट पिलाई, ऐसा तो स्कूल में भी बच्चों को नहीं करते। इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वह अभद्र व अशिष्ट भाषा थी। माननीय मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन के नेता भी हैं और इनके शब्द, इनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थे। इन्होंने कहा कि 'इस आदमी ने', 'यह आदमी हमें सिखाएगा', 'यह बकवास करता है', 'यह प्रधान मंत्री को गालियां देता है'। अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही निकालिए और देखिए कि कहीं पर भी मैंने प्रधान मंत्री जी को गाली दी हो, यह ठीक है कि उनकी जो नीतियां खराब हैं उनको मैंने यहां पर भरपूर उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको लिखित में भी दिया है कि इन्होंने जो भी अशिष्ट शब्द यहां पर कहे हैं, यदि माननीय मुख्य मंत्री इसी प्रकार की शब्दावली मेरे से भी अपेक्षा करते हैं तो मैं भी इन्हें 'ये मुख्य मंत्री नहीं ये आदमी' कहुंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर आप व्यवस्था दीजिए और कार्यवाही में जो इस प्रकार की शब्दावली आई है

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

07.02.2022/1510/JS/AS/1

श्री जगत सिंह नेगीः-----जारी-----

नियम 331 के तहत उन शब्दों को एक्सपंज किया जाए। आगे के लिए मुख्य मंत्री को भी, मंत्रियों को भी और सभी को दिशा-निर्देश दें कि किस तरह से हमने एक-दूसरे को सम्बोधित करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं और इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिए। धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि रुल 299 को अगर सख्ती से लागू नहीं करेंगे तो इस माननीय सदन का जो पूरे हिन्दुस्तान में नाम है, फिर वह गरिमा नहीं रह पाएगी। उसमें लिखा गया है कि जब कोई सदस्य बोलेगा या मंत्री बोलेंगे तो बीच में कोई इन्टरवीन नहीं करेगा। उस नियम को आप सख्ती से लागू करें कि बैठे-बैठे न मंत्री बोलें और न ही माननीय विधायक बोलें। धन्यवाद।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है आज विपक्ष बड़े ज्ञान के साथ हमारा मार्ग दर्शन कर रहे हैं। ये यहां पर नियमों का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई होती, आप लोगों को बात करने से कौन रोक रहा है? लोकतंत्र है और आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस प्रकार से जगत सिंह नेगी जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिस प्रकार से आपका व्यवहार यहां पर सब लोगों ने यहां पर देखा, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं देखा है। अध्यक्ष महोदय, यह इनका स्वभाव बन गया है। इन्होंने पहले भी प्रधान मंत्री को गाली-गलौज की है। पिछली बार भी यानि पिछले साल की बजट की कार्यवाही अगर आप देखेंगे, इन्होंने प्रधान मंत्री जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का चयन किया है? ये हर वक्त प्रधान मंत्री जी के लिए बोलते हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी की सभा हो तो समझ में आता है कि आपको कुछ लोगों के बीच में एक माहौल खड़ा करना होता है, वहां पर आप बोलिए लेकिन इस माननीय सदन के अन्दर तो आप लोग शालीनता, सब्र और संयम रखिये। यदि आप लोग बोलते ही रहेंगे, हर-कुछ बोलते रहेंगे तो यह सम्भव नहीं है कि हम सामने से कुछ नहीं बोलेंगे। आप कैसे यह उम्मीद लगाए बैठे हैं।

07.02.2022/1510/JS/AS/2

अगर *"यह आदमी"* शब्द कहीं पर मैंने यूज़ किया, "यह आदमी" शब्द मेरे ख्याल से तो असंदीय नहीं है। अगर हमने इस माननीय सदन में यह शब्द बोला है और अगर यह असंसदीय है तो आप इसे कार्यवाही से निकाल दीजिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आदमी तो आदमी है। यह भी आदमी है और वह भी आदमी है। आदमी से ऊपर भगवान तो

मैं आपको नहीं बोल सकता। कम-से-कम आपको मैं भगवान तो नहीं बोल सकता हूं इसके लिए मुझे माफ करें। आप लोग इस तरह से शब्द सौ बार बोलते हैं। श्री जगत सिंह नेगी जी, आप इस तरह से शब्द सौ बार बोल चुके हैं। हमने यदि एक बार बोला और आपको आपत्ति हो गई? अध्यक्ष जी, जो इन्होंने यहां पर नियमों का हवाला दिया है, नेगी जी, आपको सारी चीजों का ज्ञान है और आपने उपाध्यक्ष के नाते इस चेयर की भी शोभा बढ़ाई है। आपको तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप तो ऊपर ही बैठते थे हम तो नीचे ही बैठते थे। न उस वक्त ऊपर बैठते थे और न आज। मुझे लगता है कि इस तरह की आपको बातें नहीं करनी चाहिए आपको सब्र करना चाहिए। गुस्सा आ भी जाता है कि जब आप ज्यादा ही बोलेंगे, बोलते ही रहेंगे और हर कुछ बोलते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें भी गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आता है कि हम सब भेदभाव भुला कर चले हैं। जो आदमी अपने आपको इस माननीय सदन में डिफैंड नहीं कर सकता है उसके बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए। जब माननीय प्रधान मंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आज की तारीख में वे देश के प्रधान मंत्री हैं वे अपना पक्ष इस सदन के अन्दर तो प्रस्तुत नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कह सकते । आप बोलिए, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलिए, उनकी योजनाओं के खिलाफ बोलिए लेकिन आप टिप्पणी करते-करते उनकी मिमिक्री करने लग जाएंगे तो वह बहुत दुखद परिस्थिति होती है। इसलिए आप अगर सब्र रखेंगे तो हमें तो पहले से ही सब्र है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही शब्द यहां पर कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य,अब यहां पर बात आ गई है। कोई भी बात एक तरफा नहीं है। यहां से जगत सिंह नेगी जी ने कहा और वहां से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा। अब मैं व्यवस्थता देता हूं। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी बात आ गई है, आप बैठिए।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

07.03.2022/1515/SS-AS/1

अध्यक्ष : एक तरफा क्यों? यहां से नेगी जी ने कहा और यहां से इन्होंने (मुख्य मंत्री जी) कहा। अब मैं व्यवस्था दे देता हूं। मुकेश अग्निहोत्री जी बात आ गई है इसलिए आप बैठिए। ...व्यवधान...

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा का सवाल है। सदन में रोज़ पक्ष-विपक्ष की डिलिंग होती है। मुख्य मंत्री जी ने हमारे दो सदस्यों के लिए बातें कही हैं, एक जगत सिंह नेगी जी और दूसरी सुन्दर सिंह ठाकुर जी के लिए कही हैं। हम सब आपको क्या कहते हैं?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बात सुनिए। आप बैठिए, मैंने आपको सुन लिया है। वह जगत सिंह नेगी जी ने कह दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : ऐसे नहीं होगा कि आप मुख्य मंत्री जी की सुन लें। हमें अपनी बात कहनी है।

अध्यक्ष : मैंने इनकी बात सुनी क्योंकि इन्होंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर लिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : मैं विपक्ष का लीडर बोल रहा हूं। क्या आप विपक्ष के लीडर को नहीं सुनेंगे? आप हमें भी समय दें। मुख्य मंत्री जी ने बात रख दी है और हमें भी अपनी बात रखनी है। बात ऐसे खत्म नहीं हो जाएगी कि आप हमारे सदस्यों को बदतमीज कहें, आप हमारे सदस्यों को कहेंगे कि तहजीब नहीं है, बकवास कर रहो हो। क्या आपसे ये एक्सपैक्टिड है? ये रिकॉर्ड पर है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बदतमीजी कर रहे हैं, तहजीब नहीं है। यह बात तब खत्म होगी जब मुख्य मंत्री जी द्वारा कहे हुए शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आप जगत सिंह नेगी और श्री सुन्दर सिंह ठाकुर के खिलाफ मुख्य मंत्री जी द्वारा कहे गए शब्दों को कार्यवाही से निकालते हैं तब ठीक होगा, नहीं तो बात बढ़ती रहेगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए। मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि जो माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर लिया ...व्यवधान... आप बैठिए।

07.03.2022/1515/SS-AS/2

व्यवस्था मैं दूंगा या कि आप देंगे? प्वाइंट ऑफ ऑर्डर जगत सिंह नेगी जी ने रेज किया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : सदन में हर सदस्य माननीय है। कोई भी सदस्य है तो वह माननीय है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य और ये आदमी हो गया। ...व्यवधान... क्या ऐसा कहेंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए इसको कार्यवाही से निकाल जाए। ...व्यवधान...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए। विनोद जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? हर्षवर्धन जी, आप बैठिए। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। विनोद जी, आपका क्या विषय है?

श्री विनोद कुमार (नाचन) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वे ज़रा अपना वक्त याद करें। इनके समय में विधायकों को टोंडा कहा गया। इनके समय में विधायकों को बंधुआ मजदूर कहा गया। इनके समय में विधायकों को कहा गया कि आपकी छाती पर मूंग दलेंगे, तब आपको कुछ समझ नहीं आया। आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण जगत सिंह नेगी जी इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? ...व्यवधान...

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष : व्यवस्था मैं दूंगा। माननीय सदस्य विनोद जी, बैठिए। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे बैठें। वे बैठ गए हैं और आप भी बैठें। ...व्यवधान... ये जो विषय श्री जगत सिंह नेगी जी ने 5 मार्च, 2022 का उठाया जब ये बजट के ऊपर अपनी बात यहां पर रख रहे थे। **मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि मैं उस दिन की कार्यवाही को देखूंगा।** ...व्यवधान... **वह भी एक व्यवस्था का पार्ट है। उसको मैं देखूंगा और अगर उसमें असंसदीय शब्द होगा तो उसको कार्यवाही से निकालेंगे।**

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2020/1520/केएस/डीसी/1

अध्यक्ष जारी...

...(व्यवधान)... संसदीय क्या है और असंसदीय क्या है, वह इस चेयर को डिसाइड करना है। आप बैठिए। ...(व्यवधान)... मुकेश जी, यही व्यवस्था है और क्या है? आप बैठिए। मैं कार्यवाही देखूंगा और जो असंसदीय शब्द है, उसको हम निकालेंगे। माननीय सदस्य, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि जब हम विषय पर बोलते हैं, बजट पर बोलते हैं तो हम बजट तक ही सीमित रहें। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अब हमको सब्र करना चाहिए, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ...(व्यवधान)...जो शब्द आपने बोले हैं, ये किसी भी प्रकार से असंसदीय, ठीक है गुस्से में जब बात होती है तो इन शब्दों का उच्चारण हो जाता है। ...(व्यवधान)... मेरी बात सुन लीजिए। आप सिरमौर की भाषा में यहां पर मुख्य मंत्री का नारा लगा रहे थे। जोइया राम मणदा नई, कर्मचारियों री शुणदा नई। What is this Joeya Ram? आप बताएं, आप हमको ज्ञान मत दीजिए। ...(व्यवधान)... आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको मालूम है इसका क्या मतलब होता है?

(**कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर शोर-शराबा करने लगे**)

आपको मेरे से ज्यादा पता है? आप यह मत सोचो कि आपको ही सबकुछ आता है। ...(व्यवधान)...मैं यह आपको भी बोलूंगा। अध्यक्ष जी, जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, उसको फिर हम क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे और बार-बार बोलेंगे। सब बोलते हैं, पूरे प्रदेश में बोलते हैं ऐसा।...(व्यवधान)...

अध्यक्षः मैंने व्यवस्था दे दी है। कृपया करके बैठिए। माननीय सदस्य, बैठिए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, बैठिए। मैंने व्यवस्था दे तो दी। आप बैठिए।

(**कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करने**)

07.03.2020/1520/केएस/डीसी/2

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी है कि मैं रिकॉर्ड देखूंगा। फिर आप और क्या चाहते हैं?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठिए ना। मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)... सत्ता पक्ष से भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि अगर इस कार्यवाही में कुछ असंसदीय होगा तो उसको निकाल दें। मैं कार्यवाही देखूंगा, यह व्यवस्था मैंने दे दी है और मुख्य मंत्री जी ने भी यही बात यहां से कही है तो आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

07.03.2022/1525/av/dc/1

अध्यक्ष----जारी

अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा शुरू होगी। इसमें आज आपकी (विपक्ष) तरफ से भी 7 सदस्यों ने बोलना है इसलिए कृपया करके बैठ जाइए और इस प्रकार समय नष्ट मत कीजिए। ...व्यवधान... मैं अब माननीय वन मंत्री श्री राकेश पठानिया को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। । ...व्यवधान...

(विपक्ष के सभी सदस्य नारे लगाते हुए बहिर्गमन करके चले गए।)

माननीय शहरी विकास मंत्री, आप बोलिए।

शहरी विकास मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन में विपक्ष की ओर से पीठ द्वारा दी गई व्यवस्था के बाद भी इस प्रकार का व्यवहार करना अपने आपमें असंसदीय है। पक्ष और विपक्ष की किसी मुद्दे पर लड़ाई हो सकती है मगर जो पीठ की ओर से व्यवस्था

आती है; यहां पर आपने रूलिंग दे दी कि मैं सारा रिकॉर्ड देखूंगा और उसमें यदि कोई असंसदीय शब्द पाया जाएगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का वॉकआउट व्यवस्था के विरुद्ध है और यह अपने आपमें सदन की मर्यादा को भंग करता है। इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है। प्रदेश के किसी भी विकासात्मक कार्य, बिल, बजट या बाकी किसी विषय पर वॉकआउट किया जाए; तो वह बात समझ आ सकती है। लेकिन अध्यक्ष की रूलिंग के विरुद्ध इस प्रकार का व्यवहार करना और वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सदन में प्रधान मंत्री जी का मजाक उड़ाते हैं, उनकी यहां पर मिमिक्री करते हैं जोकि सबने देखी है। उनका इस बारे में यह कहना है कि कोई शब्द नहीं बोले गए। बेशक शब्द नहीं बोले गए मगर व्यवहार में उन्होंने यहां रामलीला में रावण द्वारा लगाए जाने वाले अट्टाहस का प्रयोग किया है; ये लोग यहां पर इस प्रकार का व्यवहार करते रहे हैं। उनका इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है। यहां सदन के अंदर चर्चा और वाद-विवाद करने के लिए प्रदेश की जनता का पैसा खर्च होता है। मगर ये लोग यहां अपनी व्यक्तिगत बात के लिए सदन से बहिर्गमन करके जा रहे हैं; इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस प्रकार के व्यवहार के लिए इनको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि अगर इस प्रकार का शब्द होगा तो उसको निकाल सकते हैं।

07.03.2022/1525/av/dc/2

आपने भी रूलिंग दी कि यदि इस प्रकार का कोई शब्द इस्तेमाल हुआ होगा तो उसको निकाल देंगे। उसके बावजूद भी सदन से बहिर्गमन करना आपसी संधि और प्रदेश की जनता का सरासर अपमान है; जोकि निंदनीय है।

समाप्त

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इन सारी बातों का अधिकार उस व्यक्ति को है जो इन्हें अपने ऊपर लागू करता हो। विपक्ष के लोग हमें नियम, भाषा और आचरण की बातें सिखा रहे हैं मगर इनको देखना चाहिए कि इनका इस माननीय सदन के अंदर किस प्रकार का आचरण होता है। ये लोग माननीय राज्यपाल तथा प्रधान मंत्री जी के विरुद्ध तो

टिप्पणी करते ही हैं मगर उसके बाद आसन के खिलाफ भी टिप्पणी करते हैं। अब किस हद तक इन सारी बातों को हम सहन करते रहेंगे। एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या एक व्यक्ति को इस प्रकार का अधिकार दिया जा सकता है कि वह यहां पर किसी के विरुद्ध कुछ भी बोलता जाए।

टी सी द्वारा जारी

07/03/2022/1530/टी0सी0वी0/एच0के0/1

मुख्य मंत्री.... जारी

इस प्रकार की व्यवस्था को रोकने के लिए नियम बनें हुए हैं और आपने नियम के अनुसार उचित व्यवस्था दी है। वे व्यक्ति जो शब्दावली के माध्यम से इस माननीय सदन का सबसे ज्यादा समय और माहौल खराब करते हैं, वे आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने इसके लिए व्यवस्था दी कि मैं पहले रिकॉर्ड की जांच करुंगा और उसमें यदि कोई असंसदीय शब्द पाया जाएगा तो उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। इसमें मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जब इस प्रकार का माहौल होता है तो गुस्से में कुछे ऐसे शब्दों का चयन हो जाता है। मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसके कारण इस माननीय सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है तो उस पर अध्यक्ष महोदय विचार करें और निर्णय दें लेकिन व्यवस्था देने के बाद वे तो शांत हो गए परंतु उनके बाद विपक्ष के नेता जिनके बारे में सारा प्रदेश जानता है कि उनका व्यवहार कैसा है? उनकी भाषा किस प्रकार की होती है, इस बजट की चर्चा में वे किस प्रकार की टिप्पिंया करते हैं? वे अपनी भाषा के कारण जाने-पहचाने जाते हैं। वे फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वे इस प्रकार से मार्गदर्शन करना छोड़ दें। उन्होंने जो अपनी बात कहनी थी, वह कह दी। उसके बाद आपने कहा कि मैं इस बारे में व्यवस्था दूंगा। क्योंकि आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं था और इनको सदन से बाहर निकल कर खबर बनानी थी। इसका यह पहले से इंतजाम करके आए थे कि हम मुख्य मंत्री या चेयर के खिलाफ वाकआउट करेंगे तो अपने आप खबर बनेंगी। उनके द्वारा इस तरह के व्यवहार से इस माननीय सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के सिवाय कुछ नहीं हुआ। बजट पर इतनी

महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, उस चर्चा में भाग लेते और अपनी बात कहते तो अच्छा रहता। वे बजट पर कहां बोले, वे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बोलते रहे। अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि उनको संयम रखना चाहिए। जब वे इस तरह से सारी सीमाएं पार करते हैं तो हमें भी इस तरह से सब्र और संयम का पाठ पढ़ाने का काम बन्द करें। हम भी मनुष्य हैं,

07/03/2022/1530/टी0सी0वी0/एच0के0/2

देवता तो हम भी नहीं है और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की टिप्पणियां बार-बार सुनते रहेंगे तो उनको भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि सामने से भी उसका जवाब आएगा। अगर हमारे सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने जवाब दिया है तो उसको सुनने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए था। क्योंकि जितना वे बोले हैं, हमारे माननीय सदस्यों ने उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। हमने इसी सदन में देखा है, हमें 'मक्कड़-झण्डू', 'बंधुवा मजदूर','टोंडे' और 'खेप्सू भाट' बोला गया। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने शब्द बोले गए। मैं उनका ज़िक्र नहीं करना चाहता। लेकिन सभी सदस्यों को मर्यादा में रहना चाहिए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इनकी आदत का यह एक हिस्सा बन गया है कि किस तरह से ऐसा माहौल खड़ा किया जाए जिससे सदन से बाहर जाने का रास्ता निकल सके और खबर बन जाए। आज बजट पर चर्चा होनी है और आज खबर नहीं बन पा रही थी। विपक्ष के नेता कई लोगों को फोन करते हैं कि today is my day और मुझे डियू कवरेज मिलना चाहिए। ये जाकर मीडिया के लोगों को कहते हैं कि आपने मुख्य मंत्री को कवरेज दी है लेकिन मुझे कवरेज नहीं दी है? It was my day.

एन0एस0 द्वारा जारी ...

07-03-2022/1535/NS/HK/1

मुख्य मंत्री .....जारी

इसलिए मैं उन सारी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। यह सच्चाई है। अगर विषय पर बोलते और अच्छा बोलते तो अपने आप कवरेज़ मिलती। मुझे मालूम नहीं है कि कहां कमी रह गई होगी? इनको कवरेज़ तो मिली है लेकिन ये पूरे चार पेज़ चाहते होंगे। ऐसा तो संभव नहीं कि अखबार वाले नेता प्रतिपक्ष के चार पेज़ छाप देंगे। हमने तो आज तक मीडिया वालों को कुछ नहीं कहा चाहे खबर अच्छी लगी या बुरी लगी। मीडिया स्वतंत्र है और लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है और हमारा उनके प्रति सम्मान है तथा कभी टिप्पणी नहीं करते। उनका अपना आकलन है अगर ठीक नहीं लगी है तो उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है कि ठीक करना है, बेहतर करना है और कमी रह गई तो उसको ठीक करना है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनको तो तारीफ़ चाहिए। यहां सदन में उनकी इच्छा ऐसी होने लग पड़ी है जैसे कि वे हमसे भी चाह रहे हैं कि हम भी उनकी तारीफ़ करें। अगर तारीफ़ के काबिल होते तो हम करते। व्यवहार उनके बोलने से नहीं हो पाएगा जो वे कह रहे हैं। व्यवहार दिखना और लगना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने आज वाकआउट किया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

07-03-2022/1535/NS/HK/2

<u>वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा</u>

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों पर वार्षिक वित्तीय विवरण पर आगे चर्चा प्रारम्भ होगी। अब मैं श्री राकेश पठानिया जी, माननीय वन मंत्री को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने 4 मार्च, 2022 को जो बजट पेश किया है मैं उसके पक्ष पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(कांग्रेस विधायक दल के कुछ माननीय सदस्य सदन में वापिस आए।)

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने परसों जिस तरीके से भाषण दिया। उसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा कि वे बजट के ऊपर नहीं बोले। उन्होंने अपना विषय जी0डी0पी0 से शुरू किया कि आपने 8.2 का फिगर कहां से निकाल दिया और मुख्य मंत्री जी आपके पास जादू की कौन-सी लाठी है? हिमाचल प्रदेश देश का नम्बर वन प्रदेश रातोंरात कैसे बन गया और जी0डी0पी0 इतनी कैसे बढ़ गई? इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि इन्होंने इस किताब को पढ़ा ही नहीं। इसको 'V Shape' में मानद किया जाता है। 'V

Shape' का मतलब जिस तरीके से नीचे आती है उस तरीके से ग्रो करती है। कोविड के दौरान जी0डी0पी0 -5.2 आ गई थी और देश की जी0डी0पी0 -27 पर चली गई थी। उसके बाद 'V Shape' के फॉर्मूला में हमारी ग्रोथ वापिस ऊपर आई है उसके अंदर लगभग 20,000 करोड़ एकस्ट्रा ग्रोथ में आया है उसकी वज़ह से हम यहां पर पहुंचे हैं। बजट भाषण के पेज नम्बर-4 में मुख्य मंत्री जी ने बड़ा क्लीयर लिखा है कि 'Speaker, Sir, the economy of the State is expected to grow at 8.3 percent during 2021-22. Despite Pandemic adversity in 2020-2021, this increase is a big achievement of our Government.' इसमें बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख 75 हजार 173 करोड़ रुपये रहेगा। पर बिना पढ़े केवल स्टैंड्ज़ को बोलना, मीडिया के लिए बोलना और केवल इस बात के लिए बोलना कि इस चीज़ का एक राजनीतिक इश्यू बने कि यह जादू की छड़ी कौन-सी है जिसके माध्यम से जी0डी0पी0 ग्रोथ 8.3 हो गई। बड़े सही तरीके से इसको दो पेज में एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रोथ रेट कैसे बढ़ा है? मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट हिन्दुस्तान का वन ऑफ दि बेस्ट ग्रोथ रेट आया है। इसके लिए भी यहां पर ऐसा व्यवहार किया गया कि

07-03-2022/1535/NS/HK/3

पता नहीं हमने क्या कर दिया? अध्यक्ष महोदय, जितने प्वाईंट्स इन्होंने यहां पर बोले they were all address to the gallery, not to the Chair.इसके बाद इन्होंने अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा लंबा-चौड़ा भाषण दे दिया। जैसे हम तो अधिकारियों का खून पीन आए हुए हैं, हम तो अधिकारियों के दुश्मन हैं और इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

07.03.2022/1540/RKS/YK-1

वन मंत्री... जारी

हम कर्मचारियों की शक्ल नहीं देखना चाहते, हम कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, आपने इस तरीके से अपने आप को चैम्पियन प्रमोट करने का प्रयास किया। आप यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आप ही कर्मचारियों के हितैषी हैं और हम उनके दुश्मन।

लेकिन सच्चाई कुछ और है। जितना पैकेज श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने कर्मचारियों को दिया है इससे ज्यादा शायद कभी नहीं दिया होगा। आप जिस तरीके से पत्रकार दीर्घा को अड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी है, यह बड़े शर्म की बात है। यहां पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर आधे घंटे का भाषण दिया गया और कहा गया कि पेंशन के चार सलैब बना दिए। आपके समय में किस आयु में पेंशन दी जाती थी? आप 80 वर्ष की आयु में पेंशन देते थे जबकि हिमाचल प्रदेश के लोगों का लाइफ-स्पैन 77 वर्ष है। यानी जब इंसान मर जाता था उसके बाद आप पेंशन देते थे। हमारी सरकार ने 80 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष किया और आप इस पर भी भाषण दे रहे हैं। आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। आपको इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। आपने अभी तक जितने भी भाषण दिए हैं उसमें सिर्फ यही कहा गया कि इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके कार्यकाल में प्रस्तुत हुए अंतिम बजट का दस्तावेज लेकर आया हूं। मैंने इस दस्तावेज को पूरा पढ़ा है। आप कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि आपने पानी की पाइपें कहां बिछाई? हमने सारी पाइपें हिमाचल प्रदेश में ही बिछाई हैं। हमने लोगों के घर-घर में नलके लगाए। आपने 70 वर्षों में 7 लाख नलके लगाए जबकि हमारी सरकार ने गत चार वर्षों में 8 लाख नलके लगाए हैं। लेकिन आप इस बात पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। इसके लिए आपको सरकार को बधाई देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय आपने हिम केयर कार्ड शुरू किया था। उस समय हिम केयर कार्ड एक साल के लिए वैलिड था। लेकिन अब इस कार्ड की नवीनीकरण अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। इस योजना

07.03.2022/1540/RKS/YK-2

के अंतर्गत लाभार्थियों को 218 करोड़ रुपये की निःशुल्क चिकित्सा सेवायें प्रदान की गई हैं। हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत नये कनैक्शन पर एक वर्ष में तीन निःशुल्क सिलेंडर देने का प्रावधान किया है। लेकिन आपको कोई उपलब्धि नजर नहीं आ रही है।

नेता प्रतिपक्ष यहां उपस्थित नहीं है। आप भी पांच वर्ष मंत्री रहे। आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? Ease of Doing Business में आपका क्या स्थान था? आप Ease of Doing Business में 16वें नम्बर पर थे लेकिन आज हम 7वें नम्बर पर आ गए हैं और इसके लिए मैं श्री जय राम ठाकुर और माननीय उद्योग मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। यहां पर इतनी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टर मीट हो गई लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन करने के लिए यहां आए परंतु आपको यह भी नज़र नहीं आ रहा है। लगभग 41 हजार करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहां हुई और आप कह रहे हैं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप उद्योग मंत्री रहे, आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया? हम इन चार वर्षों में हुए कार्यों के बारे में बता रहे हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए 80 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष किया है। हमने हिमकेयर कार्ड, मुफ्त राशन और मुफ्त सिलेंडर वितरित किए हैं। हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल दिये, चैक डैम बनाए, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए, वेंटिलेटर स्थापित किए और इस वैश्विक महामारी का सामना किया। लेकिन आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? अगर आप अपने कार्यकाल में हुए एक काम के बारे में बता देते तो हम आपके लिए ताली बजाते। ...व्यवधान...

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

07.03.2022/1545/बी.एस./वाई0के0/-1

वन मंत्री जारी...

आप इस सदन में बोल रहे हैं, आपने एक्साइज का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने अपने समय में कोई नीलामी ही नही की। मैं यहां पर आपका सारा रिकार्ड ले करके आया हूं। You can see your record. वर्ष 2012-13 में निन्यूअल वर्ष 2013-14 में रिन्यूअल वर्ष 2014-15 में रिन्यूअल और वर्ष 2015-16 में रिन्यूअल, उसके बाद आपने टैंडर किया और जब टैंडर

किया तो आपने कारपोरेशन बना दी। यदि कारपोरेशन का नाम लेंगे तो आपको राहत पड़ जाएगी।

श्रीमती आशा कुमारी : मंत्री जी, आप बजट पर बोलिए।

वन मंत्री : मैडम, यह बजट का पार्ट है। Please, I am replying to the Leader of the Opposition. उनकी स्पीच में मैं साथ ले करके आया हूं। उन्होंने कहा कि आप शराब के ठेके क्यों नहीं बेचते हैं? इन्होंने 10 बार यही पूछा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ठेके कब बेचे हैं? आपने कारपोरेशन बना करके प्रदेश को ही बेच दिया। कारपोरेशन बनाने से एक वर्ष पहले आपकी ग्रोथ कितनी आई थी? 15.61 और अगले वर्ष कितनी आई? -26, प्रदेश को कितना नुकसान हुआ? प्रदेश की गरीब जनता को 170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आप बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने स्टोक्स परिवार के लिए सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल की यहां पर घोषणा की है। But you didn't have the courtesy to say thank you even once. आपकी वरिष्ठ नेता रही हैं। प्रदेश का फ्रूट बाउल बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी ग्रो कर रही है it is because of that family. जो यहां पर सेब ले करके आए उस कारण से हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश कहां-से-कहां चला गया है? परंतु आपके पास धन्यवाद के लिए एक शब्द नहीं था। क्या इसका यही कारण है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उनका नाम ले लिया है। आप अच्छे काम की भी तारीफ करना सीखिए, आपको केवल और केवल आलोचना करनी आती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। आपने बार-बार कहा कि आपने रेवेन्यू मेनेजमैंट क्यों नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पिछली सरकार में राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक सब

07.03.2022/1545/बी.एस./वाई0के0/-2

कमेटी बनाई थी, कमेटी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? क्या आपने इसकी एक भी मीटिंग की थी? You have not even held one meeting of that Revenue Committee और आज यहां पर गला फाड़-फाड़ के भाषण दे रहे हैं कि आप रेवेन्यू रिसोर्सिज के बारे में क्या

कर रहे हैं? आप अपने समय में क्या कर रहे थे? अगर मैं आपकी कारपोरेशन की बात करूं, HPLB आपको होल सेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। आपने इसके तीन जगह स्टोर्ज बना करके इसकी रिटेल स्पलाई आरंभ कर दी। उसके बाद आपने ऊना,चम्बा और किनौर के ठेकों में रिटेलिंग शुरू कर दी and that thing netted us a net loss of Rs. 79 crore. 80 करोड़ रुपए का आपने वहां अलग से नुकसान किया। जो हमें एक्साइज की कमाई आनी थी, उसे गवां करके -26 प्रतिशत ले गए। आपने अपने हाथों से हिमाचल प्रदेश को लूटा, आपने आपने हाथों से इस हिमाचल प्रदेश का गला घोंटा और आपने अपने हाथों से हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क किया और आज हमें भाषण दे रहे हैं कि हमने क्या किया? हमने जो किया वो तो हमने गिना दिया है। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी बताया है और मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें भी बताया है। आज में मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जो पार्क आपको मेडिसिन डिवाइस के लिए मिला, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बल्क ड्रग जो है इस वक्त ईन लाईन है। वह भी हिमाचल प्रदेश के अन्दर आने वाला है। Every Government is ongoing Government. आपने जो अच्छे काम किए उन्हें हम गिना रहे हैं Horticulture Mission of Project आपके समय में आया था, मैं इस बात को मानता हूं और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आप एक अच्छा प्रोजैक्ट ले करके आए थे। आदरणीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी ने उसे कंटिन्यू किया। आज पूरे प्रदेश के अन्दर उद्यान की दिशा और दशा सुधर गई है। मैं हर एरिया में गया हूं, चाहे वह ट्रॉपिकल हो या सब-ट्रॉपिकल, हर एक एरिया में हमने उस पर काम किया है। आपने समय में आया we appreciate that. आप भी तो अच्छे काम की प्रशंसा करने की हिम्मत करें। आपके समय में जाइका का प्रोजैक्ट आया था, मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूं। मैं वन मंत्री हूं, ठीक है, आप इस प्रोजैक्ट को ले करके आए थे, परंतु आपने जानबूझ करके कांगड़ा नहीं डाला था। बल्क ड्रग जो है इस वक्त ईन लाईन है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

07-03-2022/1550/ए.जी.-एन.जी. /1

वन मंत्री..... जारी

ठीक है जाइका का प्रोजैक्ट आप लेकर आए थे लेकिन आपने उसमें कांगड़ा नहीं डाला था, जानबूझ कर नहीं डाला था। उसमें कांगड़ा व चम्बा जिला पूरा का पूरा नहीं है लेकिन अब हमने उसमें दोनों जिले डाले हैं। हम पूरे हिमाचल प्रदेश को एक नज़र से देखते हैं लेकिन आप नहीं देखते थे। मैंने आपको सारे आंकड़े इसके अंदर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष जी आपका स्वागत है।

खिज़ा **आई पर फूल खिलते रहे,**

तेज थी आंधियां पर दीप जलते रहे,

शाख से झड़ जाए हम वो पत्ते नहीं,

आंधियों को कह दो कि अपनी औकात में रहे ।

माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप पिछले कल बहुत बढ़िया रैली करके आए हैं लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वहां पर आपने इतना बढ़िया भाषण दिया है और मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी भी इतना अच्छा बोलती है, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपकी कल की रैली देख रहा था और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप फिर से जीत कर आएंगे लेकिन बैठेंगे इसी कुर्सी पर जहां आप आज बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौन सा सैक्टर है जिसे इस बजट में हाथ नहीं लगाया गश हो और माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ऐसा कौन सा सैक्टर है जिसे आपने टच भी किया हो? आपने यहां पर एक राजनैतिक भाषण देने का प्रयास किया और मैं उसका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार से आपने हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया,

जिस प्रकार से आपने हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में एक कंसैप्ट पैदा करने का प्रयास किया कि इस बजट में कुछ नहीं है, यह बजट तथ्यों पर नही है और यह बजट केवल शब्दों का हेर-फेर है। It is gimmicks of words and figures. यह सब आप लोगों ने बाहर जा कर मीडिया को बाइट्स दी हैं और यहां पर खड़े होकर ड्रामा किया है। हम लोग क्या बेवकूफ हैं? चुनावी वर्ष में हम बजट दे रहे हैं और यदि इसे हम इम्पलीमेंट नहीं करेंगे तो किस मुंह से लोगों से वोट मांगेंगे? ...व्यवधान... हम आपके सामने कर के दिखाएंगे। पहले भी करके दिखाया है और आगे भी कर के दिखाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसकी माननीय प्रधान मंत्री जी ने पीठ थपथपाई है। कोरोना काल में पूरे देश में यदि किसी प्रदेश का सबसे अच्छा प्रबंधन रहा है तो वह हिमाचल प्रदेश का है। Himachal Pradesh has come out as a warrior of Corona. हम जीत कर आए हैं और आपकी तरह हमने इसका मुकाबला पोलियो समझ कर नहीं किया, हमने इस महामारी का, जिसने पूरी दूनिया में कहर मचा दिया, उसका हमने पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया है। आपकी तरह हमने फर्जी बिल बनाकर हाइकमान को नहीं भेजे हैं कि इतने करोड़ रुपये का खर्चा आ गया है और उसे वापिस दे दीजिए। हमने वास्तव में ग्राउंड में जा कर काम किया है, मास्क बांटे हैं, रोटियां बांटी हैं, दवाइयां बांटी हैं और एक-एक व्यक्ति को मिलने के लिए घर-घर गए हैं। आपको हिमाचल की जनता वोट क्यों डालेगी, क्या आप हिमाचल की जनता को बेवकूफ समझते हैं? आप लोगों के पास दिल्ली में रह क्या गया है? कभी 460 सांसद होते थे आज केवल 55 बचे हुए हैं और अगली बार तो ये भी उड़ जाएंगे। आपको हिमाचल की जनता वोट क्यों देगी, क्या हिमाचल की जनता बेवकूफ है कि आपको वोट डालेगी। आपको वोट डालकर उन्हें मिलेगा क्या? आपसे उन्हें भ्रष्टाचार मिलेगा, आपसे उन्हें प्रदेश का बेड़ागर्क मिलेगा और इस बात को जनता अच्छे से जानती है कि किसे वोट डालना है और किसे नहीं, किसके माध्यम से विकास होगा व किसके माध्यम से प्रदेश आगे बढ़ेगा। ...व्यवधान...

07-03-2022/1550/ए.जी.-एन.जी. /3

माननीय सदस्य राणा जी उप-चुनावों में जीत से आप हवा में उड़ गए और हमने उससे सीख ली है। हम नीचे आ गए और आप ऊपर उड़ गए। अभी तो आपके मध्य मुख्य मंत्री पद के लिए 20-20 का वर्ल्डकप शुरू होगा।

हिमाचल प्रदेश की जनता को इस प्रकार का भाषण देकर, इस प्रकार से गुमराह करके, जी.डी.पी. में कौन सी छड़ी घुमा दी, नलके कहां पर लगा दिए, ये आपने क्या कर दिया आदि-आदि बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिमाचल प्रदेश की जनता सब भली-भांति जानती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी को कहना चाहता हूं कि you are like a younger brother to me. आपको मैं बधाई देना चाहूंगा और जिस प्रकार से आपने कल कहा कि मेरे परिवार के पास 20 सीटें हैं। 17 सीटें मण्डी लोक सभा क्षेत्र में हैं, एक आपकी अपनी सीट है, एक आप अपनी पैत्रिक सीट रोहडू और एक आप पैत्रिक सीट रामपुर मानते हो। क्या आपकी अपनी कोई अलग पार्टी है? आपकी कांग्रेस-बी है या कांग्रेस-सी है। ...व्यवधान...

श्री विक्रमादित्य सिंह : आपने मेरे परिवार के बारे में बात की थी इसलिए मैंने आपको आइना दिखाया था।

वन मंत्री : मुझे आइना दिखाने वाले आप अभी पैदा नहीं हुए हैं। ...व्यवधान... माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी आपके ई.डी. के केस की सारी कॉपियां मेरे पास हैं। ...व्यवधान... इसमें आप Accused Number-9 हैं। ...interruption... You are an accused person.

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

07.02.2022/1555/JS/AG/1

वन मंत्रीः-----जारी-------

आप अपनी खलड़ी में रहिये। ...व्यवधान... मुझको पता है, मैंने कहां पर रहना है। किस खलड़ी में रहना है, मुझे पता है। You are an accused in ED case. होश में रहिये। ...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, I am not giving you certificate. The ED will give you certificate. They have already given you the certificate. I don't want to give you any certificate. मैं इसके ऊपर सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता। अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...देखो, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। ...व्यवधान... विक्रमादित्य जी, मैंने आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। आप मेरी बात को समझें और न ही मैंने ई.डी. से सर्टिफिकेट लेना है कि किसी बात की चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगा है। ...(व्यवधान)...मेरे भाई, आप जमानती आदमी हो, चुप रहो। आप यहां पर जमानत में आये हुए हैं। अभी भी ये लोग रजवाड़ाशाही में ही रहते हैं ...(व्यवधान)... इतना highhandedness behaviour, अभी भी रजवाड़ाशाही आपके अन्दर भर-भर कर बोल रही है। हिमाचल प्रदेश के लोग भली-भांति जानते हैं कि ऐसे लोग आएंगे तो हिमाचल प्रदेश का क्या करेंगे और ये लोग किस तरीके से हिमाचल को लूटेंगे। यह कार्पोरेशन भी आपने ही as a shadow मंत्री के रूप में चलाई हुई है। आपने ही इसको लूटा है और आपने ही इस तरीके से एक्साइज का बेड़ागर्क किया है। आप मेरा मुंह मत खुलवाएं।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट जो आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने यहां पर पेश किया, यह ऐसा बजट है जिसने हर वर्ग को हाथ लगाया है। छोटे-से-छोटा आदमी और गरीब-से-गरीब आदमी यानि उस व्यक्ति का ध्यान रखा गया जिसके बारे में कोई नहीं सोचता था।

जहां मैं श्री जय राम ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा वहीं पर आपके माध्यम से सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा कि जो करोना की लड़ाई और जिस तरीके से आपने हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे हिन्दुस्तान में रोशन किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

07.02.2022/1555/JS/AG/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी बैठ जाएं प्लीज।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, स्व0 राजा वीरभद्र सिंह जी 14 बार जीते और 6 दफा ...(व्यवधान)...वन मंत्री जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी पहली बार विधान सभा में आए हैं ...(व्यवधान)...आप प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आपसे हम यह उम्मीद नहीं करते कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें। जिस ढंग से आपने बोला ...(व्यवधान)... हमला कर देंगे, मैं एक बात कह देता हूं कि इस हाउस के सारे मैम्बर्ज़ अपनी-अपनी खलड़ी में रहें अभी 6 महीने में चुनाव आ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

07.02.2022/1555/JS/AG/3

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री राम लाल ठाकुर (नैना देवीजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 4 मार्च, 2022 को बजट प्रस्तुत किया, मैं उसके ऊपर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी गर्म और नरम वातावरण में बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने यहां पर रखीं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि गर्मी और नरमी आने के बाद भी आप लोग काफी संयम से बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर बजट पेश किया है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ कि **"हमने इतनी चुनौतियों के बावजूद भी जन-आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए प्रगति की अभूतपूर्व गाथा लिखी है** और आज हमारा प्रदेश विकास के मार्ग में आगे चल रहा है"। आगे बड़े सुन्दर शब्दों में और कहा कि " **सेवा और सिद्धि के, चार साल समृद्धि के**"

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

07.03.2022/1600/SS-AS/1

श्री राम लाल ठाकुर क्रमागत :

और अगले पेज पर जाएं तो वहां पर ये इंगित किया गया है कि सरकार संकल्पों व शक्ति के साथ इस प्रदेश को आगे लेकर गई है। ईमानदारी और कार्यक्षमता के साथ आगे गई है। परन्तु मुख्य मंत्री जी जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, आप अपने मंत्रिमंडल से दिल पर हाथ रखकर पूछो कि जो आपने लिखा है और चाहा है तथा जो आप संदेश प्रदेश के लोगों को देना चाह रहे हैं क्या हमारे साथी उसमें खरे उतरे भी हैं या इसमें कितने साथी हैं जिन पर आपके कहे अनुसार शब्द फिट नहीं होते? आपने यहां पर बजट भाषण दिया, सबने कहा और आपने भी कहा; यहां पर कर्जों की बात आई। हमारी तरफ से भी कहा गया कि आपने कर्जे उठाकर रिकॉर्ड बना दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपने यह दृष्टि पत्र हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया था तो उसका नाम बदल गया, कहीं पर इसका नाम दृष्टि पत्र से बदलकर संकल्प पत्र हो गया।

(कर्नल इन्द्र सिंह, माननीय सभापति पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय, संकल्प का अर्थ है कि मैं भगवान् को हाज़र-नाज़र रखकर कसम खाता हूं कि जो हमने वायदे किए हैं हम उनको पूरा करेंगे। ये दृष्टि पत्र या संकल्प पत्र चार सालों में प्रदेश के लोगों ने देख लिया कि हर साल नए-नए नाम से लुभावने नारे देकर आता है। मुख्य मंत्री जी ने अपना पांचवां बजट प्रस्तुत किया है, उसमें हम कितने खरे उतरे हैं, कितना क्या हुआ है, वह पता लग जाएगा। जो ये कर्जों की बात करते हैं उसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये कर्जे किस सरकार ने नहीं उठाए। माननीय शांता कुमार जी ने भी लिए थे। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी दो बार मुख्य मंत्री रहे तो उन्होंने भी कर्ज लिए थे। क्योंकि काम चलाना है तो माननीय वीरभद्र सिंह जी के समय में भी कर्जे लिए गए। जो प्लानिंग कमीशन है और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के आदेश हैं उसके मुताबिक कुछ परसैंटेज में प्रदेश को कर्जे लेने की इजाज़त है। तो हर मुख्य मंत्री और सरकार ने कर्जे लेकर प्रदेश को चलाया है। परन्तु सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप यह

07.03.2022/1600/SS-AS/2

बताएं कि जब आपने यह संकल्प पत्र/दृष्टि पत्र लोगों के सामने दिया था तो आपने पब्लिक में जाकर यह कहा कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने कर्जे बहुत ले लिए लेकिन हम प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाएंगे और कर्जे नहीं उठाएंगे।

सभापति महोदय, अगर आज हम इस बजट को देखें तो 2021-22 के जो संशोधित अनुमान हैं उसमें ये कहा गया कि 2078 करोड़ रुपये का सरप्लस राजस्व प्रदेश को आया है। राजस्व व्यय 37034 करोड़ रुपये रहने का अनुमान पेज नं0 68 और 209 के ऊपर दर्शाया गया है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आपको राजस्व सरप्लस हो रहा है, आपकी जी0डी0पी0 ऊपर आ रही है तो फिर आपको ये रिकॉर्ड तोड़ कर्ज उठाने की ज़रूरत क्या पड़ी है? अभी मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट में हम 100 रुपये में से कितने रुपये विकास पर खर्च करेंगे? 100 में से सिर्फ 29 रुपये और उसके अंतर्गत अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। अब 2022-23 के लिए 51365 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है।

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2020/1605/केएस/एएस/1

श्री राम लाल ठाकुर जारी---

कुल राजस्व प्राप्तियां 37,312 करोड़ रुपये की दर्शाई हैं और वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार फिर कहा गया है कि 278 करोड़ रुपये का राजस्व सरप्लस अनुमानित है। सभी जगह सरप्लस, सरप्लस हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो आज हिमाचल प्रदेश में जो बजट दिया है, इसमें वर्ष 2022-23 के लिए 40278 करोड़ रुपये अनुमानित हैं जो हमारा खर्चा आएगा और उसके ऊपर राजस्व प्राप्तियां आपने 36,375 करोड़ रुपये बताई हैं। यह जो 3,903 रुपये का गैप बच गया है, क्योंकि हमारी प्राप्तियां कम हैं, खर्चे ज्यादा हैं, मौजूदा साल में भी आंकड़ों में भले ही आपने यह कह दिया कि कर

भी नहीं लगाएंगे तो मैं यह सोचता हूं कि बिना कर्ज लिए हुए यह काम पूरा नहीं हो पाएगा। जो आपने कहा कि प्रदेश को सैंट्रल गवर्नमैंट ने पैसा दिया, मैं यह जानना चाहूंगा कि कुल मिलाकर यह जो 9602 करोड़ रुपये का घाटा है, पिछले वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने कितना पैसा केन्द्र से लाया? सरकार के प्रबन्धन की जो इन्होंने बात की है, उसमें यह कहा गया कि यह घाटा केन्द्र सरकार के सहयोग से और वित्त प्रबन्धन से पूरा किया जाएगा। सभापति महोदय, यह जो इतना ज्यादा गैप बचा है, जिसको पूरा करना है, प्रदेश को आगे चलाना है, उसमें चोर दरवाजे से लोगों के ऊपर टैक्स लगेंगे। यह ये नहीं कह रहे हैं लेकिन चोर दरवाजे से जो टैक्स लगेंगे उससे प्रदेश की जनता और भी दुखी होगी।

सभापति महोदय, इस बजट में अतिरिक्त सहायता की बात भी की गई है कि चालू वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता मिली है और यह पूंजीनिवेश हुआ है। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है और चिन्हित कामों को छः महीने के अंदर-अंदर पूरा करेंगे। सभापति महोदय, इन कामों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है।

07.03.2020/1605/केएस/एएस/2

ये जो कार्य हैं और जो कार्य हो सके हैं इनके बारे में सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि बिना कर लगाए हमारा काम नहीं चलेगा। केन्द्र से आपको मदद नहीं मिलेगी। केन्द्र सरकार वहां पर मदद देती है जहां पर चुनाव होते हैं और वह मदद यू.पी. में भी मिली है। यू.पी. में क्या होगा, यह अभी 10 तारीख़ तक भविष्य के गर्भ में है। बाकी राज्यों में क्या होगा, यह भी पता लग जाएगा लेकिन हिमाचल प्रदेश में शुरूआत हुई है। बाई इलैक्शन का रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार मंहगाई रोकने में और रोज़गार मुहैया करवाने में बिल्कुल विफल रही है। आज जितनी कीमतें बढ़ी हैं, किसानों का हाल बुरा हुआ है, उसमें मैं कहूंगा कि लोग यह समझ चुके हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। सभापति महोदय, पार्लियामेंट की एक और तीन विधान सभा की सीटें जो हम जीतकर आए हैं, लोग कांग्रेस पार्टी को इसके लिए

मुबारकवाद तो दे ही रहे हैं लेकिन यह जो सरकार बैठी है मैं इनसे कहना चाहूंगा कि शुरुआत हिमाचल के लोगों ने कर दी है। पिछली बार भी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब कांग्रेस पार्टी जीतकर आई थी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

07.03.2022/1610/av/dc/1

श्री राम लाल ठाकुर ----जारी

तो पूरे भारत वर्ष में उसका डंका बजा था और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक तौर पर बल मिला था। अभी यहां पर जल शक्ति मंत्री जी नहीं बैठे है। अगर सिंचाई और पीने के पानी की स्कीम्ज की बात की जाए तो इसका प्रदेश में एक ही मंत्रालय है। इस मंत्रालय द्वारा जिन-जिन स्कीमों को पैसा दिया गया है और जिन-जिन स्कीम्ज को आगे लाने के लिए कहा गया है; मैं उनके बारे में यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये सभी स्कीम्ज एक साल में पूरी हो जाएगी? आपकी पुरानी स्कीम्ज नहीं चल रही है, पुरानी स्कीम्ज की मोटर्ज दो-दो वर्षों से खराब पड़ी हैं जिसके कारण उनसे पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जगातखाना-तनबोल स्कीम माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में शुरू हुई थी और उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया था। पिछले चुनाव आने पर उसकी सड़क के किनारे आधारशीला रखी गई थी कि तनबोल-जगातखाना को सिंचाई का पानी मिलेगा। मगर वह स्कीम आज तक पूरी नहीं हुई है। पहले इसको जून महीने में पूरी करने के बारे में कहा गया था, मगर अब अगला जून महीना आने वाला है। मुझे लगता है कि उसका काम अगले जून माह तक भी पूरा नहीं होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दामीघाटी के लिए यू0एस0ए0आई0डी0 की मदद से एक स्कीम बनाई गई थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि दो-दो वर्षों तक कोई स्कीम खड़ी रहे और उसकी रिपेयर के लिए पैसा न मिले। इसी तरह से कोठीपुरा की स्कीम है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही गम्बर नदी से छड़ोल पंचायत के दो-तीन गांवों को पानी उठाकर दिया गया मगर वहां कोई पानी नहीं

पहुंचा। उसमें कारण यह है कि वहां जो भी इंजीनियर आता है वह नई बात करता है। एक इंजीनियर यह कहता है कि इसका राइजिंग मेन ठीक नहीं है। इस राइजिंग मेन की पाइप मोटी होनी चाहिए और फिर दूसरा इंजीनियर आता है और कहता है कि नहीं, छोटी होनी चाहिए। वहां न मोटी पाइप से पानी गया और न ही छोटी पाइप से पानी गया; फिर सरकार का कहना है कि हमें किसानों की इंकम दोगुनी करनी है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में सेब या दूसरे फल उत्पादकों की अपनी जगह है। होर्टिकल्चर के

07.03.2022/1610/av/dc/2

क्षेत्र में सरकार को जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए; वह हम नहीं दे पा रहे हैं। यहां इस बारे में माननीय सदस्य श्री रोहित ठाकुर का एक प्रश्न लगा था। यहां जिस प्रकार से उसका उत्तर दिया गया तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि उस प्रकार से पलस्तर करने की जरूरत नहीं है। यह रिकॉर्ड है कि एक या डेढ़ वर्ष पहले यहां बेमौसमी बर्फ या बारिश हुई थी जिसके कारण लोगों की फसलें व सेब के पेड़ टूट गए थे; उनके बारे में आज की तारीख में कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यहां पर किसी के ऊपर लांछन लगाने वाली बात नहीं कह रहा हूं। आप खुद देख सकते हैं कि जो किसानों को बूटे दिए जा रहे हैं वे किस कीमत पर दिए जा रहे हैं। पहले जो बूटा सौ रुपये में मिलता था आज वह डेढ़-डेढ़ सौ रुपये में मिलता है। आज बाजार में फंगीसाइड और पैस्टीसाइड भी नहीं मिल रही है। वर्तमान में खाद की कीमत भी बढ़ा दी गई है। खाद की बोरी का वजन 50 किलोग्राम से घटाकर 40-45 किलोग्राम कर दिया है और कीमत बढ़ा दी गई है। अब आप बताएं कि हम किसानों को क्या दे रहे हैं? केवलमात्र अच्छे भाषण देने से बात नहीं बनती। यह कहना कि हिमाचल प्रदेश फल उत्पादक राज्य है इसलिए इस ओर ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। अगर वास्तव में देखा जाए तो प्रदेश में किसानों-बागवानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस बजट में मक्की और गेहूं का भी जिक्र आया है और यह कहा गया है कि मक्की के बीज पर पहले सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये मिलते थे तथा इस बार उस राशि को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।

टी सी द्वारा जारी

07/03/2022/1615/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री राम लाल ठाकुर ... जारी

सभापति जी, उस फसल की कीमत थ्रो-वे प्राइस पर ली जा रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। पिछली बार मक्की की 5 किलोग्राम की बोरी किसान को मु0 950 रुपये में मिली थी और किसान की मक्की मु0 1600 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिकी है। क्या इससे किसान की दोगुनी इनकम हो जाएगी। ऐसा ही हाल गेहूं का है। विभाग कहता है कि आप गेहूं ऊगाओ और बीज के लिए हम आपकी गेहूं खरीदेंगे। मैं अपने जिले की बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंजाब के बॉर्डर के ऊपर एक मजयारी गांव है। उनको कहा गया कि आप अपनी फसल किसान भवन, बिलासपुर लेकर आओ और वहां पर आपकी गेहूं खरीदी जाएगी। लेकिन वहां उनको कहा गया कि आपके 40 क्विंटल बीज में से 5 क्विंटल बीज ही ठीक है और 35 क्विंटल बीज खराब है। यह बीज कृषि विभाग ने पैदा करवाया था और बीज भी उन्होंने ही दिया था। अब मान लो बीज ठीक नहीं निकला तो किसका कसूर है? आज कहा जा रहा है कि कोरोना काल में हमारी जी0डी0पी0 बढ़ गई है। कोरोना के समय में जो दुःख पहुंचा है, वह सबको पहुंचा है लेकिन हमारे किसानों ने हमें नीचे नहीं गिरने दिया। इसके लिए मैं उनको मुबारिकबाद देना चाहता हूं परंतु इसके लिए भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हैं। आप मक्की का 5 किलोग्राम बीज मु0 950 रुपये में दे रहे हैं, किसान पत्थरों से लड़कर सूखी जगह में दालें और सब्जियां पैदा कर रहा है लेकिन हम आज उसको क्या दे रहे हैं, इस बारे में में भी विचार करना चाहिए। जो हम बजट बुक में लिखते हैं, इसमें जमींन और आसमान का फ़र्क है। सभापति महोदय, मैं पशुपालन विभाग के बारे में भी बात करना चाहता हूं। यहां पर अभी मंत्री जी नहीं बैठें हैं, लेकिन उनके साथी मंत्री बैठें है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इतनी गऊओं और भैंसों को इंजेक्शन लगाएंगे। मुझे विभाग के ही डॉक्टरों ने बताया कि हम गाय और भैंस को जो इंजैक्शन लगाते हैं उसको बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और कहा जाता है कि इस गाय के बछड़ी ही होगी बछड़ा नहीं होगा। अगर हम इस तरह का इंजैक्शन लगाएंगे कि गाय जो बच्चा देगी वह फीमेल होगी और मेल नहीं होगा तो क्या इससे इनबैलेंस नहीं होगा। यदि

गाय बछड़ा देती है तो उनको फॉर्मों में रखें और जो सीमन आप बाहर से मंगवा रहे हैं, वह यहीं पर उपलब्ध हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज सिवाय पहाड़ों के कोई देसी गाय किसी के पास नहीं है। सभी के पास जर्सी या अन्य किस्म की बड़ी-बड़ी गायें हैं। यहां पर कहा गया कि हमने 20 हजार पशुओं के लिए शैड बना दिए, उनके लिए सैंक्चुअरीज बना दी । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं

एन0एस0 द्वारा जारी ...

07-03-2022/1620/NS/HK/1

श्री राम लाल ठाकुर .....जारी

और यहां पर मेरे बिलासपुर के विधायक साथी बैठे हुए हैं तथा आप इनसे पूछो कि बिलासपुर शहर में कितनी गायें हैं जो ऐसे घूमती हैं? बिलासपुर शहर में जो कचरा इकट्ठा होता है उसको खातीं हैं और वहीं घूमती रहती हैं। सभापति महोदय, बिलासपुर शहर में 100 से ज्यादा गायें और बैल सड़क के किनारे पर हैं। आप मुझे यह बताएं कि क्या विभाग ने जो काम चलाए हुए हैं वे काफी हैं। हम इनको गौ माता कहते हैं लेकिन इनको डंडे मारने वाले कौन हैं? गाय जब दूध देती है तो गौ माता है और जब गाय दूध नहीं देती तो उसको डंडा मार कर सड़कों के किनारे छोड़ देते हैं तथा इधर-उधर घूमते हुए कभी ट्रक के नीचे आ रही है, कभी बाघ खा रहा है और कभी इनकी टांगें टूट रहीं हैं। सभापति महोदय, इसके लिए भाषण ही ठीक नहीं है बल्कि कुछ करना भी पड़ेगा।

सभापति महोदय, सरकार ने इन गऊओं के लिए अब दूसरी बार शराब के ऊपर टैक्स लगाया है। पहले आपने एक रुपया प्रति बोतल लगाया था और अब 2 रुपये प्रति बोतल टैक्स है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो यह पैसा इकट्ठा हुआ इसको आपने किस अनुपात में बांटा? क्या इससे गौ सदनों की मदद हुई? सरकार ने यह भी कहा था कि जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं वे एक-एक गौ सदन चलाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह काम पूरा हो गया और क्या मंदिरों के ट्रस्ट से गऊओं के लिए आगे कार्यक्रम चलाया? सभापति महोदय, सरकार की करनी और कथनी में बहुत अन्तर है।

सभापति महोदय, यहां पर गैस सिलेंडर के बारे में भी कहा गया कि जिसके पास एक गैस सिलेंडर है उसको एक और सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा और जिसके पास दो सिलेंडर हैं उसको तीसरा सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गैस की कीमत को कौन कंट्रोल करेगा? मैं यहां पर रिकोर्ड के अनुसार बोल रहा हूं। डॉ0 मनमोहन

सिंह जी के समय में गैस सिलेंडर 372 रुपये में मिलता था और आज यही सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर मिलता है। आप मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं तो आप कब तक मुफ्त देंगे? आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश धुआं रहित प्रदेश होगा। सभापति महोदय, सर्दियों में आग सेकने के लिए लकड़ियां जलानी पड़ेंगी। मुझे आप बताएं कि आज भी गांव के अंदर लकड़ी से चूल्हा नहीं जलाएंगे तो सब्जी, दाल और साग नहीं बनेगा। कागजों में तो आपने बोल दिया कि धुआं रहित हो गया और

07-03-2022/1620/NS/HK/2

प्रधान मंत्री जी ने भी भाषण में कह दिया कि मैं माताओं और बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सर्दियों में ट्राईबल एरिया, अप्पर शिमला और कुल्लू में लकड़ी नहीं जलाएंगे तो सर्दी से कैसे बचेंगे? बिलापुर में सुबह जीरो तापमान हो जाता है क्योंकि गोबिन्द सागर झील से धुंध आती है। वहां पर अगर लकड़ियां नहीं जलाएंगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि करने में और कहने में बड़ा अंतर है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए आप सही ढंग से सोचे।

अब मैं जल शक्ति विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। यहां पर लिखा गया है कि 'जल जीवन मिशन' के तहत 15.79 लाख नलकों के कनैक्शन हिमाचल प्रदेश में दे दिए गए हैं। यह आंकड़ा देने से पहले क्या आपने पता भी लगाया कि हिमाचल प्रदेश में कितने परिवार हैं? मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 14.70 लाख परिवार हैं और आपने 15.79 लाख कनैक्शन दे दिए हैं। ये परिवार कागजों में कहां से बढ़ गए? अभी आगे भी इसका काम चलेगा क्योंकि केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो आज लूटपाट हो रही

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

07.03.2022/1625/RKS/HK-1

श्री राम लाल ठाकुर... जारी

लेकिन इसमें जो लूट-खसोट हो रही है, वह ठीक नहीं है। मैंने विधान सभा प्रश्न में पूछा था कि जो पाइपें बिछाई जा रही हैं उनमें पानी कहां से आएगा? मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा

गया था कि इसी वर्ष पाइपें बिछाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त हो रही है। अगले वर्ष स्कीमों की मरमत करने का कार्य किया जाएगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सूखे नलके लगाने की क्या आवश्यकता है? जिन स्कीमों से गुजारे लायक पानी आ रहा है वहां आप सामुदायिक कनैक्शन्ज दे रहे हैं। मान लो एक परिवार में तीन भाई हैं और वे सब्सिडी लेने के लिए अलग-अलग राशन कार्ड बना लेते हैं लेकिन उनका चूल्हा एक है। उन तीन भाइयों के साथ उनके बच्चे और औरतें भी रह रही हैं। इस तरह एक ही घर में चार-चार कनैक्शन्ज लगा दिए गए जिससे इन कनैक्शन्ज का नम्बर बढ़ गया है। आपने परिवारों को इक्ट्ठा होते हुए भी बांट दिया है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को कुछ नहीं मिल रहा है। यहां पर श्री सुभाष ठाकुर बैठे हुए हैं। इनका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का आई.पी.एच. डिवीजन एक ही जगह है। इन्होंने भी कहा लेकिन इनकी भी किसी ने नहीं सुनी। हमारे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को क्लब कर दिया गया और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 18 करोड़ रुपये तक के कार्य हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों को दिए जाएंगे लेकिन ये काम हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों को नहीं मिले हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के कार्यों को क्लब करके लुधियाना के किसी ठेकेदार को दे दिया गया और पाइपें बिछाने के लिए उसे अग्रिम राशि दे दी गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। वहां के स्थानीय ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया जा रहा है लेकिन बाहर की कंपनियों को अग्रिम राशि दी जा रही है। माननीय वन मंत्री ने कहा कि 30 प्रतिशत नई प्लांटेशन की जाएगी। पहले दिल्ली की सरकार कहती थी कि हमने इतने प्लांट लगाने हैं और अब हिमाचल की सरकार कह रही है कि इतने प्लांट लगाए जाएंगे। आज प्लांटेशन के लिए ज़मीन कहां है? हम हर वर्ष लाखों-करोड़ों

रुपये के पौधे लगा रहे हैं और जब वनों में आग लगाई जाती है तो वे सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। लोग जंगलों को जला रहे हैं। इसलिए आपको पहले लोगों को जागरूक करना होगा

और उन्हें बताना होगा कि जंगलों को आग से बचाएं। जंगलों की उपयोगिता लोगों को बतानी होगी। उन्हे बताना होगा कि जंगल से हमें आक्सीजन, बारिश और जमीन को नमी मिलती है। हम हर वर्ष वनों में पौधे लगाते हैं। वन विभाग पौधों का सरवाइवल रेट 70 प्रतिशत कहता है लेकिन जमीन में एक भी पौधा नहीं मिलता। वन विभाग को इस पर चैक रखना चाहिए। जो लोग इमारती लकड़ी काटते हैं उन्हें पकड़ना चाहिए। आजकल खैर काटने का समय है। जब इन पौधों की मार्किंग की गई तो मार्किंग करने के लिए पटवारी, कानूनगो, गार्ड और रेंजर गए। एक पेड़ की मार्किंग करने के लिए 292 रुपये रिश्वत ली जा रही है। जब एक्सपोर्ट परमिट लिया जाएगा तो उस वक्त भी पैसा खाया जाएगा। मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि खैर वाले एरियाज में नजर रखी जाए ताकि वहां पर किसानों को लूटने से बचाया जा सके। खैर किसान की जमीन में लगे हुए हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मालिक बना हुआ है। जब खैर के पेड़ों की मार्किंग की जाती हैं तो दोनों विभाग वाले यह कहते हैं कि मार्किंग करने के लिए प्रति पेड़ इतना पैसा देना पड़ेगा। मेरी जानकारी के अनुसार मार्किंग के लिए 292 रुपये देने पड़ते हैं उसके बाद फैलिंग ऑर्डर मिलते हैं।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

07.03.2022/1630/बी.एस./वाई0के0/-1

श्री राम लाल ठाकुर जारी...

मेरे को यह बताया गया कि पहले 292 रुपए कुल मिला करके जमा हुआ, तब आपकी फैलिंग और मार्किंग होगी। सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन रहेगा कि मेरे नैनादेवी में रुलदू मेमोरियल कॉलेज खुला था, यह तब खुला था, जब माननीय शांता कुमार जी हमारे मुख्य मंत्री हुआ करते थे। रुलदू मेमोरियल कॉलेज इसलिए खुला क्योंकि रुलदू राम जी आदरणीय शांता कुमार जी के जानने वाले थे। यह सभी का होता है कि मित्रता है तो किसी-न-किसी तरीके से मदद की जाए। जब पंजाब में हालात बिगड़े थे तो वे सेफ जगह

चाहते थे, इसलिए नैनादेवी में जमीन ट्रस्ट के नाम हुई, ट्रस्ट ने फिर वह जमीन रुलदू नाम मेमोरियम कॉलेज को दे दी। वहां पर कॉलेज चला और फिर बाद में उन्होंने लिख करके दे लिया कि हम कॉलेज नहीं चला सकते या मंदिर से हमारी मदद की जाए। जब वहां पर माननीय वीरभद्र सिंह जी ने डिग्री कॉलेज दे दिया तो मुझे यह बताइए कि जो रुलदू राम मेमोरियल कॉलेज है, उसके स्टाफ को किस रूप में टेक ऑवर किया गया? या तो सरकार रुलदू मेमोरियल कॉलेज को अपने अधीन ले लेती, तो यह हो सकता था, परंतु वह सरकार ने अपने अधीन नहीं लिया। रुलदू मेमोरियल कॉलेज भी चला और सरकारी डिग्री कॉलेज भी चला। इसके स्टाफ के लोग टेक ओवर कर लिए गए। जिसे आपने जमीन टैंपल ट्रस्ट से दिलाई और लीज पर दिलाई, जब यह छोड़ करे चला गया तो उनके स्टाफ के लोगों को शिक्षा विभाग में रखा गया।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, अभी ग्यारह माननीय सदस्य ओर बोलने वाले हैं।

श्री राम लाल ठाकुर : मैं कर्मचारियों की ओल्ड पेशन स्कीम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे पास यह लैटर है, इसे सूचना के अधिकार द्वारा हमने ले रखा है। केन्द्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकार कदम उठाए। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उन्हें लैटर लिखा था और उन्हें बधाई भी दी और कहा कि आपका जो मसला है, वह हमारे विचारधीन है। अब आपने कमेटी बना दी है। कमेटी उस विषय पर बनाते हैं जो काम सरकार को नहीं करना होता है, जिसे करना हो उसकी कमेटी नही बनती है। धर्मशाला में क्या हुआ? आपने

सवर्ण आयोग बनाया, मुझे बताइए कि संविधान को आगे रख कर सवर्ण आयोग से कुछ हासिल होगा? इस हिमाचल प्रदेश में आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने रापूत बोर्ड, ब्राह्मण बोड और गद्दी बोर्ड भी बना था। ये सारे अलग-अगल बनाए थे। अब आपका यहां पर राजपूत बोर्ड बना हैं, तो आपको सवर्ण आयोग बनाने की क्या जरूरत है? यहां पर हजारों नौजवान साथी आए, उन्हें आपने पानी तो नहीं पिलाया, लेकिन पानी मार करके भगाया।

उनके ऊपर पुलिस बल भी प्रयोग हुआ। लेकिन क्या कारण है कि उनके बारे में सरकार उल्टा रवैया अपनाए हुए हैं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, जिन्हें में इस माननीय सदन में रखना चाहता था।

मैं एक बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि यहां पर कहा गया कि ए0एन0एम0 और स्टाफ नर्सिज हैं, वे इतनी ट्रेंड हैं और इतनों को भरा जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जिला अस्पताल हैं, मैं बिलासपुर का उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां पर 150 बिस्तरों का अस्पताल है। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, तो मैंने जोनल सिस्टम चालू किया था, उस समय एक जोन मण्डी बना था, एक धर्मशाला बना था और एक शिमला बना था। जब आगे आपकी सरकार आई तो आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने और उन्होंने हर जिला का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिल को जोनल अस्पताल बना दिया।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

07-03-2022/1635/वाई.के.-एन.जी. /1

श्री राम लाल ठाकुर ..... जारी

आज मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि नर्सिस की सैंक्शन्ड स्ट्रैंथ जो पहले थी वही आज है बल्की आज पेशंट बहुत बढ़ गए हैं। आज उनको ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा है, आज उन्हें छुट्टियां भी नहीं मिल रही हैं, उनकी स्ट्रैंथ वही है जो 30 साल पहले थी, आज के समय में पेशंट बढ़ गए हैं, आपने अस्पताल का दर्जा भी बढ़ा दिया है, बैड की संख्या भी बढ़ गई हैं, इस सबका मतलब यही है कि पैरा मैडिकल स्टाफ की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। यहां पर 500 डॉक्टर्ज़ लगाने की बात कही गई है लेकिन पैरा मैडिकल स्टाफ जोकि एक अस्पताल को सही मायने में चलाता है उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रखी है कि हम उन्हें लगाएंगे लेकिन मेरा यह निवेदन है कि आपके अस्पतालों में जो सैंक्शन्ड स्टाफ है उसके ऊपर आप नज़रसानी करें। जहां पर आज 20 नर्सिस की पोस्टें हैं वहां पर 40 की जरूरत है लेकिन आप उनकी संख्या को नहीं बढ़ा रहे हैं। कृपया करके इनकी संख्या को बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, बजट में जो है उसके बारे में तो यहां पर सभी ने बोला है, मैं भी बोलूंगा कि ये झूठ का पुलिंदा है तो ये आप अपने दिल से पूछ लीजिए कि ये क्या है, चुनाव आ गए हैं और चुनाव के लिए आपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यह बजट पेश किया है और मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

07-03-2022/1635/वाई.के.-एन.जी. /2

सभापति : अब मैं इस चर्चा के लिए माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी को आमंत्रित करता हूं।

डॉ0 राजीव बिन्दल (नाहन) : सभापति महोदय, आपका आभार क्योंकि जो बजट माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया उस पर अपनी बात कहने के लिए समय दिया। दिनांक 04-03-2022 को जो बजट प्रस्तुत हुआ उस पर मैं अपनी बात इस माननीय सदन में रखुंगा। सभापति महोदय, लगातार हर वर्ष सरकार और सरकार के वित्त मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करते हैं, बजट के ऊपर चर्चा होती है, सत्तापक्ष उस बजट को प्रस्तुत करने पर माननीय मुख्य मंत्री व माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता है और प्रतिपक्ष उस बजट के अंदर कमियां ढूंढ़ता है व उसका विरोध करने का प्रयास करता है। मुझे भी जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं इसी माननीय सदन में यह 24वां बजट देख रहा हूं। आदरणीय श्री राम लाल ठाकुर जी इस माननीय सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री व वन मंत्री भी रहे हैं, पांच बार से माननीय विधायक हैं, ये अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके व लहजे से कहते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रतिपक्ष में हैं इसलिए इनके लिए वह रस्म निभाना जरूरी है। अंत में इन्होंने कह ही दिया कि मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि इस बजट में कुछ नहीं है लेकिन मैं इसका विरोध अवश्य करूंगा।

सभापति महोदय, मैं आज एक बात बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने इस माननीय सदन में 24 बजट देखे हैं और हर बजट में कुछ-न-कुछ खूबी रहती है। वह बजट चाहे माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने प्रस्तुत किया हो, चाहे माननीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने प्रस्तुत किया हो या पिछले पांच वर्षों से माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया हो। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी हिम्मत इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने दिखाई है वह हिम्मत असम्भव

को सम्भव करने वाली है और हम उनको इसके लिए बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और माननीय वित्त मंत्री के तौर पर इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हैं। अब वह किस बात की बधाई है मैं केवल उन्हीं बिंदुओं पर आउंगा। आज मेरे सामने यहां पर सारे माननीय विधायक मौजूद हैं,

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

07.02.2022/1640/JS/AG/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः-----जारी-----

हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। विकास के कामों के लिए लड़ते हैं। क्लर्क से ले करके मुख्य मंत्री के दरवाजे तक हम लोग जाते हैं कि हमारी सड़क बननी चाहिए,पीने का पानी हमारे इलाके में होना चाहिए, पुल बनना चाहिए और उसके लिए नाबार्ड के माध्यम से हमारी एक किट्टी का निर्धारण हुआ। मुझे अच्छे से याद है कि लगभग वर्ष 1998 के आस-पास नाबार्ड का पैसा विधायक की अपनी किट्टी के माध्यम से यानि एम.एल.ए. प्रायोरिटी के माध्यम से लगना शुरू हुआ। यह बढ़ता चला गया। पिछले चार साल के अन्दर जो इस धनराशि में माकूल इज़ाफा हुआ है, शायद अगर मैं गलत न हूं तो 105 करोड़ रुपये से ले करके 150 करोड़ रुपये तक विधायक प्राथमिकता की धनराशि को श्री जय राम ठाकुर जी ने बढ़ाया है, हम इसलिए इनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। मैंने आग्रह किया कि मेरी किट्टी बहुत पहले खत्म हो गई जिसमें से 135 करोड़ रुपये पिछले वर्ष किया था, 120 करोड़ रुपया उससे पहले था और 105 करोड़ रुपया उससे पहले था। अब 150 करोड़ रुपया विधायक प्राथमिकता का है उसका इतना करना सचमुच में काबिले तारीफ है। इसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई। इसी तरह से विधायक निधि भी जब शुरू हुई थी तो वह 15 लाख रुपये से शुरू हुई थी। वह बढ़ती चली गई जो कि बहुत अच्छा हुआ। पिछले चार साल में वह 1.50 करोड़ रुपये हुई और फिर 1.80 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये हुई। हम कहीं जा रहे हैं तो एक लाख रुपया सड़क के लिए देना है, एक लाख रुपया सामुदायिक भवन के लिए देना है, सामुदायिक भवन में रिपेयर के लिए देना है, महिला मण्डल भवन के लिए

पैसा देना है और बहुत सारी चीजें हमारी सरकार ने, माननीय जय राम ठाकुर जी ने उसमें शामिल की हैं। जो पिछली बार किया वह अभी कांटिन्यू है कि रजिस्टर्ड सैल्फ हैल्प ग्रुप, महिला मण्डल है, उसको आप 50,000 रुपये तक का सहयोग उसके रिवॉल्विंग फंड के लिए, विकास कार्यों के लिए दे सकते हैं। विधायकों की ताकत बढ़ाने के लिए जो कार्य माननीय जय राम जी ने किया, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। मुझे लगता है इसके लिए तो ताली आपको भी

07.02.2022/1640/JS/AG/2

बजानी चाहिए। ....व्यवधान... हर्ष वर्धन जी आप हमारे परम् मित्र हैं। आप मेरे सिरमौरी भाई हैं। ऐच्छिक निधि को बढ़ा करके 12 लाख करना यह भी एक बहुत महत्व की बात है। जब हम स्कूल में जाते हैं, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं वहां पर किसी की बीमारी के लिए पैसा चाहिए, कुछ सहयोग के लिए राशि चाहिए तो 5-10 हजार रुपया विधायक दे पाये, यह बहुत बड़ी बात है। माननीय सभापति महोदय हमारे प्रदेश के अन्दर सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अनेक योजनाएं चल रही हैं। अभी तक सभी मुख्य मंत्रियों ने अपने-अपने समय के अन्दर इन योजनाओं को चलाया है। सभी ने इसको बढ़ाने का भी प्रयास किया। किसी ने 20 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 10,000 रुपये का इज़ाफा किया, किसी ने 20,000 रुपये का इज़ाफा किया लेकिन एकमुश्त जो जबरदस्त इज़ाफा किया, इधर व उधर के विधायक साथियों को अनुमान नहीं होगा कि 70 वर्ष की आयु बिना आय सीमा के पिछली बार की थी और वह एकमुश्त घटा करके 60 वर्ष एक बार में कर दी जाएगी, यह हिम्मत सच में असम्भव को सम्भव करके दिखाने की बात है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

07.03.2022/1645/SS-AG/1

डॉ0 राजीव बिन्दल क्रमागत :

कौन मान रहा है? चुनाव आएगा और जाएगा। ठाकुर साहब, कौन सदन में आएगा और कौन नहीं आएगा वह जनता निर्धारित करेगी। परन्तु एक बात निश्चित है कि आज तक इतनी बड़ी हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। मैं नाहन विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। हमारे पड़ोस में हरियाणा लगता है। हरियाणा में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। जब हम जाते थे तो हमने बोला कि 70 साल तो बोले कि बिल्कुल पड़ोस में मेरा संबंधी है, मेरा रिश्तेदार है तो वहां 60 साल में पेंशन लगती है। हम कल्पना भी नहीं करते थे कि 60 साल के अंदर पेंशन लग जाएगी और 60 साल की उम्र में पेंशन लगाकर जो लाभ प्रदान किया है वह सचमुच में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ लाभ प्रदान करने की बात नहीं है उसको बढ़ा करके कितना किया? विधवाओं, एकल नारी के लिए जो पेंशन है उसको 700 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये कर देना, अपंगता-दिव्यांगता की पेंशन 70 साल से ऊपर वालों को 1100 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये पेंशन कर देना; 65 साल से 70 साल की बहनें जो इस कैटेगिरी के अंदर आती हैं उनके लिए 1000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन कर देना और इतना ही नहीं इस साल 40 हजार पेंशन और ऐड कर देना, ये सच में काबिलेतारीफ़ है। हमारे साथी कई बार कहते हैं कि इम्प्लीमैंट नहीं होगा। 70 साल वाला इम्प्लीमैंट हो गया, बाकी सारे इम्प्लीमैंट हो गए और मेरा विश्वास है कि जय राम जी ने कहा है, उनके साथ राम का नाम जुड़ा है तो ये इम्प्लीमैंटेशन भी तीन महीने के अंदर-अंदर हो जाएगी। 40 हजार पेंशन भी बढ़ जाएगी और 60 साल वाले जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन भी मिल जाएगी। 35 हजार से 50 हजार जो वैल्फेयर स्कीम्ज के अंदर लगने वाली मिनीमम क्वालीफिकेशन है वह भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिटमैंट के साथ काम करने वाली सरकार है। मैं दो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर ज़रूर लाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जो इस बजट बुक के अंदर बताया, इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर 6.35 लाख लोग इस प्रकार की सोशल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और ये

07.03.2022/1645/SS-AG/2

जो वद्धावस्था पेंशन बढ़ जाएगी और जो कैटेगिरीज बढ़ जाएंगी, इसके बाद सोशल पेंशन का आंकड़ा लगभग साढ़े 7 लाख होने वाला है। अगर 75 लाख की आबादी है और यह साढ़े 7 लाख हो रहा है यानी प्रदेश का 10 प्रतिशत मानव ऐसा है जिसको सोशल पेंशन मिल रही है। पूरे भारत के अंदर कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां 10 परसैंट लोगों को सोशल पेंशन का लाभ मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश सेवा और पेंशन के मामले में तथा गरीबी की सेवा के मामले में अग्रणी भूमिका के अंदर आकर खड़ा होने वाला है। मैं इसके लिए भी जय राम ठाकुर की सरकार को बहुत-बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। एक और आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक सोशल पेंशन के ऊपर 450 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है। ये बढ़ करके 1300 करोड़ रुपया यानी तीगुनी राशि इसके अंदर खर्च होने वाली है। अब इसके बाद भी अगर कोई बजट के लिए बधाई न दे तो सच में चिंता की बात है। कहीं-न-कहीं उनको विचार तो करना पड़ेगा कि उनके अंदर नेगेटिविटी का क्राइटेरिया कितना बढ़ गया है।

गौवंश की बात आई कि गौवंश का सम्वर्धन होना चाहिए, गौवंश का संरक्षण होना चाहिए। सालों से सड़कों के ऊपर गौवंश, जिसको बेसहारा गौवंश कहा है, जिसको हमारे प्रतिपक्ष के लोग आवारा गौवंश कहते हैं; अब उस गौवंश के लिए गऊ सैंक्चुअरी बनाने का काम किसने किया, हमारी जय राम ठाकुर जी की सरकार ने किया। सैंक्चुअरी में 20 हजार गौवंश को रखने का काम किसने किया, वह जय राम ठाकुर की सरकार ने किया।

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2020/1650/केएस/एएस/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----

और एक गोवंश के ऊपर 500 रुपये प्रतिमास सहयोग राशि देने का काम पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, जय राम ठाकुर की सरकार ने किया और इस बजट में 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने की घोषण जय राम ठाकुर जी ने

की तो बधाई तो बनती है। हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबका सहयोग चाहिए, गोवंश सड़कों के ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी आवश्यकता है। अगर शराब पीने वाले को एक रुपया और टैक्स लग जाएगा, सभापति महोदय, यहां पर हमारे एक माननीय सदस्य ने एक बात सुनाई कि रात को पीते समय वह थोड़ा छीटा दे कर बोलता है कि मैं गऊ के नाम की पी रहा हूं। सभापति महोदय, हमारी सरकार सेवा करने वाली सरकार है और हमारी सरकार ने सूक्ष्म वर्ग व निर्धन वर्ग की चिंता की है। जो छोटा कर्मचारी है, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मल्टीपरपज़ वर्कर, वाटर कैरियर, पंचायत चौकीदार, रेवन्यू चौकीदार, इस प्रकार का जो छोटा वर्कर है, एक भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसके मानदेय में वृद्धि करके सरकार ने यह बताने का प्रयास नहीं किया कि हम छोटे कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं और उनके मानदेय में माकूल इज़ाफा करके इस बात को कहने का प्रयास किया है कि हम कोविड की भारी तंगी के बावजूद आपके साथ खड़े हैं। इसके लिए भी इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं।

सभापति महोदय, आंगनबाड़ियां मज़बूत होनी चाहिए क्योंकि वहां से बच्चों की नींव डलती है। अगर आंगनबाड़ियों के लिए सरकारी भवन नहीं हैं तो वहां पर वातावरण अच्छा नहीं होता। किराये का आज एक जगह भवन लिया, कल दूसरी जगह लिया, कहीं पर मकान नहीं मिलता तो आंगनबाड़ी बहनें वहां पर अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। 1000 आंगनबाड़ियों को इस बजट के अंदर नए मकान बनाकर देने का जो फैसला

07.03.2020/1650/केएस/एएस/2

किया है, एक बहुत विहंगम प्रयास, अच्छा प्रयास किया गया है और उसके लिए भी हम माननीय मुख्य मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। 6718 मॉडल आंगनबाड़ियां बन चुकी हैं तथा 12,207 आंगनबाड़ियां और मॉडल बनाई जाएंगी, इसके लिए भी हम सरकार को बहुत-बहुत बधाई देते हैं।

सभापति महोदय, पंचायत के प्रतिनिधि जो दिन-रात सेवा करते हैं, पंचायत का प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड मैम्बर, बी.डी.सी. व जिला परिषद का सदस्य, नगर निकायों के सदस्य, कॉर्पोरेशन के मैम्बर, सभी के मानदेय में वृद्धि करना चुने हुए प्रतिनिधियों की दृष्टि से एक बहुत अच्छा फैसला है।बहनें स्वरोज़गार की तरफ आगे बढ़े, उसके लिए सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बन रहे हैं। कोई बी.डी.ओ. के माध्यम से, कोई नाबार्ड के माध्यम से तथा कोई अपने आप प्रेरणा से बना रहे हैं। जो रजिस्टर्ड सैल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, उन सभी को 25 हजार रुपये का एक मुश्त रिवॉल्विंग फंड उनके सहयोग के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। महिलाओं को मज़बूत करने की दिशा में 25 करोड़ रुपये का एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है जिसके लिए भी हम सरकार को बधाई देते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है। सारी दुनिया की भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत के कारण भारत दुनिया का विश्व गुरू रहा। जो संस्कृत पढ़ाने वाले शास्त्री हैं। टीचर के नाते वे पढ़ाते हैं अगर उन्होंने

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

07.03.2022/1655/av/as/1

डॉ0राजीव बिन्दल----जारी

बी0एड0 या टैट किया है तो ऐसे अध्यापकों को टी0जी0टी0(संस्कृत) और टी0जी0टी0(हिन्दी) का दर्जा देना सचमुच में संस्कृत और हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान है। हम इसके लिए भी सरकार को बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को चैंपियन का दर्जा दिया है। कोविड महामारी की वैक्सीनेशन देने में हिमाचल प्रदेश नम्बर एक पर आया। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्व की बात मुझे दिखाई देती है वह आयुष्मान योजना है जिसके अंतर्गत 2.40 लाख लोगों ने 218 करोड़ रुपये का लाभ लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई योजना 'हिम केयर' शुरू की और इस साल के बजट में इसके

लिए बहुत अच्छी घोषणा की गई है। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम उसको कहते रहते हैं कि भाई हिम केयर कार्ड बना लो। मगर वह व्यक्ति नहीं बना पाता क्योंकि कई बार एक गरीब व्यक्ति 1,000 रुपये खर्च करने की स्थिति में भी नहीं होता। इसलिए इस बजट में कहा गया है कि पूरे वर्ष यानी 12 महीनें हिम केयर कार्ड का पंजीकरण चालू रहेगा। इसके लिए भी हम सरकार को बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। यहां पर माननीय ऊर्जा मंत्री बैठे हैं, हम इनको बधाई देते हैं। इन्होंने 60 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट तक 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली और किसानों को 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने की बात कही गई है जोकि प्रदेश में पहली बार हुआ है। हमारी सरकार सचमुच में बधाई की पात्र है। जल जीवन मिशन के संदर्भ में दोनों पक्षों की ओर से बड़े जोर-शोर से चर्चा की जा रही है। यहां पर यह सभी मानते हैं कि कनेक्शन लग रहे हैं। प्रदेश में 8.35 लाख घरों में कनेक्शन लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। प्रदेश में 1,25000 करोड़ रुपये की पांच नई योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखना, सिवरेज की चार बड़ी नई योजनाओं को पूरे करने का लक्ष्य रखना व 7 मल निकासी योजनाओं के ऊपर तेज गति से कार्य करने की बात करने के लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। लेकिन सभापति महोदय, मंत्री जी को

07.03.2022/1655/av/as/2

बधाई देने के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके अंदर नाहन का जिक्र करना बहुत जरूरी था। नाहन जिला हैडक्वार्टर है और यह शहर 421 साल पुराना है। वहां सिवरेज की व्यवस्था नहीं है और इसके लिए हम आपसे लगातार आग्रहपूर्वक कह रहे हैं तथा अभी दोबारा अनुरोध करते हैं कि इस बजट के अंदर आप नाहन सिवरेज सिस्टम का भी प्रावधान करें। आपको बधाई है क्योंकि आपने छोटे-छोटे टाऊन भी सिवरेज सिस्टम के अंतर्गत कवर कर लिए हैं। इसलिए नाहन को भी इस बजट के अंदर लाने की कृपा करें क्योंकि नाहन भी जिला सिरमौर का हैडक्वार्टर है। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय जल शक्ति मंत्री इसी बजट में उसके लिए प्रावधान करेंगे। इसके अतिरिक्त

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में सड़कों का कार्य लगातार होता आया है और आगे भी होगा। लेकिन रीन्यूल कोट करने का जो पहले 5 साल का पीरियड था उसको घटाकर 3 साल करना बहुत ही अहम फैसला है। बर्फ या भारी बारिश से सड़क खराब होने पर जब एक्सियन को सड़क की रीन्यूल के लिए कहा जाता है तो उसका कहना होता है कि मैं कैसे करूं, मेरे पास धनराशि का प्रावधान नहीं है। अब उसको 5 साल से 3 साल किया है; इसके लिए हम सरकार को बहुत-बहुत बधाई देते हैं।

टी सी द्वारा जारी

07/03/2022/1700/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
डॉ0 राजीव बिंदल .... जारी ।

बेरोज़गार युवकों की बात बड़े जोर से कही जाती है और उनके नाम पर राजनीति करना भी बहुत आसान है। यह सच बात है कि जो बेरोजगार है, वह रोजगार ढूंढ रहा है। वह प्राइवेट व सरकारी सेक्टर में स्वरोजगार के अंदर रोजगार ढूंढ रहा है। उनके लिए 'मुख्य मंत्री स्वाबलम्बन योजना' बहुत कामयाब निकली है। इस योजना के तहत 457 करोड़ रुपये का प्रावधान करके लगभग 3000 युवाओं को सीधा-सीधा रोज़गार और 30,000 युवाओं को इन-डायरेक्ट रोजगार मिला है। इस योजना में माकूल धन है। सभापति महोदय, टूरिज्म सेक्टर हिमाचल प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा साधन हो सकता है, यह सभी कहते आए हैं। जब से मैं इस माननीय सदन में आया हूं तब से टूरिज्म की बात होती है। इसके लिए सभी ने प्रयास किया परंतु एक सक्षम प्रयास इस वर्ष के बजट के अंदर दिखाई देता है। एशियन डवलपमेंट बैंक का लगभग 2,121 करोड़ रुपये का जो प्रोजैक्ट है, वह हिमाचल प्रदेश के लिए टूरिज्म डवलपमेंट का एक बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। हम इस प्रोजैक्ट के लिए वर्तमान सरकार को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। इसमें 1000 करोड़ रुपये का पहला चरण और 1060 करोड़ रुपये का दूसरा चरण है। इसमें सिरमौर के बहुत-सारे हिस्से शामिल हैं। नाहन टाउन और चूड़धार का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ए0डी0बी0 को इस प्रोजैक्ट को अतिशीघ्र आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए भी सरकार को

बहुत-बहुत बधाई। इससे सभी माननीय विधायकों के क्षेत्रों के अंदर विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

सभापति महोदय, वॉटर कंजर्वेशन पूरे देश व दुनिया की आवश्यकता है। वन विभाग ने बहुत-सारे अच्छे काम किए, मैं केवल चिन्हित बातों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। वॉटर कंजर्वेशन के लिए 125 वॉटर बॉडीज बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हम चाहेंगे कि हर क्षेत्र में वॉटर बॉडीज बनाएं। वॉटर कंजर्वेशन होने से फॉरेस्ट बढ़ेगा, पशुधन बढ़ेगा और जंगली जानवरों को भी इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस बजट के अंदर सरकार ने एक और नया फैसला लिया है।

07/03/2022/1700/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

चीड़ के जंगल हमें किसी भी प्रकार से रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सभापति महोदय, मैंने यहीं सदन में अपना विषय रखा था कि चीड़ के जंगलों की स्थिति बहुत भयावह है। उसके अंदर से बिरोजा निकालने के बाद उसमें आग लग जाती है। उसमें एक साल में आग लगती है और दूसरे साल वह पेड़ गिर जाता है। तीसरे साल वन विभाग सड़े हुए पेड़ को उठा ले जाते हैं। 40-50 सालों में पेड़ बिरोजा निकालने लायक होता है और वह तीन साल के अंदर खत्म हो जाता है। बिरोजे वाले और बाकी लोगों की मौज हैं लेकिन जंगल का सत्यानाश हो जाता है। मैंने यहां फोटोग्राफ भी दिखाए थे लेकिन किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस सरकार ने चीड़ के पेड़ बदल कर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ लगाने का अच्छा निर्णय लिया है। इसके लिए हम सरकार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। स्वर्ण जयन्ती वर्ष में 75 गांवों को विशिष्ट पहचान देकर उनको पूर्णतः विकसित करके एक अच्छा विलेज बनाया जाएगा।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

07-03-2022/1705/NS/DC/1

डॉ0 राजीव बिन्दल .....जारी

युवाओं के प्रोत्साहन के लिए, उनको नशे से दूर रखने के लिए, उनकी मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने खेल महाकुंभ करने का निर्णय लिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही सरकार खेल के बहुत बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने जा रही है और उसके अंदर सिरमौर जिला के माज़रा का Astroturf Field भी शामिल है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। सभापति महोदय, जब भी कहीं गेम्ज़ होती हैं तो खेलने वाले खिलाड़ी बार-बार यह आग्रह किया करते हैं कि हमारी डाइट मनी बहुत कम है। सरकारों ने पहले भी डाइट मनी बढ़ाने का प्रयास किया और किसी ने 10 रुपये, किसी ने 20 रुपये बढ़ाए। यह जय राम ठाकुर जी की सरकार है जिसने डाइट मनी को 120 रुपये से 240 रुपये बढ़ाया और 200 रुपये से 400 रुपये किया। सच में यह बहुत बड़ा निर्णय है। मैंने पहले ही कहा कि सरकार ने असंभव को संभव करके दिखाया और ये फैसले बहुत कठिन फैसले हैं। डाइट मनी थोड़ी-थोड़ी बढ़ाते हैं तो उतनी देर युवा को वह सब कुछ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, बजट के अंदर एक और निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्र के अंदर अढ़ाई लाख से अधिक जनजातीय लोग रहते हैं। श्रीमती आशा कुमारी जी वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्होंने मेरी बात को सुधारने का प्रयास किया है कि गैर जनजातीय क्षेत्र में अढ़ाई लाख से भी ज्यादा जनजातीय लोग रहते होंगे। इन लोगों के विकास की दिशा के अंदर जो ट्राईबल का बजट है उसका खर्च नहीं होता है। हमने देखा है कि हमारे यहां का ट्राईबल दूरदराज़ में रहता है और उसके लिए सड़क पहुंचाना, बिजली और पानी पहुंचाने की दिक्कत रहती है। पहली बार सरकार ने हिम्मत की है कि गैर जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई और साधुवाद देता हूं।

मैंने पहले ही कहा कि यह बजट गरीब की चिंता करने वाला बजट है। इसके लिए वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 गरीबों को मकान इस साल अलग-अलग मद के माध्यम से दिए जाएंगे। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। अभी हमारे फाज़िल दोस्त ने कहा कि चिकित्सकों के पद बढ़ा दिए। सभी ने बढ़ाए कभी 25 पद कभी 50 पद और कभी 100 पद बढ़ाए परन्तु एकमुश्त 500 डॉक्टरों के पदों को सृजित

07-03-2022/1705/NS/DC/2

करना और इनका बजट के अंदर प्रावधान कर देना सच में बधाई की बात है। इसके लिए मैं, जय राम ठाकुर जी को बधाई देता हूं। 50 नई एम्बुलैंस लाना, पैट स्कैन लगाना और अनेक प्रकार के इक्विपमैंट्स लगा करके अस्पतालों को स्ट्रैंथन करना बहुत सराहनीय निर्णय है। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि किसानों की चिंता करते हुए 11 नई अनाज मंडियां खड़ी करना, 50,000 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के अंदर लाना, महर्षि बाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना, श्रीमती इन्दिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना, डॉ0 भीम राव अम्बेदकर छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना को बढ़ा करके 1500 रुपये महीना करना और सैनिक स्कूलों के बच्चों की छात्रवृत्ति को बढ़ा करके 2000 रुपये करना सराहनीय निर्णय है। भविष्य के हिमाचल की दिशा के अंदर उसको आगे बढ़ाना चाहे यह रेलवे, रोपवे और हवाई पट्टी की दिशा के अंदर हो, मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट गरीब के विकास के लिए गरीब की चिंता का बजट है। इसमें पूरी हिम्मत के साथ अंसभव को संभव करके दिखाया गया है और सच में बधाई के पात्र हैं। 7.50 लाख पेंशन भोगी

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

07.03.2022/1710/RKS/HK-1

डॉ. राजीव बिन्दल... जारी

सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत लोग हिमाचल प्रदेश में ही हैं और इसके लिए मैं श्री जय राम ठाकुर जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं दो-तीन छोटे-छोटे सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी योजनाएं शुरू की हैं और इन योजनाओं को इसी वर्ष आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत भी हैं। कुछ सरकारी अधिकारी कामों को लंबित करने की दिशा में प्रयासरत हैं उनको महत्व देकर कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट लगातार कार्यों को लंबित करने का काम करता है, इस विभाग को भी पूरी तरह देखने की आवश्यकता है। फोरेस्ट क्लीयरैंस के मामलों की परमिशन जल्दी मिले, उस दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है। आर्किटेक्चर वाले भी नक्शे जल्दी से प्रस्तुत करें इसके लिए भी निर्देश देने की

आवश्यकता है। विभागों में आपसी तालमेल की भी बहुत आवश्यकता है। अगर किसी विभाग के पास भूमि बेकार पड़ी है तो उस भूमि को दूसरे विभाग को ट्रांसफर करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्षों तक भूमि हस्तांतरण मामलों में एन.ओ.सी. नहीं मिल पाती। इस दिशा में बहुत सारे उदाहरण देने को है और मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर माननीय मुख्य मंत्री को इन उदाहरणों को प्रस्तुत करूंगा। यह बजट गरीब, बेरोज़गार, किसान और कर्मचारियों के लिए प्रस्तुत किया गया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल चर्चा में भाग लेंगे।

07.03.2022/1710/RKS/HK-2

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना पांचवां और इस सरकार का आखिरी बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट से प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें थी लेकिन जब बजट पेश किया गया तो इसमें शेरो-शायरी के मनोरंजन के अलावा कुछ भी नहीं था। इस बजट में शेरो-शायरी तो खूब हुई लेकिन जब प्रदेश की जनता को भूख लगेगी तो शेरो-शायरी से उसका पेट नहीं भरेगा। इस बजट में प्रदेश हित की बातों को सबसे ऊपर स्थान मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बजट के अनुसार आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिकी काफी प्रभावित होगी। यह वर्ष चुनाव का वर्ष है और हमें यह अपेक्षा थी कि आप चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अच्छी योजनाएं लागू करेंगे। अगर इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डवैलपमेंट, बेरोजगारों के लिए कोई ठोस नीति और कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की होती तो हम आपका धन्यवाद करते। हमने और भी कई बातें माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाई हैं। इस बजट में मुझे कहीं भी financial crunch नजर नहीं आ रहा जिस प्रकार से यह बजट है।

अगर आप इस बजट में ज़िलों की बात कहते तो हम समझते की बजट में कुछ नया है। यह सरकार का पांचवां बजट है लेकिन इससे पहले के जो चार बजट पेश किए गए हैं उनकी कई योजनाएं आज तक लाँच नहीं हो पाई हैं।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

07.03.2022/1715/बी.एस./एच0के0/-1

श्री आशीष बुटेल जारी...

और न ही टेकअप हो पाई है। इन पिछले चार वर्षों में जो criminal wastage of public fund वह भी पिछले चार वर्षों में बहुत ज्यादा हुआ है। अगर हम नेशन हाइवे की बात करें, तो वह भी बजट में होती थीं। मैं कहना चाहता हूं कि जिला कांगड़ा में एक भी इंच नेशन हाइवे पर काम नहीं हो पाया है। आपके विधान सभा क्षेत्र में फोर-लेन से टू-लेन पर आ गया है। कई ऐसे विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं, जहां पर पिछले चार वर्षों से लोक भवन बन रहे हैं या कई जगह ये बनना भी शुरू नहीं हुए हैं। आज प्रदेश में चार हजार के करीब पंचायतें हैं और उन पंचायतों में सूचना पट्ट लगाए गए थे, जिन पर एक अनुमानित खर्चा 50 हजार रुपए के करीब आया था। आप एक भी ऐसी पंचायत बता दें जहां पर वे सूचना पट्ट लगे हों, तो उनमें विधायक निधि पैसा किस पर्पज के लिए लगा, यदि वे इस बात को दर्शाते हों, तो मैं मान जाऊंगा। महोदय, बजट बेहद निराशा जनक तो है ही, परंतु इसमें किसी के लिए कुछ नहीं दिया गया है। बस एक ही बात की जाती है कि पिछले 50 सालों में कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने क्या-क्या काम किए, कितना ऋण इस प्रदेश के लिए छोड़ कर गई। मैं एक चीज आपको याद करवाना चाहता हूं। आप अगर कह रहे हैं कि आज 50 वर्ष हुए हैं, तों उसमें से तकरीब 20 वर्ष तो आपकी सरकारें रही हैं। जब वर्ष 1998 और 2003 के बीच भाजपा की सरकारें रही थीं, उस समय कितना ऋण लिया गया? उसको पहले देख करके आना चाहिए। मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपने दो बार इस मान्य सदन में कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार 28 हजार करोड़ रुपए का ऋण छोड़ करके गई है। यह मुझे नहीं मालूम कि कौन आपको ये गलत जानकारी दे रहा है। आपके ही बजट भाषण

वर्ष 2018-19 में बड़ा साफ लिखा है कि जो पिछली सरकार थी, वह 18 हजार 800 रुपए का ऋण झोड़ करके गई है। आपको पता है कि लोन सब सरकारें लेती हैं। लेकिन अगर हमारी सरकार ने 18,800 करोड़ रुपए का ऋण लिया था उसमें काम भी किया था capital outlay उस हिसाब से हुआ। उस समय capital outlay पर खर्चा होता था, वह तकरीबन 50 प्रतिशत कम-से-कम जो ऋण लिया जाता था उस पर होता था। आज क्या स्थिति है?

07.03.2022/1715/बी.एस./एच0के0/-2

आज आप बात कर रहे हैं कि 12 हजार 530 करोड़ रुपए का आप और ऋण लेने जा रहे हैं। महोदय, उस पर capital outlay कितना लेंगे? 12,000 करोड़ रुपए में से विर्फ 5600 करोड़ रुपए ऐसा होगा, जिसे आप इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्य में इस्तेमाल करेंगे। यह जो आंकड़ा इस बार 5600 करोड़ रुपया है, वह पिछली बार 7,000 के करीब था, उसे भी इस बजट में कम कर दिया गया है। यह भी बात सामने आनी चाहिए कि जो capital outlay इस बजट में है। वह 1500 रुपए से कम हुआ है। आपने 12,500 हजार करोड़ रुपए की राशि लिखी है तो इससे यह लोन बढ़ने वाला है और यह अनुमानित कर्ज वर्ष 2022-23 में 18,000 से 20,000 तक पहुंच जाएगा। आज की तारीख में cumulative debt यानी कुल जोड़ जो हमारे ऋणों का है वह 70,000 करोड़ रुपए मार्च, 2022 तक पहुंच जाएगा। आप एक चीज याद रखें कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता से गई थी, उस समय यह 46,385 करोड़ रुपए था। आज वह 70,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि 23,000 से 24,000 करोड़ रुपए ऋण आपकी सरकार में लिया गया है। पांच सालों में जब तक आप जाएंगे, आप सत्ता में आने से गए, यह प्रदेश की जनता जानती है, लेकिन जब आप कुर्सी छोड़ करके जाएंगे तब तक आप प्रदेश को 30-35 हजार करोड़ रुपए ऋण में डुबो करके जाएंगे।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

07-03-2022/1720/वाई.के.-एन.जी. /1

श्री आशीष बुटेल..... जारी

यह आपकी ही किताबें बोल रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरा, हम राजस्व प्राप्तियां की बात करते हैं जो सरकार की आय का साधन है। इस विषय पर तो पूरे बजट में कोई बात ही नहीं की गई है कि किस प्रकार से संसाधन जोड़े जाएंगे, कैसे संसाधनों को इक्कठा किया जाएगा। जी.एस.टी. का Compensation या Protected Amount जो हर वर्ष लगभग 1,700 करोड़ रुपये आता है वह भी दिनांक 30-06-2022 को बंद होने वाला है। इसके अलावा केन्द्रीय ग्रांट्स का भी एक decline trend रहा है और वे भी कम होती जाएंगी। इसमें आपने कहा कि इस वर्ष हमने कोई टैक्सिस भी नहीं जोड़े हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि आपने कोई नए टैक्स नहीं लगाए हैं, आपकी ग्रांट्स कम हो रही हैं और जी.एस.टी. का Compensation Amount भी नहीं मिल पाएगा तो आप मुझे यह बताएं कि आपकी राजस्व प्राप्तियां कैसे बढ़ रही हैं? इस बजट में यह शब्दों व आंकड़ों का हेर-फेर नहीं है तो फिर क्या है?

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। राजस्व प्राप्तियां आप कैसे बढ़ाएंगे, क्या आप सड़क पर चलने वाले का मास्क न पहनने पर चालान करके राजस्व प्राप्तियां बढ़ाएंगे, क्या किसी गाड़ी का चालान कर देंगे तो उससे राजस्व प्राप्तियां बढ़ जाएंगी, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई भी आय का स्त्रोत नहीं है? इसके अलावा मैं शब्दों के हेर-फेर पर एक बात और करना चाहता हूं। हमारी सरकार के दौरान भी यही विभाग था, यही अधिकारी थे और आपकी सरकार में भी यही विभाग है व यही अधिकारी हैं। आपने प्रति व्यक्ति आय को दिखाने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को ही कम कर दिया। वर्ष 2018-19 में आपने अनुमानित जनसंख्या 76 लाख दर्शाई थी और आज वर्ष 2022-23 में वह 74 लाख दर्शाई गई है। 2 लाख लोग कहां गए, क्या पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में कोई पैदा ही नहीं हुआ और क्या 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई? इसका यही मतलब हुआ कि इस बजट में शब्दों व आंकड़ों का बहुत हेर-फेर चल रहा है। मैं समझता हूं कि यह बजट इस प्रकार से ठीक नहीं है।

07-03-2022/1720/वाई.के.-एन.जी. /2

अध्यक्ष महोदय, यहां पर ट्रेज़री बेंचिस की ओर से बहुत चर्चा हो रही है और अभी माननीय डॉ0 राजीव बिन्दल जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार में बिना आय के वृद्धा पैंशन की आयु 80 वर्ष से ऊपर थी और हमारी सरकार ने इसे 70 वर्ष कर दिया। आपने वर्ष 2018-19 के अपने बजट भाषण में कहा कि बिना आय प्रमाण पत्र के किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैंशन मिल जाएगी जिसकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो चुकी हो। अब आप इसे अपने बजट भाषण में 60 वर्ष पर लेकर आ गए हैं। लेकिन प्रदेश की जनता आप पर किस प्रकार से विश्वास करे क्योंकि आपके पहले बजट भाषण में जब आपने इसे बिना आय प्रमाण पत्र के 70 वर्ष पर लाया था तो उसके बाद दिनांक 17-05-2021 को एक अधिसूचना निकाली गई जहां पर कहा गया कि यदि किसी दम्पति में से कोई भी आयकर दाता है या उसकी कोई अन्य पैंशन आती है तो उसे यह पैंशन नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों हुआ? आपने यह कुछ सोच-समझ कर ही किया होगा, लेकिन आपके व आपकी सरकार के ऊपर यह विश्वास कैसे किया जाए क्योंकि जब आप वर्ष 2018-19 में इसकी आयु को 70 वर्ष पर लेकर आए थे तब भी आपने कहा था कि आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है और उसके बाद आपने दिनांक 17-05-2021 को एक फरमान जारी कर दिया कि दम्पति में से कोई भी आयकर दाता होगा तो उसके पक्ष में यह पैंशन नहीं लग पाएगी। अध्यक्ष महोदय, यहां पर किसानों के ऊपर बात चलती है और किसानों के साथ क्या-क्या हुआ हम सब जानते हैं। प्रदेश व देश में किसानों ने लगभग 1 वर्ष तक अपना आक्रोश जताया। केन्द्र सरकार द्वारा किसान बिल लागू किए गए लेकिन जब केन्द्र सरकार को भूख लगी और किसानों के कारण उनके पास खाना उपलब्ध नहीं था तब उन किसान बिलों को वापिस लिया गया। अब प्रदेश की सरकार ने भी असंवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश में कृषि व बागवानी का बजट ही काट दिया। प्रदेश सरकार ने कृषि व बागवानों का वह बजट काट दिया जिससे किसानों-बागवानों को आय हो सकती थी और आपने इस बजट में 75 करोड़ रुपये पिछले बजट के मुकाबले कम कर दिया। उस सैक्टर को काटा गया है जोकि

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

07.02.2022/1725/JS/YK/1

श्री आशीष बुटेलः----जारी-------

कोविड-19 के दौरान जिसकी वज़ह से आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ी थी। महोदय, बजट में मानदेय बढ़े और मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मानदेय बढ़ाये हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं आपको बहुत ही रोचक बात बताना चाहता हूं। आपने दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई, मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी का उसके लिए धन्यवाद भी करता हूं। जो दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ी वह 50 रुपये बढ़ी लेकिन जो पढ़े-लिखे एस.एम.सी. टीचर्ज़ हैं, उनकी 33 रुपये, आई.टी. टीचर्ज़ की 33 रुपये, स्पैशल पुलिस ऑफिसर की 33 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिका की 30 रुपये और आशा वर्कर्ज़ की, जिसने कोविड काल में घर-घर जा कर अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना उस दौर में काम किया, उसकी आपने दिहाड़ीदार के साथ कम्पेयर करके 60 रुपये की दिहाड़ी बढ़ाई । यह आपने किया है और अगर आप चाहते तो सबसे बड़ा तबका जहां पर दिहाड़ी लगती है, वह मनरेगा का है, आप उसको बढ़ाते। यदि आप मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाते तो आपका धन्यवाद भी करते। यहां पर एजुकेशन की बात की जाती है। पिछले चार सालों में मेरे चुनाव क्षेत्र में स्कूलों की अनाउंसमैंट हुई और वहां पर कहा गया कि इस स्कूल में यह कमरे बनने जा रहे हैं और इस स्कूल के लिए 3 करोड़ रुपये दे दिए। एक टोकन अमाउंट वहां पर आ जाता है जिसके हिसाब से टैंडर भी नहीं लगता। आज हालत यह है कि आप कहते हैं कि आपने बजट बढ़ा दिया। आपने पिछले चार सालों में एक कमरा भी मेरे चुनाव क्षेत्र में नहीं बनाया। इसके लिए वहां की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि हमने एजुकेशन में बहुत कुछ कर दिया। आप लोगों से बच्चों के लिए लैपटॉप तक दिए नहीं गए। आज तक लैपटॉप बच्चों को नहीं मिल पाए हैं। माननीय मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी, आपके विभाग का 14 परसेंट का बजट यहां पर डिक्लाइन शो कर रहा है। अर्बन डवलपमैंट में यह जो हमारा बजट है इसको नीचे ला दिया गया है। एम. एम. सैगी की जब हम बात करते उसमें आपने कहा तो है कि शहरी गरीबों को भी मनरेगा की तर्ज़ पर रोजगार

07.02.2022/1725/JS/YK/2

मिलेगा। मगर वह कानून कब बनेगा, यह सोचने वाली बात है। खास करके जो टी.सी.पी. और एम.सी., मेरे चुनाव क्षेत्र में जो नगर निगम आपने बनाई, जो वहां पर गरीब लोग थे, आस-पास के लोग थे, आम लोग थे, पंचायतें थीं, उनको मर्ज़ करके आपने नगर निगम बनाया है। आज वहां पर दिक्कत क्या आती है कि अगर किसी ने, जहां पर टी.सी.पी. एक्ट लागू नहीं होता था, वहां पर यदि दो मंजिला भवन बना दिया और टी.सी.पी. एक्ट उसमें लागू नहीं है, उसके पास नहीं लिखा है तो फिर भी उसको नोटिस दे देते हैं कि तुम्हारा बिजली व पानी कट जाएगा। इसके लिए हमने प्रार्थना की थी कि आप लोग उसका सर्वे करवाएं। कुछ पैसा वहां नगर निगम को सर्वे के लिए दिया जाए ताकि ठीक ढंग से सर्वे हो, ताकि जो भी काम वहां पर हैं उनको पूरा किया जाए। वाटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन में इस बार के बजट में माइनस 23 का डिक्लाइन है। एग्रीकल्चर में मैंने जैसे कहा कि 6 परसेंट का उसमें डिक्लाइन है। इण्डस्ट्री में 12.3 परसेंट का, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 5 परसेंट का डिक्लाइन है। इसके अलावा इस बजट में जो बातें होनी चाहिए थीं, जो हमारे भाई व बहन करूणमूलक आधार पर हैं, वे आपसे बात करना चाहते थे। वे 220-225 दिनों से बाहर बैठे हैं, आप लोगों को उन लोगों की बात करनी चाहिए थी, आपको पुलिस की बात करनी चाहिए थी जिनको आज भी 7 रुपये प्रतिदिन मिलता है यानि 210 रुपये उनको राशन के दिए जाते हैं आप लोगों को उनकी बात करनी चाहिए थी। आपको होम गार्डज़ की बात करनी चाहिए थी, जो पुलिस का काम करते हुए उनके बराबर उनको न कोई इनसैंटिव मिलता है, न कोई उनको सैलरी मिलती है इसलिए उनकी बात यहां पर करनी चाहिए थी। यहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति बनाने की बात करनी चाहिए थी। यहां पर बात होनी चाहिए थी, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहते हैं, मीडिया की बात होनी चाहिए थी। मुझे तो यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि दो साल पहले जब बजट अनाउंस हुआ था तो यह कहा गया था कि जितने भी इनके जितने भी स्टेट एक्रेडेटिड जर्नलिस्ट्स हैं उन सबको लैपटॉप दिए जाएंगे। उनको लैपटॉप तो दे दिए लेकिन बिना कार्ड के, बिना मेमरी कार्ड के दे दिए। उनको खुद जा करके मेमरी कार्ड खरीदना पड़ा। इस पर भी यदि आप जांच करवाना चाहे तो आप जांच करवाएं

07.03.2022/1730/SS-AG/1

श्री आशीष बुटेल क्रमागत :

कि क्या जब वह लैपटॉप खरीदा गया है तो उसके इतने पैसे दिए गए थे कि उसको एस0एस0डी0 कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा।

महोदय, बेरोज़गारों की चर्चा हमेशा बजट में करते आए। पिछली बार भी आप काफी लोगों को बेरोज़गारी से हटाना चाहते थे और कहते थे कि रोज़गार देंगे। लेकिन नहीं दे पाए हैं। इस बार भी आपने कहा है कि 30 हजार बच्चों को रोज़गार देंगे। परन्तु रोज़गार कैसे देंगे? उसके लिए कोई नीति हो होगी। क्या चोर दरवाजे से आप सारी नौकरियां देंगे तो उस तरह से कहा जाएगा कि वे रोज़गार ले रहे हैं? क्या ऐसा होगा कि जिस तरह से कोई चाहेगा वैसा नौकरी लग जाएगी? क्या इसके लिए नीति नहीं होनी चाहिए थी? आपके बजट में पेशकश होनी चाहिए थी कि किस तरह से हम बेरोज़गारी को दूर करेंगे। चरणबद्ध तरीके से करते, उसको वैसे ही करना चाहिए था।

महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पालमपुर की बात करना चाहूंगा। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक मेन मुद्दा चल रहा है। जब हम कहते हैं कि ज्यूडिशियल रिफोर्म्स हम लेकर आना चाहते हैं और उसके लिए आपके बजट में पैसा भी है। तो पालमपुर में ऐसा क्या था कि नहीं हो सकता। जितनी मेरी जानकारी है कि हाई कोर्ट तक से एडिशनल ए0डी0जे0 का कोर्ट परमानेंट बैंच के लिए पालमपुर हेतु क्लीयर हो गया था। लेकिन सरकार नहीं करती। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए।

रोपवे की बात हुई। आपने कहा है कि रोपवे आएंगे। आपका एम0ओ0यू0 गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से साइन होगा। लेकिन जो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से एम0ओ0यू0 साइन होने वाला है इसमें कितने पैसे आएंगे, क्या आएगा, किस तरह से होगा, पी0पी0पी0 मोड पर होगा या गवर्नमैंट करेगी, वह बताएं। आपकी पार्टी के लोगों वहां पर ऑलरेडी वाहवाही लूट चुके हैं ये कहते हुए कि हम इतना पैसा लेकर

आ रहे हैं। सैंट्रल गवर्नमैंट से इतना पैसा आ रहा है। जब स्टेट गवर्नमैंट को नहीं मालूम कि कितना पैसा पालमपुर रोपवे के लिए आएगा तो वहां पर आपके भाजपा के लोगों को इसके बारे में कैसे मालूम है, यह बात मेरी समझ से बाहर है।

महोदय, आर्म्ड पुलिस हैडक्वार्टर की बात माननीय मुख्य मंत्री की पालमपुर के लिए अनाउंसमैंट है। उसके ऊपर इस बजट में कुछ नहीं है। हम डवलपमैंट ब्लॉक की बार-बार बात करते हैं, सिर्फ परमजीत सिंह जी, रमेश चंद ध्वाला जी और मेरा डवलपमैंटल ब्लॉक रह गया; पता नहीं ध्वाला जी आपको चाहिए या नहीं लेकिन मुझे तो अवश्य चाहिए। पालमपुर विकास खंड कार्यालय का एक मुद्दा बहुत समय से लटका हुआ है। उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं वह सोल्व हो।

फिर उसके बाद एक और बात है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि ए0डी0बी0 के तहत पालमपुर की ब्यूटीफिकेशन का एक प्रोजैक्ट है। मुख्य मंत्री जी चले गए लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इस प्रोजैक्ट को पार्किंग के प्रोजैक्ट में तबदील किया जाए। पालमपुर में पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है। अगर ए0डी0बी0 के अंडर वहां पर कुछ कार्य हो तो पार्किंग का हो, ऐसी रिक्वैस्ट मैं माननीय मुख्य मंत्री से करना चाहूंगा।

इंडोर स्टेडियम की बात हुई। इंडोर स्टेडियम की चर्चा तो यहां पर ऐसे हुई कि सब इंडोर स्टेडियम शुरू कर देंगे। लेकिन पालमपुर का इंडोर स्टेडियम जिसका शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री कर चुके हैं उसमें पी0डब्ल्यू0डी0 के पास 30 लाख रुपया 17 करोड़ रुपये के विरुद्ध आया था। परन्तु अगर 30 लाख रुपये वहां पड़े थे तो उनको भी आज वहां से उठा लिया गया है। महोदय, तो मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है।

महोदय, मैं ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहंगा कि पिछले डेढ़ वर्ष से पब्लिसिटी पर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, उसका एक प्रश्न आप ही समक्ष इस विधान सभा में लगाया है। वह प्रश्न हर सत्र में स्थगित प्रश्न के रूप में

07.03.2022/1730/SS-AG/3

आता है और फिर से उसको स्थगित कर दिया जाता है। क्या पिछले डेढ़ साल में इस सरकार का यह भी मालूम नहीं है कि पब्लिसिटी पर कितना पैसा खर्च किया है। जब हम बात कर रहे हैं कि 12500 करोड़ रुपये का हम ऋण लेने लगे हैं। उसमें से हम 5200 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट पर लगाएंगे। इलैक्शन आ गया है तो क्या 7 हजार करोड़ रुपया उसकी पब्लिसिटी पर लगने जा रहे है? महोदय, मैं ज्यादा न कहता हुआ आपसे इतना कहूंगा कि यह सरकार जाने वाली सरकार है। इस चमन की ये जाती बहारें हैं और जल्द ही इलैक्शन में पता लगेगा कि यह बजट जनता को किस तरह से भाया। मुझे तो बिल्कुल नहीं भाया और मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी भाग लेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2020/1735/केएस/एएजी/1

श्री विनोद कुमार (नाचन): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने 04 मार्च, 2022 को वर्ष 2022-23 के जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, उसका समर्थन करने हेतु मैं खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, नाचन विधान सभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से इस माननीय सदन का मैं भी यह दसवां बजट सुन व देख रहा हूं। यहां पर विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से कहा गया कि बजट निराशाजनक है, इसमें कुछ नहीं है लेकिन बजट निराशाजनक विपक्ष के लिए है, जनता के लिए नहीं है, यह बात मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। इसके साथ

ही इन्होंने कहा कि इस बजट में सिर्फ शेरो-शायरी की गई तो मैं अपने सहयोगी साथियों के लिए कहना चाहूंगा किः-

न संघर्ष न तकलीफें, क्या है मज़ा फिर जीने में,
मेरे मित्र तूफ़ान भी थम जाएंगे, जब लक्ष्य रहेगा सीने में,
जब लक्ष्य रहेगा सीने में।

अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा। जिस तरह से इस कोरोना महामारी के बीच में इन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है, मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हर जनमानस का, हर वर्ग का निश्चित तौर पर इस बजट में ध्यान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हर चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा कोशिश की जाती है कि उसके विधान सभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो, विकास के नए-नए काम हों और हर चुना हुआ व्यक्ति यही प्रयास करता है। आप लोगों ने अगर बजट भाषण को ढंग से सुना होगा तो हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने सबसे पहली चिंता, सबसे पहली बात चुने हुए

07.03.2020/1735/केएस/एएजी/2

प्रतिनिधियों को ले कर कही है। इन्होंने कहा कि प्लानिंग की बैठक में जो सुझाव सभी माननीय विधायकों की ओर से आए हैं, सभी विधायकों की ओर से एक बात कही जाती है कि नाबार्ड को ले कर जो हमारी सीलिंग रहती है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि नाबार्ड के तहत जो 135 करोड़ रुपया हर विधान सभा क्षेत्र को मिलता था, उसको अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने 150 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मैं विपक्ष के मित्रों को कहना चाहूंगा कि 150 करोड़ रुपये सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों को ही नहीं मिलेंगे , 68 के 68 विधायकों को मिलेंगे। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 150 करोड़ रुपये में

से 70 करोड़ रुपया केवल हमारे इस पांच साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी की इस सरकार द्वारा बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हर विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्य के लिए अब विधायक क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ रुपये की गई है और यह बात भी सही है कि वर्ष 1999 से विधायक क्षेत्र विकास निधि को शुरू किया गया था। उस वक्त केवल 15 लाख रुपया हर विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्य के लिए दिया जाता था।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

07.03.2022/1740/av/as/1

श्री विनोद कुमार----जारी

उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा क्योंकि यहां पर जैसे माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी ने कहा है कि श्री प्रेम कुमर धूमल की सरकार ने नई शुरुआत की थी। अगर इसको उस समय की हमारी पार्टी की सरकार ने शुरू किया था तो मैं अपनी उस सरकार को भी बधाई देता हूं। आज हमें 2 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है। अगर हम वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2017 की बात करें तो लगभग इन 19-20 वर्षों के लंबे अंतराल में विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 1.17 करोड़ रुपये की राशि ही दी जाती थी। लेकिन जब से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से इसमें लगभग 83 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर ऐच्छिक विधायक निधि की बात की जाए तो इस बार भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें 2 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है। हम जब सरकार में आए थे तो हमें ऐच्छिक विधायक निधि के रूप में 5 लाख रुपये की धनराशि मिलती थी परंतु वर्तमान बजट के अनुसार अब यह राशि 12 लाख रुपये कर दी गई है। इसमें हमारी सरकार ने कुल मिलाकर के 7 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है जिसके लिए मैं

माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। यह बात सही है कि जब भी किसी सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार में चुने हुए सभी प्रतिनिधि उसका समर्थन करते हैं और विपक्ष के हमारे साथी उसका विरोध करते हैं। लेकिन मेरा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों से एक निवेदन रहेगा कि हमने जो डिमाण्ड मुख्य मंत्री जी से की होती है और उसको जब उनके द्वारा पूरा कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर हमें उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे सहयोगी इस बात को लेकर के बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे कि गैस का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। यहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि गैस का सिलेंडर 1,000 रुपये का हो गया और कुछ कह रहे थे कि 1,100 रुपये का हो गया। मैं इस माननीय सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि यदि 1,000 रुपये या 1,100 रुपये गैस सिलेंडर का रेट होगा तो मैं आज ही

07.03.2022/1740/av/as/2

विधान सभा सदस्य से इस्तीफा देता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज की डेट में गैस का सिलेंडर 970 रुपये या 972 रुपये में मिल रहा है। यहां पर आप लोग जो 1,000 रुपये की बात कर रहे हैं तो आप लोग अपना वक्त भूल गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी सरकार के समय में गैस का सिलेंडर 1,263 रुपये में भी आया है। यहां पर चाहे उज्ज्वला योजना की बात की जाए या गृहिणी सुविधा योजना की बात की जाए; हमारी सरकार ने कहा है कि हम इस योजना को हिमाचल प्रदेश में जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि इसमें और ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता होगी तो हम वह भी करने का प्रयास करेंगे। यहां पर जो यह कहा जा रहा है कि आपने गैस का कनेक्शन तो दे दिया परंतु उस सिलेंडर को एक गरीब व्यक्ति कैसे भरेगा? मैं इस सदन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में रहने वाले उन सभी गरीब परिवारों को बधाई देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री के आशीर्वाद से अब एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन-तीन सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जिन्होंने पहले गैस का कनेक्शन ले लिया है तथा साथ में एक फ्री गैस सिलेंडर लिया है; उनको अब दो-दो और मुफ्त गैस के

सिलेंडर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जिन्होंने दो फ्री गैस के सिलेंडर ले लिए हैं उनको एक-एक और फ्री गैस का सिलेंडर मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री के आशीर्वाद से प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं और इस बजट में इन्होंने हर वर्ग का सहयोग करने का पूरा प्रयास किया है

टी सी द्वारा जारी

07/03/2022/1745/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्री विनोद कुमार . .. जारी

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम गाय को गौ-माता कहते हैं लेकिन हमने उसके लिए किया क्या है? मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। जब से हिमाचल प्रदेश में आपके नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, अनेकों कऊ सेंक्चुअरीज और गौ सदनों का निर्माण हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया। आज 20 हजार गौवंश उन कऊ सेंक्चुअरीज और गौसदनों में रखने का का कार्य किया जा रहा है। जहां यह कऊ सेंक्चुअरीज व गौ-सदन चल रहे है और जितने भी गौवंश वहां पर रखे गए हैं, उनको एक गौवंश के ऊपर 500 रुपया प्रतिमाह दिया जाता था। इसके बारे में एक डिमांड आई थी कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने इसको 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने का काम किया है। जितना भी गौवंश इनके अंदर रखा गया है, उनका आशीर्वाद निश्चित तौर पर सरकार को मिलेगा और विशेष करके मुख्य मंत्री जी को मिलेगा। पशु पालकों को को बेहतर सुविधा देने के लिए 44 मोबाइल एंबुलेंसिज हमारी सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चलाई जाएगी। इससे पिछड़े क्षेत्र के पशु पालकों को लाभ मिलेगा। इस पर 7 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। मैं सभी दूध उत्पादकों की ओर से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस बजट में भी दूध के दाम 2 रूपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की। इसे पहले आपने दूध के मूल्य में 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है यानी आपने दूध के मूल्य में कुल 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस प्रदेश में अनेकों सरकारें आई और चली गईं लेकिन इतनी बड़ी वृद्धि दूध के रेट में अगर किसी सरकार ने की है तो आदरणीय मुख्य मंत्री ठाकुर जय राम की सरकार ने की है। दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की

और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के एक लाख बुजुर्गों लिए पेंशन की आयु सीमा 80 से 70 साल करने का निर्णय लिया। कुछ माननीय विधायक कह रहे थे कि जो घोषणाएं मुख्य मंत्री जी ने की हैं, ये इम्प्लीमेंट कब होंगी? मैं इस माननीय सदन में कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने जितनी भी स्कीमों की घोषनाएं की थीं, उन सभी स्कीमों को चलाया गया है और लागू किया गया है। जब मुख्य मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो हम भी यह मानकर चल रहे थे कि पेंशन की आयु सीमा शायद 65 साल तक हो जाए।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

07-03-2022/1750/NS/DC/1

श्री विनोद कुमार .....जारी

लेकिन जब मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अब मैं बिना इनकम की पेंशन की आयु सीमा को 70 वर्ष से घटा कर 60 वर्ष कर रहा हूं। सत्ता पक्ष में सबके चेहरे खिले हुए थे और विपक्ष में जितने सहयोगी बैठे थे उनके होश उड़े हुए थे। इसका क्या कारण था? कारण यह था कि अगर 80 वर्ष से 70 वर्ष हुई तो 1 लाख से ऊपर बुजुर्गों को लाभ मिला और अब 70 वर्ष से 60 वर्ष होगी तो निश्चित तौर पर यह संख्या मेरे हिसाब से अढ़ाई लाख से तीन लाख के करीब होगी और ये सारे बुजुर्ग श्री जय राम ठाकुर जी और इस सरकार को आशीर्वाद देंगे जिनके कारण उनको पेंशन मिलने वाली है। अध्यक्ष महोदय, जब हम विपक्ष में थे और गांव में लोगों के बीच जाते थे तो कुछ बुजुर्ग पेंशन का फार्म जेब में लेकर हमारे पास आते थे और कहते थे कि कब वक्त आएगा और कब पेंशन लगेगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब राम राज्य आ गया है और जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चली है। निश्चित तौर पर चाहे गौवंश की बात हो या बुजुर्गों की बात हो, इन सबका ध्यान हमारी सरकार में रखा गया है। उन बुजुर्गों का ध्यान हमारी सरकार के माध्यम से रखा गया जिनके कारण आज हम आप सब लोग यहां पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजनों की पेंशन की बात ही नहीं बल्कि मुख्य मंत्री जी ने हर वर्ग का सहयोग करने की कोशिश की है और इस पेंशन को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। आप सबके ध्यान में होगा कि यह पेंशन योजना हमारी सरकार के समय में शुरू हुई थी और इस पेंशन योजना को पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय श्री

शांता कुमार जी के समय में शुरू किया गया था तथा उस समय 50 रुपये पेंशन दी गई थी। आपमें से कुछ सहयोगी उस समय थे और जो हंसे थे कि आप विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन के रूप में 50 रुपये देंगे। आज इस पेंशन का बहुत बड़ा लाभ पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जैसे यहां पर कहा गया कि 6.35 लाख बुजुर्ग और परिवार हैं जिनको हमारी सरकार के माध्यम से पेंशन दी जा रही है। पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय श्री शांता कुमार जी का सहयोग व आशीर्वाद इस पेंशन को शुरू करने में रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि बुजुर्गों के दर्द को किसी ने समझने की कोशिश की है तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर

07-03-2022/1750/NS/DC/2

जी ने की है। उन सभी बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जितने भी प्रतिनिधि चुन करके आए हैं उनके लिए मुख्य मंत्री जी ने पूरी कोशिश की है कि चुने हुए प्रतिनिधि का मान सम्मान होना चाहिए और इनके मानदेय को बढ़ाया है। मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को बधाई देता हूं। मुख्य मंत्री जी ने इनका मानदेय 3000 रुपये बढ़ाने की घोषण की है। अब जिला परिषद के चेयरमैन को 15,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। जब वे 15,000 रुपये वेतन एक महीने का लेंगे तो इसमें से 7000 रुपये वेतन बढ़ाने का काम श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। मैं, मुख्य मंत्री जी का सभी जिला परिषद के अध्यक्षों की ओर से धन्यवाद करता हूं। जिला परिषद के उपाध्यक्षों को 2000 रुपये वेतन बढ़ाने का काम मुख्य मंत्री जी ने किया है और उनको अब 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इसमें से 4000 रुपये वेतन हमारी सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जिला परिषद के सदस्य, चाहे बी0डी0सी0 के चेयरमैन, उपाध्यक्ष की बात हो, चाहे बी0डी0सी0 मैंबर की बात हो,

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

07.03.2022/1755/RKS/DC-1

श्री विनोद कुमार... जारी

पंचायत प्रधान या उप-प्रधान की बात हो, सभी पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय माननीय मुख्य मंत्री जी ने और सरकारों की अपेक्षा अधिक बढ़ाया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में काफी काम हुए हैं। विपक्ष के साथियों ने कहा कि प्रदेश में इतनी ज्यादा पाइपें आ गई कि पाइपों को बिछाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कई जगह पाइपों के बाड़ लगा दिये गए। जब हम विपक्ष में थे तो हम पाइपों के लिए तरसते थे। पाइपें जंग लगने के कारण सड़ जाती थी परंतु हमें पाइप नहीं दी जाती थी। हम विधायक निधि से ही लोगों को पाइपें दे पाते थे। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत जो दो वर्षों में 8,35,000 नये कनैक्शन्ज लगाने का काम किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और जल शक्ति मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। आज हिमाचल प्रदेश के किसी भी विधान सभा चुनाव क्षेत्र में पाइपों को लेकर कोई इश्यू नहीं है। पहले पाइपें नहीं मिलती थी लेकिन आज जिस व्यक्ति को पानी का कनैक्शन लेने के लिए जितनी पाइपों की आवश्यकता होती है, उसे उतनी ही पाइपें दी जा रही हैं। पाइपों के साथ नलका भी मुफ्त दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 12,000 बेघर लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया था जिसे हमारी सरकार ने निश्चित रूप से पूरा किया है। हमने इस वर्ष 12,769 बेघर लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा है। इस वैश्विक महामारी के समय आशा वर्कर्ज ने अपनी बेहतरीन सेवाएं दी हैं। आप आशा वर्कर्ज के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने कार्यकाल में इन कार्यकर्ताओं को क्या दिया? आपके समय में आशा वर्कर्ज का मानदेय सात सौ या एक हजार रुपये था। मेरी आशा वर्कर्ज बहनें कहती थी कि हमें जितना मानदेय मिलता है उससे तो हमारा आने-जाने का किराया भी पूरा नहीं हो पाता। हमारी सरकार ने इस मानदेय में 3700 रुपये की बढ़ोतरी की है और अब उन्हें 4700 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। अगर उनके मानदेय में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इन कार्यकर्ताओं को नौ हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इस नौ हजार मासिक वेतन में 4500 रुपये की राशि हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। मिनि आंगनवाड़ी

कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिड-डे-मील वर्कर्ज,वाटर कैरियर, जल रक्षक और पैरा फिटर्ज इन सभी श्रेणियों का मानदेय हमारी सरकार ने ही बढ़ाया है।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

07.03.2022/1800/बी.एस./एच0के0/-1

श्री विनोद कुमार जारी...

इसकी विशेष बधाई तो मैं अपने बड़े भाई जी को देना चाहता हूं और इसके साथ-साथ चाहे मिनी आंगनबाड़ी की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी सहायिका की बात हो, चाहे मिड-डे-मील की बात हो, जल रक्षक की बात हो, चाहे पैराफिटर की बात हो । इन सब का मानदेय हमारी सरकार ने बढ़ाया है। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय में कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कपया समाप्त करें।

श्री विनोद कुमार : जो लोग तपती धूप में और ठिठुरती सर्दी में जो दिन-रात मेहन करता है। उसका ध्यान भी हमारी सरकार ने रखा है। उस मजूद की मजदूरी 50 रुपए प्रतिद बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे इस कार्यकाल में उस मजदूरी की मजदूरी 140 रुपए बढ़ाने का काम किया है तो जय राम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा यहां पर बात आई एस0एम0सी0 के अध्यापकों की, मैं कहना चाहता हूं कि एस0एस0सी0 के जितने भी हमारे अध्याप साथी हैं, मैं अपनी सरकार की ओर से उन्हें आश्वस्त करवाना चाहूंगा कि हमारे बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि आपका एक हजार प्रति माह वेतन बढ़ाएंगे और जहां-जहां भी आप सेवाएं दे रहे हैं, आप अपनी सेवाएं स्वतंत्रता से दे सकते हैं और आने वाले समय में आपको ले करके नीति भी बनाई जाएगी। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी हा धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब आप मंत्रिमंडल में सहयोगी थे तो आप के माध्यम से एक हिमकेयर योजना आरंभ की गई थी और उस हिमकेयर योजना के तहत पाचं लाख से अधिक हिमकेयर कार्ड हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के उन करीब लोगों के बनाए गए थे। आज अढ़ाई लाख के करीब ऐसे परिवार हैं जो इस योजना के

माध्यम से लाभ उठा चुक हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अब जो हिमकेयर कार्ड जनवरी से मार्च, महीने तक बनते थे वे अब पूरी साल भर बनेंगे। अब उनके रिन्यूल करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वे तीन वर्ष तक चलेंगे। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 50 नई एंबुलेंसिज लाई जाएंगी। इसके साथ ही 500 डॉक्टर्ज के पद भरे जाएंगे और इसके साथ-साथ दूरदराज क्षेत्र में स्वास्थय सुविधा हर द्वार तक उपलब्ध हो उसके मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना का शुभारंभ किया है।

07.03.2022/1800/बी.एस./एच0के0/-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया वाइंडअप करें।

श्री विनोद कुमार : हमारी सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि 0-60 यूनिट बिजली तक जो भी उपभोक्ता खर्च करेगा, उससे कोई भी पैसा हमारी सरकार नहीं लेगी और प्रदेश में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या साढ़े चार लाख है। मैं कहना चाहूंगा कि जब उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारी सरकार को मिलेगा। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 60-120 यूनिट बिजली का हम एक रुपया वसूल करेंगे। जहां तक किसानों की बात है मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने की बात कही गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बजट हिमाचल प्रदेश के लोक प्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर ने प्रस्तुत किया है, मैं इसका निश्चित तौर से समर्थन करता हूं और आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

07.03.2022/1800/बी.एस./एच0के0/-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणा, सुजानपुर : माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 4 मार्च को वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया है। उस पर चर्चा करने के लिए मैं भी शामिल हुआ हूं।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

07-03-2022/1805/एच.के.-एन.जी. /1

श्री राजेन्द्र राणा..... जारी

इस बजट में लिखा गया है कि 51,365 करोड़ रुपये का यह बजट पेश किया गया है। इस बजट में यह भी दर्शाया गया है कि वर्ष 2021-22 में 37,312 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और 37,034 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं, यानि के 278 करोड़ रुपये सरप्लस अनुमानित है। वर्ष 2022-23 के बजट में प्राप्तियां 36,375 करोड़ रुपये हैं यानि के वर्ष 2021-22 के मुकाबले लगभग एक हज़ार करोड़ रुपये कम दिखाए गए हैं। जबकि वर्ष 2022-23 में 40,278 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है और वर्ष 2022-23 में 3,903 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में यह भी दर्शाया गया है कि वर्ष 2021-22 का जो बजट था उसमें जी.डी.पी. ग्रोथ माइनस 5.2 प्रतिशत थी जबकि यह खुशी की बात है और आंकड़ों में दिखाया जा रहा है कि इस वर्ष 8.3 प्रतिशत ग्रोथ होगी। मुझे लगता है कि यह केवल आंकड़ों को ही बढ़ाया गया है और हकीकत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, मेरे साथियों ने भी चर्चा की है और मुझे लग रहा है कि बजट इतना नीरस है कि सत्तापक्ष के सभी माननीय सदस्यों का इसमें कोई भी रूची नहीं है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि :-

यह कहना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं,

हम मशरूफ जरूर हैं, लेकिन बेखबर नहीं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जो बजट पेश हुआ था और इस वर्ष जो बजट पेश हुआ है इन दोनों में लगभग वही आंकड़े हैं और आंकड़ों को थोड़ा-बहुत घुमा कर दिखाने की कोशिश हुई है। इस बजट में कुल 29 प्रतिशत बजट राज्य के विकास के लिए खर्च होगा।

07-03-2022/1805/एच.के.-एन.जी. /2

मुझे लग रहा है कि जो बजट राज्य के विकास के लिए खर्च होना चाहिए वह धीरे-धीरे सिकुड़ कर कम होता जा रहा है जोकि प्रदेश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सारी चर्चा हुई कि 46,000 करोड़ रुपये का कर्ज पिछली सरकार के समय प्रदेश के ऊपर था। आज यह कर्ज लगभग 70,000 करोड़ रुपये होने जा रहा है। पिछली बार जब हम सत्ता में थे और विपक्ष की ओर से जो आवाज़ें आती थीं और मीडिया के माध्यम से भी समाचार पत्रों में जो पढ़ने को मिलता था कि यह सरकार तो कर्जा लेकर ही चल रही है। उस समय प्रदेश की जनता ने समझा कि प्रदेश में यदि डबल इंजन की सरकार चलेगी तो कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल इंजन होगा तो दिल्ली से पैसा आएगा और डबल स्पीड से प्रदेश चलेगा लेकिन मुझे लगता है कि न तो दिल्ली वाला इंजन चला और न ही प्रदेश का इंजन चला। कर्जे की स्पीड बढ़ती चली गई और आज प्रदेश पर 70,000 हजार करोड़ रुपये कर्जा हो गया, यह बहुत ही चिंता का विषय है। हम लोग चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, सरकारें आती हैं, जाती हैं लेकिन हम ऐसा कब तक करते रहेंगे और प्रदेश को कब तक कर्ज लेकर चलाते रहेंगे? इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 22 पन्नों का जो दृष्टि पत्र जिसका नाम 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र-2017' था। मैं इसे पढ़ रहा था और इसे पढ़ कर ऐसा लगा कि सरकार ने इसे डस्टबीन में ही डाल दिया है। इस पर कुछ काम हुए हैं लेकिन 70 प्रतिशत से ज्यादा कामों पर तो सरकार की नज़र ही नहीं है। मैं आपका शुभचिंतक हूं और मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लोग जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि क्या आपको हमने इसलिए वोट दिया था कि आपने जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं करेंगे? यह आप सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैं कहना चाहूंगा कि-:

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

07.02.2022/1810/JS/YK/1

श्री राजेन्द्र राणाः----जारी----------

सोचा याद दिला दूं भाजपा को,

सोचा याद दिला दूं भाजपा सरकार के वायदे,

मंहगाई का विकास और जनता के विनाश में थे इरादे।

मुझे तो ऐसा लग रहा है। उस वक्त तो एक नारा यह भी चला था किः-

बहुत हुई मंहगाई की मार, अबकी बार भाजपा सरकार।

...व्यवधान...आप देखिए, माननीय सदस्य जी आप सुनिए, मैं तो आप लोगों की बात बड़ी शांति से सुन रहा था। यही नारा तो अब विनाश का कारण बनेगा। लोग आपसे पूछेंगे कि तब तक 70 रुपये की कड़वे तेल की बोतल मिलती थी और अब तो आपने इसे 220 से 235 रुपये तक पहुंचा दिया है। यह मंहगाई की वजह है। पिछली सरकारों में क्या था। पेट्रोल और डीजल के जो इन्टरनेशनल मार्किट में दाम थे, वे कहां पर थे और पेट्रोल और डीजल कितने में मिल रहा था? आपकी सरकारों ने तो इसे 100 रुपये से पार पहुंचा दिया है। आप खाने-पीने की चीजों को देखो। इनकी कितनी कीमतें हो गई यह इसी का तो नतीजा है। ये जो बाई इलैक्शन हुए इसको स्टडी करने की कोशिश करो। इसमें कोई चिन्तन-मनन करिये। ये जो तीन विधान सभा और एक सीट लोकसभा की है, इसमें भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया गया लेकिन आप लोग इसको अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप यहां पर बोल रहे हैं कि हम तो 15 साल के लिए आ गए हैं। आप 15 साल के लिए छोड़िए अब आपकी सरकार की हालत जैसे कोई मरीज वेंटिलेटर पर पड़ा होता है उसकी तरह हो गई है। मैं दो दिन अपने चुनाव क्षेत्र में था और मैं लोगों के बीच में था। वहां पर लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसकी आपके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी आपके पास 5-7 महीने हैं कुछ अच्छे काम करके जाएं। जो बजट है उसकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। इसमें कुछ काम अच्छे भी हुए हैं। हम उनकी तारीफ करते हैं कि जो अच्छे काम हुए हैं। आपने विधायक निधि बढ़ाई है हम उसकी तारीफ करते हैं। आपने ऐच्छिक

निधि बढ़ाई है, हम उसकी तारीफ करते हैं। पंचायतों के प्रतिनिधियों का आपने मानदेय बढ़ाया है, आपने बुढ़ापा पैंशन की आयु सीमा कम की है और पैंशन बढ़ाई है, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपने पिछले बजट में पेश की थी, वह हकीकत जमीन पर नहीं उतरी है। यहां पर गौ सैंक्चुअरी की बात भी हुई है। हम गऊ माता की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं परन्तु अभी भी सड़कों पर हजारों की तादाद में पशु घूम रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक गौशाला बनाई गई और अभी उद्घाटन ऑन लाइन हुआ है और ऑन लाइन होने के पहले ही जो दीवारें वहां पर लगाई थीं, वे गिर गई। हमने सरकार को लिखा कि यह पब्लिक का पैसा है, इस पैसे का दुरूपयोग हुआ है, इसकी कम-से-कम जांच तो करवाएं। तब भी कुछ नहीं हुआ। ठेकेदार मौज़ लूट रहे हैं और मलाई चाट रहे हैं। सरकार में कोई कुछ नहीं है। ये सारी बातें समाचार-पत्रों में छपती रही। दूसरा जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, वह है बेरोजगारी का। आज लगभग जो आंकड़ें बताए जा रहे हैं कि 14 लाख के करीब हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार हो गये हैं। आपने इस बजट में भी यह कहा है कि हम 30 हजार रोजगार देंगे। पिछली बजट बुक में भी था कि 30 हजार रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर कितने दिए, वह तो आपको तब पता चल जाएगा जब बजट के ऊपर रिप्लाई आएगा। हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे कोविड के दौरान हजारों नहीं लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कई बच्चे प्राइवेट सेक्टर, आई.टी. सेक्टर और इण्डस्ट्रीज में काम कर रहे थे वे सारे-के-सारे बच्चे घर चले गए। सरकार के पास क्या कोई उनका आंकड़ा है? सरकार के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि कितने बच्चे बेरोजगार हो गए, किसने लोन ले रखा था, किसने गाड़ी ले रखी थी? आज वे सारे-के-सारे नौज़वान परेशान हैं। सरकार की इसको ले कर क्या योजना है इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा जो कोविड का दो साल का समय रहा, इसमें जो छोटा,मध्यम या बड़ा व्यापारी तबका है, यह लगभग तबाह हो गया। आप दुकानदारों को पूछिए कि कारोबार की क्या हालत है, वे आपको बताएंगे कि क्या हालत है? लोगों का बहुत बुरा हाल है। सरकार की ओर से उनको कोई-न-कोई इन्सेंटिव दिया जाना चाहिए। उनके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। अगर व्यापार नहीं चलेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो न लोगों को रोजगार मिलेंगे और न सरकार को टैक्स आएगा। यह चिन्ता का विषय है। इसमें सरकार की कोई

नज़र नहीं है। दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि नोटबंदी आपकी सरकार ने करी। इससे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

07.03.2022/1815/SS-YK/1

श्री राजेन्द्र राणा क्रमागत :

बहुत बुरा हाल है। नोटबंदी और जी0एस0टी0 भी बड़े haphazard way से लागू हुई है उससे प्रदेश व देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। आप देखिए कि 1.76 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखा हुआ था। वह इसलिए रिजर्व रखा जाता है कि देश के ऊपर कोई विपदा आ जाए या कोई युद्ध हो जाए या कोई डिजास्टर हो जाए तो उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पैसे को भी आपकी सरकार रिजर्व बैंक से निकाल कर ले गई। आपने बड़ी चर्चा की, मीडिया में चर्चा हुई, रैलियों में चर्चा हुई कि आप किसानों की आमदन डबल कर देंगे। लेकिन आज किसानों का क्या हाल है? 2017 से पहले आपका मंडी का जो फोरलेन बन रहा था उसको लेकर कितना विरोध हुआ, आप उसमें शामिल हुए। क्या आपने उनको फैक्टर-2 के तहत मुआवजा दिया? क्या फैक्टर-1 या फैक्टर-4 के तहत मुआवजा दिया? आज जो किसान या जमींदार हैं वे उसी तरीके से वहां पर जूझ रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में धौलासिद्ध प्रोजैक्ट लगा। वहां पर किसानों की जो जमीन ली गई, उसमें आप 30 हजार रुपया किसान को दे रहे हैं। उसकी जो स्टाम्प डयूटी लगाई जा रही है, मंत्री जी मैं आपके डिपार्टमैंट से सवाल कर रहा हूं कि धौलासिद्ध प्रोजैक्ट में जो जमीन एक्वायर हुई है चाहे वह नदौन, सुजानपुर, जयसिंहपुर या ज्वालामुखी निर्वाचन क्षेत्र की है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला यह हुआ है कि किसान से जबरन जमीनें खरीदी गई हैं। उनको 30 हजार रुपया दिया गया जबकि आपका सर्कल रेट 2.30 लाख रुपया है। प्रोजैक्ट वाले स्टाम्प डयूटी 2.30 लाख रुपये की लगा रहे हैं परन्तु किसानों को मुजावजा 30 हजार रुपया दिया जा रहा है। उन लोगों को ठगा गया

है। आपकी सरकार में किसानों की हालत यह है। यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप इसकी इंक्वायरी करिए। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।

(श्री बलबीर सिंह, माननीय सभापति पीठासीन हुए।)

07.03.2022/1815/SS-YK/2

दूसरा, मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश का लगभग ढाई लाख कर्मचारी आज सड़कों पर है। वह ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहा है। यह ओल्ड पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी के समय में बंद हुई थी। केन्द्र में उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। हम सब उनका सम्मान करते हैं लेकिन उस समय ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई थी। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई थी। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं आप उसको सुनिए। सरकार पेंशन देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही है यह सरकार का काम है। परन्तु बाहर यह चर्चा है कि विधान सभा के अंदर जब कोई आदमी इलैक्ट होता है वह चाहे एक महीना, दो महीना, छः महीना, एक साल या पांच साल लगाए, उसको पेंशन दी जाती है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि या तो कर्मचारियों को पेंशन दो, नहीं तो हम सब लोगों पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। फिर विधायकों की और मेम्बर पार्लियामेंट की पेंशन बंद करवाओ ताकि वे लोग भी संतुष्ट हो जाएं कि सब की पेंशन बंद हो गई। इसलिए यहां पर भी रेजोल्यूशन लगाया जाए कि सब विधायकों की पेंशन बंद कर दो।

पुलिस डिपार्टमैंट के कर्मचारी लगातार एजीटेशन कर रहे हैं। पुलिस वालों को जो डाइट मनी मिलती है उसके बारे में बजट में कोई ज़िक्र नहीं आया। 7 रुपया उनको डाइट मनी दी जाती है तो क्या 7 रुपया जायज है? पुलिस वाले डाइट मनी को बढ़ाने के लिए लम्बे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2015 के बाद जिन लोगों की रिक्रूटमैंट हुई है और उनके वेतन में जो विसंगतियां हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है जिसके वे लगातार प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे भाई-बहन बाहर नौकरियों के लिए जाते हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं तो उनके बच्चे बाहर दिल्ली या अन्य जगह पढ़ रहे हैं। चाहे कोई आर्मी में देश की सेवा के लिए गया है तो वह फैमिली को साथ लेकर जाता है तो उनका बच्चा 10वीं या 12वीं की क्लास बाहर से ही करता है तो हिमाचल प्रदेश में

07.03.2022/1815/SS-YK/3

शिक्षा को लेकर उसके साथ भेदभाव हो रहा है। उसको 85 परसैंट कोटा जो पी0एम0टी0 में मिलता है या एम0बी0बी0एस0 करने के लिए मिलता है, उससे उसको वंचित रखा जा रहा है। वह भी 2018 में हुआ। वे लोग भी आपके खिलाफ जा रहे हैं, आप उसको भी ठीक कर लीजिए। आज आप देखिए कि प्रदेश में पिछले चार सालों में विकास नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। विकास नाम का कोई मतलब नहीं है। आप यह बताइए कि चार साल में अगर कोई एक बड़ा प्रोजैक्ट आपके चुनाव क्षेत्र में हुआ होगा।

जारी श्रीमती के0एस0

07.03.2020/1820/केएस/एजी/1

श्री राजेन्द्र राणा जारी---

...व्यवधान... अगर आपके चुनाव क्षेत्र में हुआ होगा तो आपको बधाई लेकिन हमारे यहां कोई विकास नहीं हुआ और हिमाचल प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। ...व्यवधान... हम मज़ाक नहीं कर रहे हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो सरकार बैठी है इसका जो नया प्रारूप है, उसको बनाने में हमारा भी योगदान है।

सभापति महोदय, यह जो दो साल का कोविड का समय रहा है, इसमें जो ट्रांस्पोर्टज़ हैं वे चाहे टैक्सी ऑप्रेटर्ज़ हैं या ऑटो ऑप्रेटर्ज़ हैं, उनका दो साल काम नहीं चला। आदमी लोन ले कर टैक्सी डालता है, कोई ऑटो, कोई ट्रक डालता है। उनके ऊपर जो हैवी टैक्सिज़

लगाए गए हैं, जो उनको टैक्स देने थे, उनकी टैक्स देने की स्थिति नहीं है तो सरकार उनको सहयोग क्यों नहीं कर रही है? सरकार को चाहिए कि उनकी मदद करें, उनके टैक्सिज़ को माफ करें या थोड़े-बहुत टैक्सिज़ लगाकर उनका मामला सैटल करे। मुझे लग रहा है कि यह तबका भी आपके खिलाफ जा रहा है।

सभापति महोदय, शनिवार को हमारे सुजानपुर में एक सैनिक सम्मेलन हुआ। उसमें 15 के करीब आर्मी ऑफिसर आए। मैं बड़ा हैरान हुआ, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने बताया कि 2400 दिनों से लगातार जंत्र-मंत्र पर पूर्व सैनिक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया बैन कर दिया है, उनकी कोई बात बाहर नहीं आती है। 2400 दिनों से वे धरने पर बैठे हैं। वन रैंक, वन पैंशन का जिस तरीके से उन्होंने उस दिन व्याख्यान किया कि इसमें हमारे साथ ज्यादती हुई है। जिस तरीके से हमें हमारा हक मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि बाकी के लोग तो ठगे गए। कोई 15 लाख के नाम पर तो कोई 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर ठगे गए परन्तु जो देश की सेवा करते हैं, कम से कम उनको तो छोड़ देना चाहिए था।

07.03.2020/1820/केएस/एजी/2

सभापति महोदय, ज्यादातर बजट, चाहे केन्द्र सरकार है, चाहे प्रदेश सरकार है, अधिकतर बजट सरकार की पब्लिसिटी में लग रहा है। यह पब्लिक मनी है और कई-कई प्रोजैक्टों में तो 70-70 परसेंट बजट पब्लिसिटी पर खर्च किया जा रहा है। यह सरकार विज्ञापनों वाली, पब्लिसिटी वाली सरकार बन गई है। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा किः-

आसमां में देखा तो विमान उड़ रहा था,
सड़क पर देखा तो गरीब चल रहा था,
न दाल, न रोटी, न कोई रोज़गार,
प्रदेश का विकास तो बस विज्ञापनों में बन रहा था।

यह विज्ञापनों वाला जो काम है, मुझे लग रहा है कि विज्ञापनों वाली जो सरकार बन गई है, आप ध्यान दें कि जमीन पर भी काम होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। अब सरकार के जाने का समय आ गया है। अब सरकार वेंटिलेटर पर है और अंतिम सांस ले रही है। इसका संकेत बाई इलैक्शन में लोगों ने दे दिया है। ...व्यवधान... मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुनता हूं। अब आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो कड़वी बातें होती हैं, ये कई बार कड़वी लगती हैं हालांकि असर बहुत करती हैं। आप गलतफहमी में जी रहे हैं और जो सत्ता में होते हैं तो उनको सब हरा-हरा नज़र आता है। यह सरकार तो जाने वाली है और इसका एहसास सत्ता पक्ष के जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, इनके चेहरों पर साफ-साफ झलक रहा है कि ये बिल्कुल जाने वाले हैं। अब देखिए, साढ़े चार साल का अरसा हो गया, इस सरकार को बनाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुजानपुर में एक काम बता दो जो वहां हुआ हो। मैं चार-साढ़े चार साल से बोल रहा हूं कि सुजानपुर में वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय मैंने एक टाउन हॉल बनाने की घोषणा करवाई, शिलान्यास करवाया। उसके लिए 75 लाख रुपए आ गए जो कि चार-साढ़े चार साल से डी.सी. के दफ्तर में पड़े हैं। वहां एक ईंट भी नहीं लगी। मैंने कहा कि अब हर चुनाव क्षेत्र में नए डिविज़न खुल रहे हैं,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

07.03.2022/1825/av/ag/1

श्री राजेन्द्र राणा----जारी

तो सुजानपुर में विद्युत विभाग का सब डिवीजन खोला जाए। इसके अतिरिक्त वहां पर जल शक्ति विभाग का भी एक डिवीजन खोला जाए। हमारे साथी श्री रोहित ठाकुर जी अभी जीत कर आए हैं। वहां जैसे इनके चुनाव क्षेत्र के जुब्बल और कोटखाई नाम से दो हिस्से बन गए हैं तो वहां पर दोनों जगह एस0डी0एम0 के दफ्तर खोल दिए हैं। हमने कहा कि सुजानपुर में भी एस0डी0एम0 का दफ्तर है तो उस तर्ज पर आप टौणी देवी में भी खोलिए। इसके अतिरिक्त, मैं बमसन चुनाव क्षेत्र के लिए बड़े लंबे समय से डिग्री कॉलेज की

डिमाण्ड कर रहा हूं परंतु इस सरकार ने उस दिशा में कुछ नहीं किया। आपने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत बनने वाली स्कीम्ज के लिए हमने डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लिमिट कर दी है। अच्छी बात है, मगर हमने जो सुजानपुर की स्कीम्ज को प्रायोरिटी में डाला है; उनको आपने ठण्डे बस्ते में डाल दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि नाबार्ड को भेज दी हैं मगर पैसा नहीं आ रहा है। इस प्रकार का भेदभाव ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता आपको इसका जवाब देगी। हमारे चबूतरा में पी0एच0सी0 के लिए जमीन दी हुई है, अभी पीछे मेरे एक प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया हुआ है मगर वह काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछली सरकार के समय में शुरू किए गए कार्य आगे नहीं बढ़े हैं। मैं अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि सुजानपुर का होस्पिटल मण्डी और कांगड़ा के लोगों को भी फीड करता है। यह एक सिविल होस्पिटल है और प्रदेश के कई सिविल होस्पिटल्ज में आपने स्पेशलिस्ट और पी0जी0 डॉक्टर्ज लगा रखे हैं। इसलिए आप सिविल होस्पिटल, सुजानपुर में भी पी0जी0 डॉक्टर्ज नियुक्त करने की कृपा करें। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हैल्थ सिस्टम पूरी तरह से रैफरल बन गया है। सुजानपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से टांडा और टांडा से पी0जी0आई0; इस प्रकार से आपका हैल्थ सिस्टम एक रैफरल सिस्टम के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि सुजानपुर की सड़कों की हालत बहुत खराब है। वहां पर नई सड़कों का

07.03.2022/1825/av/ag/2

बनना तो छोड़ो परंतु सड़कों की मुरम्मत तक नहीं हो रही है। इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो बजट पेश किया गया है; यह बहुत ही निराशाजनक है। इस बजट में प्रदेश में विकास कार्यों के संदर्भ में कोई दिशा-निर्देश नहीं है। आप जो यहां पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में 15 साल के लिए पक्की हो गई है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ने पॉवर ऑफ ऑटोर्नी नहीं दे दी है कि यहां 15 वर्षों तक केवल आपकी पार्टी की ही सरकार रहेगी। यह प्रदेश की जनता

का अधिकार है और प्रदेश की जनता इसका सोच-समझकर इस्तेमाल करेगी। यहां पर मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि माह अक्तूबर के बाद आप शिफ्ट होकर विपक्ष में बैठने वाले हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है जिसके बारे में न तो मुझे शक है और न ही आपको होना चाहिए। ...व्यवधान... आप लोग चिंता मत कीजिए अभी तो ट्रेलर आया है, आगे पूरी पिक्चर भी आने वाली है। अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि :-

तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है।
मगर ये आंकड़ें झूठे हैं और यह दावा किताबी है॥

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता और यह बजट निराशाजनक है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

07.03.2022/1825/av/ag/3

श्री बलबीर सिंह, सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल हिस्सा लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल (झण्डुता) : सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2022 को प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इसके पक्ष में बोलूंगा और तथ्यों के साथ बोलूंगा। यहां पर माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा ने कहा कि 'कुछ किताबी हैं, तो कुछ ख्वाबी हैं'; परंतु अच्छी बात यह है कि आज दोपहर के बाद होने वाली चर्चा ज्यादातर बजट पर ही केंद्रित रहीं। यह 51,365 करोड़ रुपये का जो बजट है

टी सी द्वारा जारी

07/03/2022/1830/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री जीत राम कटवाल ... जारी

इसके मुख्य बिन्दु मैंने और आप सब लोगों ने देखें हैं। इसको हम समावेशी बजट का नाम देते हैं और मैं अपने तथ्य से इसको अप्रूव भी करना चाहूंगा। इसकी वार्षिक इकोनोमिक ग्रोथ 8.3 प्रतिशत है। मेरे से पहले विपक्ष के एक मित्र ने कहा कि कृषि का क्या होगा? मैं उनको बताना चाहूंगा कि कृषि की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत है। यह फिगर्ज की बात नहीं, यह तथ्य पर आधारित है। इस बजट में 30,000 नौकरियों का प्रस्ताव है। यह आज ही कह देना कि इनको कैसे भरेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। आप विपक्ष के नाते अपना सहयोग दें। यह बात अलग है कि आपका विरोध, विरोध मात्र होता है। अगर तथ्य की बात हों तो तथ्य अन्य भी निकलते हैं। हाउसिंग के 12,769 यूनिट्स बनाए जाएंगे। राज्यपाल के भाषण में भी नॉन इम्प्लायमेंट की बात की गई और कहा गया कि ये 14 लाख हैं। अभी भी इसकी बात की जा रही है। वे पिछले 4 सालों में ही नहीं हुए या ये सारे कोरोना काल में ही नहीं बढ़े हैं। सरकार इम्प्लायमेंट कितनी दे सकती है, इसका एक तरीका है और वह यह है कि आपके समय में कितनी इम्प्लायमेंट दी गई और वर्तमान सरकार द्वारा कितनी दी जा रही है? यह तुलना की बात है। आप इसके बारे में भली-भांति परिचित हैं। हर साल आर0टी0आई0 में फिगर्ज आती हैं और यहां भी बोली जाती हैं। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लगभग पौने आठ साल का समय इस देश को नेतृत्व देते हो गया है। आप सब लोगों को विदित है कि केन्द्रीय सरकार ने हर मोर्चे पर सफलता पाई है और हर समस्या का समाधान किया है। 'आयुष्मान भारत योजना' विश्व का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के लगभग 10 लाख लोग कवर्ड हैं। 'हिम केयर' योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा किया जाता है और जो इससे वंचित रह गए उनका बीमा सरकार 365 रुपये देकर सुनिश्चित करती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवाने के लिए 143 करोड़ रुपया और 203 करोड़ रुपया हिम केयर योजना में दिया गया। इसी प्रकार से केन्द्र की 'वन रेंक, वन पेंशन' के बारे में भी बात हुई। वर्ष 2013-14

07/03/2022/1830/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

में कांग्रेस सरकार के समय में इसके लिए मात्र 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। लेकिन मोदी सरकार ने 'वन रेंक, वन पेंशन' के माध्यम से मु0 48000 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यही कारण है कि आज 99 प्रतिशत एक्स-सर्विस मैन ऐसे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जवानी दी और व़क्त आने पर कई शहीद भी हुए। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उनके परिवार की देखभाल सुनिश्चित ही नहीं की बल्कि उनका मान-सम्मान यथावत बनाए रखा।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

07-03-2022/1835/NS/AS/1

श्री जीत राम कटवाल .....जारी

यह बोलने वाली बात नहीं। इसके बाद मैं वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के आई0डी0आर0एफ0 की बात करता हूं । जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसमें 80 करोड़ रूपये की लिमिट थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई उन्होंने इसकी लिमिट को 150 करोड़ रूपये कर दिया। पिछले पांच सालों में 779 योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत हुई हैं जिनका अमाउंट 3200 करोड़ रुपये है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में 826 योजनाएं स्वीकृत हुईं जिनमें 3451 करोड़ रूपये विधायक प्राथमिकता की योजनाओं के लिए आ चुके हैं। सम्भवतः जैसे मेरे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा है, मैं उनको अवगत करवाना चाहता हूं कि काम हो रहे हैं और जिन योजनाओं का मैंने उल्लेख किया उस संदर्भ में मैं यही कह सकता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे विपक्ष के मित्र लोन के बारे में बात कर रहे थे। वर्ष 2012 के अंत में जब प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ से गई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई तो उस समय लोन की राशि 28707 करोड़ रूपये थी। जब भाजपा की सरकार दिसम्बर 2017 में आई तब लोन 47,906 करोड़ रुपये था। इसमें आपने पांच वर्षों में 19,199 करोड़ रुपये लोन लिया था। यह ऑथोराइज फिगर्ज़ हैं। यह रिकोर्डिड फिगर्ज़ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले चार वर्षों में 15,294 करोड़ रुपये का लोन लिया है। दो-तीन मौके ऐसे हैं जहां भारत

सरकार से ऑथोराइजेशन ज्यादा थी जोकि कांग्रेस की सरकार के समय में ज्यादा एक्सीड करते थे और ऑथोराइजेशन ज्यादा थी तथा लोन कम लिया गया। इसमें यह कहा जा सकता है कि better finance management, better resources management, better social management or political management और आप डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। यह डबल इंजन सरकार का ही पुण्य प्रताप है कि हम इस स्थिति में हैं। केंद्र सरकार से 90 प्रतिशत स्पैशल केटेगरी स्टेट्स माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश को सुनिश्चित किया था जोकि बहुत पहले चला गया था और यहां तक कि इंडस्ट्रियल पैकेज भी चला गया था जिसको वाजपेयी जी ने दिया था। ये देखने वाली बातें हैं और मात्र बोलने से कुछ नहीं होता। ये सब कुछ रिकोर्ड पर है

07-03-2022/1835/NS/AS/2

और इसको आप भी देख सकते हैं तथा ये हमें भी दिखता है लेकिन हमें वही बोलना चाहिए जो सच और सही हो।

अध्यक्ष महोदय, यह इन्कलूसिव बजट है। इस बजट में ऐसी कोई केटेगरी नहीं है जिसको इस बजट में वृद्धि न दी गई हो। इस बजट में धन और नौकरियों में भी वृद्धि की गई है। पिछले चार वर्षों के हरेक बजट में इसके लिए 70 प्रतिशत से 120 प्रतिशत तक बढौतरी की गई है। आप अपने आपको जन हितैषी बोलते हैं और कर्मचारियों की ओ0पी0एस0 के बारे में बोलते हैं तो आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आज तक के तीनों पे कमीशन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लागू किए हैं। आपने वर्ष 2003 के बाद एन0पी0एस0 को लागू किया है। अगर आप स्वच्छ और सही होते तो उस दिन इसको लागू नहीं करते लेकिन आपने लागू किया। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

07.03.2022/1840/RKS/DC-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

मेरे पास आपका वर्ष 2017 का बजट भाषण है जिसमें आपने कंप्यूटर तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नीति बनाने की घोषणा की थी। यह घोषणा आपकी सरकार के पांचवें बजट में की गई थी और इसका दस्तावेज आपके पास भी उपलब्ध होगा। लेकिन

आप कह रहे हैं कि आप इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। आपने अपने बजट में यह घोषणा की थी लेकिन आपने इस घोषणा को लागू नहीं किया। अब आप लोगों को भ्रमित करने का षडयंत्र कर रहे हैं। हम सभ्य समाज के लोगे हैं और हमें इस तरह किसी को उकसाना नहीं चाहिए। किसी की विचारधारा का विरोध करना अलग बात है परंतु किसी को भ्रमित करना ठीक बात नहीं है। हमने हरेक सैगमेंट को लाभ दिये हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा कहा। आप इस अभिभाषण को ध्यान से पढ़िये। आप कह रहे हैं कि हम इस तरफ आ जाएंगे। यह तो जनता ही तय करेगी कि कौन कहां जाएगा। इसके लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए और हम भी तैयार हैं। अगर हमने अच्छे कार्य किए होंगे तो हम रिपीट करेंगे। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार ने आशा वर्कर्ज, सिलाई इंस्ट्रक्टर्ज, चौकीदार, नम्बरदार, जल रक्षक और अन्य सभी श्रेणियों के मानदेय को बढ़ाया है। जिसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन 850 रुपये मिलती थी उसे अब एक हजार रुपये और जिसे एक हजार रुपये मिलती थी उसे साढ़े ग्यारह सौ रुपये और साढ़े ग्यारह सौ रुपये वालों को 1700 रुपये मिल रही है। आपके समय में इसके लिए 410 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था लेकिन आज 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यह झूठ है। इस प्रदेश में 18,925 आंगवाड़ियां स्थापित हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक हजार नये मॉडल आंगनवाड़ी स्कूल खोलने का एलान किया है। 12,000 आंगनवाडियों को मॉडल आंगनवाड़ी बनाने की बात की जा रही है। इसके लिए पहले 418 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था लेकिन अब 650 करोड़ रुपये बजट प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ियों

07.03.2022/1840/RKS/DC-2

में 38,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। जब मैं सरकारी सेवा में था तो उस समय यह विभाग मेरे पास था। आप हर वर्ष उनसे हड़ताल करवाते हैं लेकिन उनका मानदेय भारतीय जनता पार्टी सरकार ही बढ़ाती है। आज उनका मानदेय नौ हजार रुपये हो गया है। इस मानदेय में 2800 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और इसलिए मैं इस बजट को समावेशी बजट कह रहा हूं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 35 हजार रुपये की आय सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया है। वर्ष 2017 में 3,89,850

पेंशन धारक थे लेकिन हमारी सरकार ने साढ़े सात लाख लोगों को पेंशन देने का प्रावधान किया है। हम कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत लोगों को पेंशन देने के लिए 1300 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको इस बात का सम्मान करना चाहिए। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां बिल्ली नहीं होगी। आप पढ़े-लिखे लोग हैं और आपको सभ्य व्यवहार करना चाहिए। आपकी विचारधार अलग हो सकती है लेकिन लोक कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र के साथ काम किया है। इस बजट के अनुसार लगभग 14 प्रतिशत लोगों को डायरेक्ट कैस बैनिफिट हो रहा है। भारत सरकार द्वारा 'किसान सम्मान योजना' के तहत 6-6 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

07.03.2022/1845/बी.एस./डी0सी0/-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

भारत सरकार द्वारा किसान सम्मान योजना के तहत 6-6 हजार रुपया दिया जाता है। आज आप इनकम टैक्स वालों की सोच रहे हैं, आप उन लोगों की चिंता कीजिए, जिनके लिए हम भी बोलते है कि जो व्यक्ति आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ है, उसका हम ध्यान रखेंगे। यदि कोई इनकम टैक्स वाले हैं, तो वे अपने आपको संभालने में सक्षम है। उनको मेरी और आपकी जरूरत शायद ही पड़ेगी। अगर होगी भी तो केवल ट्रांसफर के लिए होगी। इस बजट में हर वर्ग का लाभ हुआ है। मैं स्कूलों के बारे में बताना चाहता हूं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 100 दिए गए हैं और पिछली साल भी इनकी संख्या 100 ही थी, कॉलेज दिए, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल 68 दिए और ये हर विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में दिए गए हैं। हमारी सरकार ने यह नहीं देखा कि कौन सत्ता पक्ष का है और कौन विपक्ष का है। सद्भाव एवं संभाव से देखने की जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सोच है, उस पर हमने कार्य किया है। हमारे मुख्य मंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं आती है। हमारे बोलने और

सोचने का थोड़ा अन्तर हो सकता है। गृहिणी सुविधा योजना, उज्ज्वला योजना, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। एक मिनीमम प्रोग्राम के अन्तर्गत आपको एक सामान्य आवश्यकता के तौर पर हर घर में चूल्हा उपलब्ध करवाया और तीन सिलेंडर रिफिल की सुविधा हमारी सरकार दे रही है। यह समावेशी नहीं तो क्या है? यह कई लोगों को भाता नहीं है, क्या यह लोगों के हित की बात नहीं है? एक बात बताना चाहता हूं कि जो गरीब परिवार हैं, जिनके दो-तीन परिवार के सदस्य होते हैं वे एक सिलेंडर को तीन-चार महीने तक चला लेते हैं। यह सोचने वाली बात नहीं है, यह आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी होगा। यहां पर एन0टी0टी0 टीचर्ज की बात हुई। एक अच्छी सोच की बात है, मैं वर्ष 2017-18 की तुलना में एक और बात देख रहा था, इस बजट में दिन-रात का अन्तर है। यह बात सही है कि समय बदलता है, परंतु सच्चाई तो सच्चाई है उसे आपको मानना चाहिए।

यहां पर डॉक्टर्ज की बात आई, मैं अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं। जब मैं विधायक बना था, तो वहां पर 24 पोस्टो के अंगेस्ट मात्र छः डॉक्टर्ज थे। अब

07-03-2022/1850/एच.के.-एन.जी./1

श्री जीत राम कटवाल..... जारी

इस राष्ट्रवादी विचार की बात मैं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है और जो उद्देश्य रहता है वह हर जगह का विकास, हर व्यक्ति का विकास, क्षेत्र का विकास, परिवार का विकास, प्रजातांत्रिक तरीके से विकास हो, न कि कांग्रेस की तरह एक ही परिवार के पीछे चले हुए हैं। माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी कह रहे हैं कि पूंछ पकड़ी हुई है। यह पुराने आदमी हैं और इन्हें शब्दों का अच्छा ज्ञान है। मुझे तो अनुभव कम है लेकिन माननीय श्री रमेश चंद ध्वाला जी कह रहे हैं कि गो-दान की तरह ये पूंछ पकड़ कर चले हुए हैं। यह सोचने वाली बातें हैं और मैं यह रिकॉर्ड के ऊपर बोल रहा हूं। हमारा एजेंडा समावेशी विकास का है और वही रहेगा। मैं स्ट्रे एनिमल्स की बात करना चाहता हूं और हम उन्हें गोवंश कहते हैं। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पहले प्रदेश में 6,000 पशुओं की व्यवस्था थी और अब 20,000 पशुओं की व्यवस्था है। मेरे चुनाव क्षेत्र में 300 पशुओं की व्यवस्था है और 300 पशुओं की व्यवस्था के लिए कार्य चल रहा है। आने

वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जून माह तक हमारी सरकार 10,000 पशुओं की अतिरिक्त व्यवस्था करने में अवश्य कामयाब होगी। प्रदेश में गो-अभयारण्यों के केस बन रहे हैं और मेरे क्षेत्र में भी बन रहे हैं। इसे हम सभी को मिलजुल कर समझना होगा तो ठीक रहेगा और यदि विरोध के नाते समझेंगे तो शायद इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। मैं यहां पर जल जीवन मिशन की बात करना चाहता हूं कि यह एक बहुत अच्छा काम हुआ है। आप लोगों की चिंता कईं शब्दों से सही लगती है। हमारे बड़े भाई माननीय श्री राम लाल ठाकुर जी कह रहे थे, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, इनका बोलने का बहुत अनुभव है और मैं इन्हें बहुत ध्यान से सुनता भी हुं, यह कह रहे थे कि नलके तो लग गए लेकिन पानी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं पानी की योजनाएं बनाना हम विधायकों का भी काम है। मैं दावे से कह रहा हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जून माह तक सभी 9 योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी।

07-03-2022/1850/एच.के.-एन.जी./2

मेरे क्षेत्र में अभी तक 70 लाख लीटर पानी की व्यवस्था थी लेकिन इन योजनाओं से अब 1 करोड़ 60 लाख लीटर पानी और जुड़ रहा है। मेरे क्षेत्र में आने वाले 50 वर्षों के लिए पानी की समस्या नहीं होगी। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार काम हो रहे हैं ये भी अपने क्षेत्र में उसी प्रकार काम करवाएं। पानी तो जहां है, जितना है वहीं से उठाना पड़ेगा, चाहे वह कम होगा या ज्यादा। यदि योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सब कार्य हो जाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी और विभाग के अधिकारियों का निजी तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। मेरा आधा चुनाव क्षेत्र पानी की किल्लत से परेशान रहता था वह इन योजनओं के बाद बिलकुल ठीक होने वाला है। इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए लास्ट डेट 30 जून, 2022 है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 15 मई, 2022 से लेकर 15 जून, 2022 तक सभी योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इन योजनाओं के लिए विभाग के अधिकारियों ने मेहनत से काम किया है, माननीय जल शक्ति मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट आवंटित किया है और लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए भी मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र की अन्य गतिविधियों के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में 9 पुल बन रहे हैं। आप लोगों ने कंदरौर के पुल के बारे में सुना होगा जोकि सतलुज नदी पर है और 280 मीटर लम्बा है। इसके अतिरिक्त एक पुल 330 मीटर लम्बा बन रहा है जोकि कंदरौर पुल से 50

मीटर ज्यादा लम्बा है और दूसरा पुल 389 मीटर लम्बा बन रहा है जोकि कंदरौर पुल 109 मीटर ज्यादा लम्बा है। यह दोनों पुल इसी कार्याकाल में शुरू हुए थे और इसी कार्यकाल में पूरे हो जाएंगे। पानी व रोड कनैक्टिविटी के हम साक्षी ही नहीं बने हैं बल्की अपने लोगों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने में भी सक्षम होंगे। मैं तो यह मानता हूं कि विकास हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया वाइंडअप कर दीजिए।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति जी, सिर्फ तीन-चार मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

07.03.2022/1845/बी.एस./डी0सी0/-2

वहां पर 27 डॉक्टर्ज हैं। डैंटल डॉक्टर्ज अलग से हैं, आंख के अलग हैं और अब फ़िज़ियोथेरेपिस्ट भी आने लगे हैं। यह सही है कि विभाग में स्पेशलिस्ट की कमी है। हमारे मैडिकल कॉलेज खुले हैं, उन्हे चलाना भी एक जिम्मेवारी है। मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के कुछ रूल्ज होते हैं और मैंडिकल कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात होती है। यहां बात आई कि यहां पर मैंडिकल कॉलेज होते, तो हमारे बच्चे यूक्रेन नहीं जाते। जहां जितनी मैरिट की बात है, वहां बच्चों को आना चाहिए और अगर फिर भी बात नहीं बनती तो बच्चे विदेशों में जाते हैं। वहां सब नहीं जा सकते जिनके पास 30-35-50 लाख रुपया कैश होगा और इच्छा शक्ति होगी कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, चाहे उसे यूक्रेन भेजना हो, चीन में भेजना हो या किरगीस्तान हो। यह भी एक अच्छी बात है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। इसके लिए तारीफ करना तो बनता है।

यहां पर बिजली की बात आई, 60 यूनिट तक फ्री कर दी है और 125 यूनिट्स तक एक रुपए प्रति यूनिट कर दिया है और एग्रीकल्चर वाले जो ट्यूबवेल हैं, हमारे प्लेन वाले एरियाज हैं, एग्रीकल्चर की स्कीमें चलती हैं, उन्हें 50 पैसे से कम करके 30 पैसे कर दिया है। यह भी एक अच्छी बात है उसे भी हमें एकनॉलेज करना चाहिए। इन कार्यों के लिए सरकार का होंसला बढ़ाना चाहिए और काम की प्रशंसा भी करनी चाहिए। आपने भी उन्ही

व्यक्तियों से वोट लेने हैं और हमने भी वहीं जा करके वोट लेने हैं परंतु उन्हें आप जा करके कहेंगे कि आपके साथ बहुत बुरा किया कि बिजली के दाम कम कर दिए, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारा जो सबका साथ, सबका विकास

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

07.02.2022/1855/JS/HK/1

श्री जीत राम कटवालः---**जारी**-----

अध्यक्ष जी, सिर्फ तीन-चार मिनट में खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही ज्यूडिशियल कोर्ट खुला, एक्सिअन्ज़ के दफ्तर गए, फायर स्टेशन गए और भारत सरकार की कृपा से आर्मी की सी.एस.डी.गई तो विकास की एक नई रूप-रेखा के अंतर्गत काम हुआ। उसके लिए मैं प्रदेश व केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। ये कोई घड़ी-घड़ाई बातें नहीं हैं। सारे चुनाव क्षेत्रों में काम हुआ परन्तु बोलने और सुनने में हमें थोड़ा फर्क रहता है। उसको अगर हम करैक्ट कर लें तो एक अच्छी परिपाटी होगी। काम करने की कला और भ्रम फैलाकर कोई फायदा नहीं होता। आपकी सरकार ने वर्ष 2003 में एन.पी.एस. लागू की। आप लोग बोलते हैं कि अब हम यह कर देंगे और आपने वर्ष 2017 में बोला था कि हम एक महीने के अंदर-अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों,कम्प्यूटर के अंदर जो भी आउटसोर्स हैं, उनके लिए पॉलिसी लाएंगे, यह मेरे पास डॉकुमेंट है। आप इसके पेज नं0-77 को पढ़ लीजिएगा। ये चीजें भ्रम फैलाना नहीं तो और क्या है? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी मैं तारीफ तो करुंगा ही और एक अच्छे तरीके से जो काम किया, उसके लिए मैं सरकार का आभार भी व्यक्त करता हूं।

(अध्यक्ष महोदय पदीसीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, अभिवादन। जय हिंद, धन्यवाद।

अध्यक्षः अगर माननीय सदस्यों की अनुमति हो तो सदन को कल 11.00 बजे तक स्थगित किया जाए?

अब इस सदन की कार्यवाही कल दिनांक 08.03.2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 07 मार्च, 2022 **सचिव।**